राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

नहीं रुकेगी सलमान की फिल्म 'भारत' की रिलीज
>>6

दैनिक जागरण

वर्ष 2 अंक 357

मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, मंगलवार, 4 जून 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

सरोकार

पर्यावरणीय चुनौती को मात दे रहीं 'सुपर वूमन' रागिनी

नई दिल्ली : देशभर की 40 लैंडफिल साइट्स पर कूड़े के पहाड़ों को समतल करके रागिनी जैन पर्यावरण प्रहरियों के

बीच 'सुपर वूमन' बन चुकी हैं। उन्नत तकनीकी और अटूट जज्बे के बूते वह पर्यावरणीय चुनौतियों का कारगर समाधान प्रस्तुत कर रही हैं। (पेज-13)

जागरण विशेष

चांद पर दोबारा महकेगी अमरोहा की 'खुशबू'

अमरोहा : उत्तर प्रदेश की 'खुशबू' एक बार फिर चांद पर महकेगी। भारतीय अंतरिक्ष

अनुसंधान संगठन (इसरो) 9-16 जुलाई को चंद्रयान-2 लॉन्च करने जा रहा है। इसके चांद की सतह पर छह सितंबर को उतरने की संभावना है। अमरोहा के सिकंदर मिर्जा की बिटिया खुशबू मिर्जा चंद्रयान-1 का भी हिस्सा रही हैं। (पेज-13)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

डोभाल फिर बने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ओहदा भी बढ़ा

नई दिल्ली : पिछले पांच साल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा को नया आयाम देने में अहम भूमिका निभाने वाले अजीत डोभाल अगले पांच वर्षों तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने रहेंगे। इसके साथ ही उनका ओहदा भी बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि पहले उनका दर्जा राज्यमंत्री का था। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने डोभाल को एनएसए बनाए रखने का फैसला लिया।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

ब्रेक्जिट पर घमासान के बीच ब्रिटेन पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप

लंदन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को तीन दिनी दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे। उनके साथ पत्नी मेलनिया भी है। ट्रंप का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब ब्रेक्जिट को लेकर ब्रिटेन में सियासी घमासान मचा हुआ है। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरी बार ब्रिटेन आए डोनाल्ड ट्रंप इस दौरे में प्रधानमंत्री टेरीजा मे के साथ जलवायु परिवर्तन और चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी हुआवे समेत कई अहम मसलों पर चर्चा करेंगे।

स्पोर्ट्स ▶ पृष्ठ 12

टीम इंडिया की प्रेस कांफ्रेंस में नाराज हुए पत्रकार

साउथैंप्टन : विश्व कप खेलने के लिए इंग्लैंड पहुंची टीम इंडिया को भारतीय पत्रकारों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। दरअसल, अभ्यास के बाद टीम इंडिया को प्रेस कांफ्रेंस करनी थी, जिसमें नियमित खिलाड़ी के बजाय नेट बॉलर आवेश खान और दीपक चाहर भेज दिया गया। भारतीय पत्रकारों को यह रास नहीं आया और प्रेस कांफ्रेंस नहीं हो सकी।

क्रिकेट महाकुंभ
अफगानिस्तान vs श्रीलंका
दोपहर 3:00 बजे से
स्थान : कार्डिफ
स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

एयरबस विमान खरीद में हुआ था 1000 करोड़ से अधिक का घोटाला

नीलू रंजन, नई दिल्ली

संप्रग सरकार के दौरान हुई एयरबस विमान खरीद में 1000 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला हुआ था। इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) के फैसले को ही बदल दिया गया था। घोटाले के सारे सुबूतों से लैस प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल को पूछताछ के लिए समन भेजा है। पटेल से गुरुवार को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पूछताछ होगी।

ईडी के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार, 2006 में सीसीएस ने एयरबस से 43 विमानों की खरीद को हरी झंडी दी थी। समिति ने यह भी तय कर दिया था कि किस कीमत पर ये विमान खरीदे जाएंगे। इसके साथ यह शर्त भी जोड़ी गई थी कि एयरबस को 17.5 करोड़ डॉलर (लगभग 1000 करोड़ रुपये) की लागत से भारत में ट्रेनिंग, मेंटिनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग की सुविधा विकसित करनी होगी। ताकि पायलटों की ट्रेनिंग से लेकर विमानों के रखरखाव पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

सीसीएस की हरी झंडी मिलते ही एयर इंडिया ने एयरबस से 43 विमान खरीदने का फैसला किया। इसके लिए एयरबस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। समझौते में विमान की कीमत तो वही रखी गई, लेकिन ट्रेनिंग, मेंटिनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की सुविधा विकसित करने के लिए भारत में 1000 करोड़ रुपये के निवेश की शर्त को हटा दिया। इस तरह से एयरबस को सीधे-सीधे 1000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सीसीएस की शर्त हटाने के साथ ही समझौते में प्रावधान-16 के तहत एक नई शर्त जोड़ दी गई। इसके अनुसार, नए विमान उड़ाने और अन्य ट्रेनिंग के लिए एयर इंडिया को अपने पायलट और स्टाफ को फ्रांस स्थित ब्लॉनैक, जर्मनी के हैमबर्ग, अमेरिका के मियामी या फिर चीन के बीजिंग स्थित एयरबस के ट्रेनिंग सेंटर में भेजना था। इसमें यह भी जोड़ा गया कि ट्रेनिंग के लिए अपने स्टॉफ के आने-जाने से लेकर रहने, खाने-पीने तक सारा खर्च एयर इंडिया उठाएगा। साथ ही ट्रेनिंग के दौरान एयरबस के प्रशिक्षकों, ट्रेनिंग में प्रयुक्त होने वाले साजो-सामान समेत सारा खर्च एयर इंडिया पर डाल दिया गया। इस तरह, सीसीएस की शर्त हटने से जहां एयरबस भारत में 1000 करोड़ रुपये का निवेश करने से बच गया। वहीं, एयर इंडिया पर अपने पायलटों व स्टाफ की विदेश में ट्रेनिंग का अतिरिक्त बोझ भी डाल दिया गया।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीसीएस के फैसले का उल्लंघन करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन एयरबस से विमान खरीद में ऐसा हुआ। आश्चर्य की बात है कि संप्रग सरकार में इसे न सिर्फ आसानी से होने दिया गया, बल्कि किसी ने सवाल भी नहीं उठाया। उस वक्त के उड्डयन सचिव और अन्य अधिकारियों से पूछताछ में इस बात का कोई जवाब सामने नहीं आया कि सीसीएस की शर्त को समझौते से हटाकर नई शर्त क्यों डाली गई। अब तत्कालीन उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल को इसका जवाब देना होगा। साथ ही यह भी बताना होगा कि उड्डयन मंत्री रहते हुए उन्होंने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया।

संप्रग सरकार में हुई गड़बड़ी की खुलने लगीं पर्तें

- सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति के फैसले की उड़ाई गई धज्जियां
- तत्कालीन उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल गुरुवार को ईडी के सामने देंगे जवाब

एयर इंडिया में इस्तेमाल होते हैं एयरबस के विमान। फाइल

ब्याज दर घटने की उम्मीद में सेंसेक्स हुआ चालीस हजारी

मुंबई : देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को

रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुए। इंट्राडे ट्रेड में सेंसेक्स ने 40,308.90 का और निफ्टी ने 12,103.05 का रिकॉर्ड ऊपरी स्तर भी छुआ। जीडीपी के कमजोर आंकड़े को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य नीतिगत ब्याज दर में कटौती की उम्मीद में निवेशकों ने बाजार में चौतरफा खरीदारी की। बीएसई का सेंसेक्स 553.42 अंकों की तेजी के साथ 40,267.62 के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 165.75 अंकों की तेजी के साथ रिकॉर्ड 12,088.55 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पहली बार 40,000 के ऊपर बंद हुआ। (पेज-10)

टूट के कगार पर सपा-बसपा गठबंधन

दो टूक ▶ बसपा आगे के चुनावों में किसी पार्टी का सहयोग नहीं लेगी : मायावती

उप्र विधानसभा उपचुनावों में सभी 11 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी बसपा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा चुनाव में एकतरफा बाजी मारने की मंशा से उत्तर प्रदेश में जातिगत गोलबंदी के लिए गठित सपा-बसपा और रालोद के गठबंधन पर संकट के बादल छाने लगे हैं। बसपा प्रमुख मायावती के तल्ख बयानों के बाद गठबंधन टूट के कगार पर पहुंच गया है। गठबंधन के बिखरने का एलान राज्य में उपचुनावों की घोषणा के साथ हो सकता है। हालांकि समाचार एजेंसी प्रेट्र के मुताबिक, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में कहा, सामाजिक न्याय के लिए सपा-बसपा मिलकर लड़ती रहेंगी, जबकि सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का कहना था कि उनकी पार्टी बसपा के आधिकारिक रुख का इंतजार करेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लेगी।

मायावती सोमवार को यहां उत्तर प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ लोकसभा चुनाव की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने गठबंधन के प्रदर्शन को बेहद खराब करार देते हुए कहा, लोकसभा चुनाव के साथ अन्य प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में भी यह गठजोड़ नाकाम साबित हुआ है। बसपा आगे के चुनावों में किसी पार्टी का सहयोग नहीं लेगी, बल्कि अपने संगठन के बल पर चुनाव में उतरेगी। अब उसका पूरा जोर पार्टी संगठन को मजबूत बनाने पर होगा। मायावती ने पदाधिकारियों व निर्वाचित प्रतिनिधियों से कहा, वे पार्टी संगठन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को शामिल करने पर जोर दें ताकि आगामी चुनावों में पार्टी का आधार सुदृढ़ हो सके। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 11 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मायावती ने कहा, आमतौर पर बसपा उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेती, लेकिन इस बार वह उपचुनावों में प्रत्याशी उतारेगी। राज्य के 11 विधायक चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए हैं। इनमें से नौ भाजपा के और एक-एक सपा और बसपा के हैं।

मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, वे गठबंधन के भरोसे जीत की उम्मीद न करें, संगठन की मजबूती पर ध्यान दें और पार्टी के बूते उपचुनावों को जीतने की रणनीति तैयार करें। बसपा प्रमुख ने दो टूक कहा कि हमारे 10 सांसदों की जीत पार्टी के परंपरागत वोट बैंक के भरोसे हुई है। गठबंधन के सहयोगी दल सपा पर तोहमत लगाते हुए उन्होंने कहा कि वह अपने वोट बैंक (यादव) को हमारे प्रत्याशियों के पक्ष में ट्रांसफर कराने में विफल रही।

लोकसभा चुनाव से पहले सपा-बसपा और रालोद के बीच हुए गठबंधन को राज्य की 50 सीटें जीतने का अनुमान था। यह अनुमान विशुद्ध जातिगत समीकरणों के आधार पर लगाया गया था। लेकिन चुनाव में सपा को पांच सीटों पर संतोष करना पड़ा। पार्टी प्रमुख अखिलेश की पत्नी डिंपल, भाई धर्मेंद्र व अक्षय प्रताप चुनाव हार गए। वहीं, बसपा जो 2014 के लोकसभा चुनाव में शून्य पर पहुंच गई थी, उसे 10 सीटें मिल गईं। चुनाव नतीजों के बाद दोनों दलों के बीच वोट ट्रांसफर नहीं होने की शिकायतें तो मिल रही थीं, लेकिन इतनी जल्दी खटास इस हद तक बढ़ जाएगी, इसका अनुमान किसी को नहीं था।

- समीक्षा बैठक में गठबंधन के प्रदर्शन को बताया बेहद खराब
- कहा, अपने यादव वोट बैंक को हमारे पक्ष में ट्रांसफर नहीं करा सकी सपा

बसपा प्रमुख मायावती (फाइल फोटो)

इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर इफ्तार पार्टी नहीं देगी कांग्रेस

नई दिल्ली, प्रेट्र: लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस इस बार

नदीम जावेद। फाइल

राष्ट्रीय स्तर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं करेगी। हालांकि राज्य इकाई अपने स्तर पर इस तरह का आयोजन करेंगी। कांग्रेस के अल्पसंख्यक सेल के चेयरमैन नदीम जावेद ने इसकी पुष्टि की है। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने पिछले सप्ताह ही इफ्तार पार्टी दी थी। एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने कहा कि पिछले साल एक आलीशान होटल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इफ्तार पार्टी दी थी, लेकिन इस बार उन्होंने कोई पार्टी नहीं दी। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद राहुल द्वारा दी जाने वाली यह पहली इफ्तार पार्टी थी। सूत्रों के मुताबिक इफ्तार पार्टी नहीं दिए जाने के पीछे लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन भी एक कारण है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से हिंदी की अनिवार्यता खत्म

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने त्रिभाषा फार्मूले में किया बदलाव
- गैर-हिंदी भाषी राज्यों से उठ रहे विरोध को देख लिया गया फैसला

सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में बदलाव कर दिया है। अब हिंदी पढ़ने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। संशोधित मसौदे में त्रिभाषा फार्मूले के तहत छात्र अब कोई भी तीन भाषा पढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि इनमें एक साहित्यिक भाषा जरूरी होगी। पुराने मसौदे में हिंदी, अंग्रेजी के साथ कोई एक स्थानीय भाषा पढ़ने का प्रावधान था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में यह बदलाव सोमवार को गैर-हिंदी भाषी प्रदेशों, खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों, से उठ रहे विरोध के सुर को देखते हुए किया गया है। इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी, जहां द्रमुक समेत कई राजनीतिक दलों ने इसे लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। द्रमुक के अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। हालांकि, सरकार ने कहा था कि किसी पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। यह अभी एक शुरुआती मसौदा है। सभी पक्षों से सलाह के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा।

संशोधित शिक्षा नीति के मसौदे में त्रिभाषा फार्मूले को लचीला कर दिया गया है। अब इनमें किसी भी भाषा का जिक्र नहीं है। छात्रों को कोई भी तीन भाषा चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के राज्यों में पहले से दो भाषा पढ़ाई जा रही है। इनमें एक स्थानीय और दूसरी अंग्रेजी है। हालांकि संशोधित शिक्षा नीति के मसौदे में यह साफ कहा गया है कि स्कूली छात्रों को तीन भाषा पढ़नी होगी।

नई शिक्षा नीति के मसौदे को लेकर यह विवाद तब खड़ा हुआ है, जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे 31 मई को जारी कर लोगों से सुझाव मांगे। इसके तहत कोई भी व्यक्ति 30 जून तक सुझाव दे सकता है। शिक्षा नीति के मसौदे पर मिल रहे सुझावों पर प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय और नीति तैयार करने वाली कमेटी पैनी नजर रख रही है। (पेज-3 भी देखें)

बदलाव का संगीतकार एआर रहमान ने किया स्वागत

नई दिल्ली, एएनआइ : प्रख्यात संगीतकार एआर रहमान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में हिंदी की अनिवार्यता खत्म किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, इस बदलाव से छात्र पसंद की भाषा पढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। रहमान ने ट्वीट किया, 'तमिलनाडु में हिंदी अनिवार्य नहीं है। मसौदा नीति को बदल दिया गया है। बेहतर समाधान।'

वायुसेना का एंटोनोव एएन-32 हुआ लापता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- असम के जोरहाट से अरुणाचल प्रदेश के लिए भरी थी उड़ान, करीब आधे घंटे बाद टूटा संपर्क
- चालक दल के 13 सदस्य हैं सवार, खोज में लगाए गए सुखोई-30 व सी-130 विमान

वायुसेना का परिवहन विमान है एएन-32। फाइल

भारतीय वायुसेना का एंटोनोव एएन-32 विमान असम के जोरहाट से सोमवार दोपहर उड़ान के बाद लापता हो गया। विमान में विंग कमांडर, चार फ्लाइट लेफ्टिनेंट, एक स्क्वाड्रन लीडर और सात एयर मैन सवार हैं, लेकिन उनके बारे में भी कोई खबर नहीं है। विमान की खोज के लिए वायुसेना, सेना और सरकारी तंत्र द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया गया है। वायुसेना प्रमुख के स्वीडन यात्रा होने के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया से बात की। सिंह ने कहा, वायुसेना के हेलीकॉप्टर विमान खोजने की कोशिश कर रहे हैं।

वायुसेना के मुताबिक, विमान ने जोरहाट से दोपहर 12.25 बजे अरुणाचल प्रदेश के मेंचुका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के लिए उड़ान भरी थी, जो चीन सीमा से 35 किमी दूर है। विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी बार संपर्क दोपहर एक बजे हुआ था। विमान के तय समय पर मेंचुका नहीं पंहुचने पर उसकी तलाश शुरू की गई। सुखोई-30, सी-130 विमानों को खोज अभियान में लगाया गया। सेना, आइटीबीपी, विभिन्न सरकारी व नागरिक एजेंसियों की मदद भी ली गई है। वायुसेना ने ट्वीट कर कहा, संभावित दुर्घटनास्थल की कुछ रिपोर्टें मिली हैं, लेकिन विमान का मलबा अभी तक नहीं दिखा है।

10 साल पहले भी इसी जगह हुआ था लापता : नौ जून, 2009 को एक विमान इसी जगह लापता हुआ था। उसमें भी 13 ही लोग सवार थे। विमान का मलबा नियंत्रण रेखा से 60 किमी दूर रिंची पहाड़ी पर मिला था।

2016 में भी हुआ था लापता : 2016 में भी चेन्नई से अंडमान-निकोबार द्वीप समूह जा रहा एएन-32 विमान बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उड़ते हुए लापता हो गया था। विमान में 29 लोग सवार थे।

परिवहन विमान है एएन-32 : एएन-32 दो इंजन का परिवहन विमान है। वायुसेना इसे 1984 से इस्तेमाल कर रही है। वायुसेना में 100 एएन-32 विमान है, जिनका अपग्रेडेशन किया जा रहा है।

बड़े काम का है एएन-32 विमान पेज>>7

तत्काल तीन तलाक पर आएगा नया बिल : प्रसाद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- फिर संभाला कानून मंत्रालय का कार्यभार, बोले-जजों की नियुक्ति में कानून मंत्रालय सिर्फ पोस्ट ऑफिस नहीं, बल्कि पक्षकार

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि तत्काल तीन तलाक पर नया विधेयक लाया जाएगा। पुराना विधेयक लोकसभा भंग होने के बाद समाप्त हो गया था। फिलहाल तत्काल तीन तलाक पर रोक लगाने का अध्यादेश लागू है, लेकिन संसद सत्र आने वाला है ऐसे में अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए संसद से विधेयक पास कराना जरूरी है। न्यायाधीशों की नियुक्ति मामले में उन्होंने कहा कि कानून मंत्रालय और कानून मंत्री महज पोस्ट ऑफिस नहीं हैं, बल्कि पक्षकार हैं।

एक बार फिर कानून मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, पक्षकार की तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से परामर्श के जरिये जजों की नियुक्ति में तेजी लाई जाएगी। उनका मंत्रालय महज पोस्ट ऑफिस नहीं है बल्कि एक पक्ष है और परामर्श के जरिये नियुक्तियों को गति दी जाएगी, के काफी मायने हैं। उन्होंने कहा, वह कोलेजियम का पूरा सम्मान करते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की कई सिफारिशें सरकार ने कोलेजियम को पुनर्विचार के लिए लौटाई थीं। अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए रविशंकर ने अधीनस्थ अदालतों में जजों की नियुक्ति के संबंध में ऑल इंडिया ज्यूडीशियल सर्विस के लिए सभी पक्षकारों से विचार-विमर्श में तेजी लाने की भी बात कही। उन्होंने कहा, वह चाहते हैं कि न्यायपालिका में अच्छे लोग आएं और चयन मेरिट के आधार पर हो। समाज का वंचित तबका भी इसमें शामिल हो। प्रसाद ने कहा, त्वरित न्याय, सबकी न्याय तक पहुंच और न्यायपालिका में ढांचागत संसाधन बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता में है। उनकी सरकार ने सबसे ज्यादा संख्या में जजों की नियुक्ति की है।

रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया। प्रेट्र

उन्होंने कानूनी शिक्षा और कानून में शोध को बढ़ावा देने के साथ ही वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा और कल्याण की योजनाएं लाने पर भी विचार करने की बात कही। मध्यस्थता से विवादों के निपटारे और भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बनाने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रसाद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान अनुच्छेद 370 और 35ए के बारे में पूछे गए सवाल को यह कहते हुए टाल दिया कि यह मुद्दा गृह मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अयोध्या में राम मंदिर के बारे में सरकार के नजरिये पर पूछे गए सवाल पर कहा, वह पहले भी कहते आए हैं कि इस मामले में कानूनी मुद्दे का जल्द निपटारा होना चाहिए।

मौसम की मार

हरियाणा के सिरसा जिले में 49 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तापमान, दिल्ली में गर्मी से मिली कुछ राहत, आज बारिश होने की संभावना

आसमान से बरसी आग, दुनिया के 10 सबसे गर्म शहर भारत में

जेएनएन, नई दिल्ली

भारत में गर्मी विकराल रूप ले चुकी है। कई शहरों का अधिकतम तापमान 50 डिग्री के पास पहुंच चुका है। अमेरिका की मौसम निगरानी वेबसाइट अल डोराडो की माने तो 24 घंटों के दौरान (रविवार शाम 5.00 बजे से सोमवार शाम 5.00 बजे तक) दुनिया के 15 सबसे गर्म शहरों में 10 भारत के रहे। शेष पाकिस्तान के। झुलसती गर्मी का आलम यह है कि देश के आधे से अधिक हिस्से में लू चल रही है। हरियाणा में सोमवार को सिरसा जिले के केहरवाला गांव में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पंजाब के बठिंडा में अधिकतम तापमान 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू का अधिकतम तापमान 41.1 रहा। महाराष्ट्र का नागपुर 47 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में जबरदस्त लू चल रही है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। फूड डिलीवरी एप जोमैटो ने अपने ग्राहकों से निवेदन किया है कि जब उनका स्टाफ खाने की डिलीवरी लेकर पहुंचे तो उसे पीने के लिए ठंडा पानी जरूर पेश करें।

हरियाणा में कार सवार को पानी पिलाता युवक। एएफपी

बढ़ रही मरने वालों की संख्या : देश भर में प्रचंड गर्मी से मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो तेलंगाना में गत तीन हफ्ते में गर्मी से 17 की मौत हो चुकी है। राजस्थान के बीकानेर और हरियाणा के गुरुग्राम में लू के चलते दो की मौत हो गई। पंजाब में गरमी के चलते एक की मौत हो गई।

दिल्ली में आज राहत के आसार : देश की राजधानी भी तप रही है। हालांकि सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 42.4 दर्ज किया गया। रविवार को यह 45 से भी ज्यादा था। मौसम विभाग की मानें तो 4-6 जून के बीच दिल्ली-एनसीआर में बारिश हो सकती है।

प्री मानसून सूखा : भारत की मौसम विज्ञानी स्काइमेटवेदर वेबसाइट की मानें तो भारत में प्री मानसून का सीजन 31 मई को खत्म हो गया है। पिछले 65 सालों के दौरान यह सबसे कम बारिश वाला प्री मानसून रहा। इस दौरान 99 मिमी ही बारिश हुई, जबकि औसतन बारिश 131.5 मिमी होती है।

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी : मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी कर रखा है। रेड अलर्ट के दौरान दिन में बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। लू के चलते मौसम विभाग चार श्रेणियों में अलर्ट जारी करता है। जिसमें रेड, आरेंज, येलो और ग्रीन अलर्ट शामिल है। रेड अलर्ट तब जारी किया जाता है जब सामान्य तापमान अधिकतम से चार डिग्री से अधिक हो। सरकार ने गर्मी से बचने के लिए कई तरह के निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान के चूरू में तापमान से पिघल रही सड़कों को बचाने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। चूरू को थार रेगिस्तान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है।

ओडिशा में आंधी का कहर आठ की मौत पेज>>7

सबसे गर्म 15 शहर

चूरू, राजस्थान	50.3
जैकबाबाद, पाकिस्तान	50.1
श्रीगंगानगर, राजस्थान	48.8
सिबी, पाकिस्तान	48.5
बीकानेर, राजस्थान	48.4
फलौदी, राजस्थान	48.2
रोहरी, पाकिस्तान	48.1
जैसलमेर, राजस्थान	47.8
नौंगांव, मध्य प्रदेश	47.7
खानपुर, पाकिस्तान	47.6
नारनौल, हरियाणा	47.6
बहावल नगर, पाकिस्तान	47.5
कोटा एयरोड्रम, राजस्थान	47.5
पिलानी, राजस्थान	47.5
बाड़मेर, राजस्थान	47.2

(रविवार शाम 5 से सोमवार शाम 5 बजे तक के आंकड़े, स्रोत-मौसम वेबसाइट अल डोराडो)

दिल्ली में मेट्रो-बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर का तोहफा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- सीएम केजरीवाल ने दो से तीन माह में योजना पर अमल का किया दावा
- एनसीआर की महिलाओं को लाभ देने का फैसला जनता के सुझाव पर

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो और बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर कराने का बड़ा एलान किया है। उन्होंने दावा किया कि दो से तीन माह के भीतर योजना को धरातल पर उतार दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम को प्रस्ताव बनाकर देने के लिए कहा गया है ताकि, योजना पर आने वाले खर्च और इसके क्रियान्वयन की तस्वीर साफ हो सके। हालांकि, प्राथमिक स्तर पर इस योजना को लागू करने में इस वित्तीय वर्ष में सात से आठ सौ करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान लगाया गया है।

केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में पत्रकार वार्ता कर योजना का एलान किया। उन्होंने कहा, सरकार ने दो बड़े निर्णय लिए हैं। पहला, एक लाख 40 हजार की जगह दिल्ली भर में 2 लाख 80 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दूसरा, महिलाओं के लिए मेट्रो और सरकारी बसों में यात्रा मुफ्त होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माना गया है। इसी का ध्यान रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर सभी डीटीसी बसों, क्लस्टर बसों और मेट्रो में महिलाओं का सफर मुफ्त किया जाएगा, ताकि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकें। योजना दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए होगी, हालांकि सक्षम महिलाएं स्वेच्छा से इसका लाभ छोड़ भी सकेंगी। सीएम ने बताया कि अधिकारियों को विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। योजना का लाभ एनसीआर की महिलाओं को मिलना चाहिए या नहीं, जनता के सुझाव के आधार पर ही इस पर फैसला लिया जाएगा। (पेज-2 भी देखें)

6612 मेगावाट बिजली की मांग दिल्ली में सोमवार को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे दर्ज की गई। इसके साथ ही बिजली कटौती की समस्या भी बढ़ रही है। इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 4 जून 2019

महिलाओं की सुरक्षा आप के लिए सर्वोपरि : केजरीवाल

फैसला ▶ मेट्रो और बस में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा वाले एलान को विधानसभा चुनाव से जोड़ने को सीएम ने किया खारिज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मेट्रो और बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के एलान के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है। इसके लिए उनकी सरकार हर संभव कदम उठाएगी। लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार के बाद माना जा रहा था कि केजरीवाल सरकार मतदाताओं में फिर से पैठ बनाने के लिए कुछ बड़े फैसले ले सकती है। हालांकि पत्रकार वार्ता में विधानसभा चुनाव को लेकर यह फैसला लिए जाने की बात को केजरीवाल ने सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि अच्छे कार्य के लिए कोई समय नहीं होता है। उन्होंने कहा कि किसी खास वजह से नहीं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह योजना लागू की जा रही है। एक आम आदमी की बेटी, बहन, पत्नी, मां सुबह नौकरी, स्कूल, कॉलेज इत्यादि के लिए घर से बाहर निकलती है, तो वह जब तक लौट नहीं आती परिवार के लोगों चिंतित रहते हैं। दिल्ली सरकार लोगों की इस चिंता को दूर करना चाहती है इसलिए दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं मुफ्त और सुरक्षित सफर कर सकें।

दो साल में 55 फीसद बढ़ा मेट्रो ट्रैक : मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 से 2019 के बीच मेट्रो ट्रैक में करीब 55 फीसद का इजाफा हुआ है। वर्ष 2017 में 212 किमी मेट्रो लाइन थी, जो बढ़कर 2019 में 327 किमी हो गई। ऐसे में यात्री भी बढ़ने चाहिए थे। लेकिन किराया बढ़ने की वजह से मेट्रो में यात्रियों की संख्या कम हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर यह योजना अगस्त-सितंबर से लागू हो जाती है, तो इस वित्त वर्ष में दिल्ली सरकार को करीब 700 से 800 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।

योजना सफल हुई तो गरीबों और बुजुर्गों को भी मिलेगा लाभ : मुख्यमंत्री ने फिलहाल इस योजना को दिल्ली की महिलाओं के लिहाज से घोषित किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जनता से सुझाव मांगे गए हैं। यदि जनता दिल्ली-एनसीआर की महिलाओं को भी लाभ दिए जाने के पक्ष में होगी तो विचार किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि योजना सफल हो जाती है तो बाद में इसे महिलाओं के साथ गरीब पुरुषों के लिए भी लागू करने पर विचार किया जाएगा।

दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों से बात करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। साथ में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत। जागरण

दिल्ली में अब लगेंगे दो लाख 80 हजार सीसीटीवी कैमरे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार ने दिल्ली भर में लगने वाले सीसीटीवी कैमरों की संख्या एक लाख 40 हजार से बढ़ाकर अब दो लाख 80 हजार कर दी है। इस फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पिछले दो-ढाई साल में पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोशिश चल रही है। इसमें डेढ़ लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का टेंडर हो चुका है। करीब 70 हजार सीसीटीवी कैमरों के लिए सर्वे पूरा हो चुका है। अब आठ जून से ये कैमरे लगने शुरू हो जाएंगे और दिसंबर तक तक यह काम पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा एक लाख 40 हजार कैमरे और लगाने का प्रस्ताव भी इसी महीने पास हो जाएगा। इस तरह पूरी दिल्ली में लगभग दो लाख 80 हजार कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी स्कूलों के अंदर अलग से डेढ़ लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। यह काम नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है।

3000 नई बसें उतारने की है तैयारी : मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 10 से 12 महीने के अंदर 3000 नई बसें दिल्ली की सड़कों पर आ जाएंगी। इनमें भी सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। पहली खेप इसी माह आ जाएगी, जिसमें 25 से 30 बसें आएंगी। डीटीसी की सभी बसों में मार्शल तैनात हैं। अब कलस्टर बसों में भी मॉर्शल तैनात कर दिए जाएंगे। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बसों में सफर कर रही बहुत सी महिलाओं को यह पता भी नहीं होता कि उनकी सुरक्षा के लिए बस में मॉर्शल मौजूद हैं। इसलिए अब बसों में पोस्टर भी लगा दिए जाएंगे कि इस बस में मॉर्शल मौजूद हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइए।

छात्रों और बुजुर्गों को भी मिले मुफ्त यात्रा की सुविधा : कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र कोचर ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए तो मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा कर दी है, लेकिन वास्तव में इसकी जरूरत छात्रों और बुर्जुगों को अधिक है। उन्हें भी योजना का लाभ मिलना चाहिए अन्यथा केजरीवाल सरकार की यह घोषणा पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मानी जाएगी।सोमवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी यह अच्छी तरह से मालूम है कि केंद्र सरकार उनके इस मंसूबे को लागू करने के लिए कभी राजी नहीं होगी। भले ही दिल्ली सरकार इसके लिए कितनी भी सब्सिडी दे दे। सच तो यह है कि केजरीवाल इस घोषणा से दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि केंद्र इस योजना को लागू करने पर राजी नहीं होगा। इससे विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बना कर दिल्ली की जनता के बीच जा सकेंगे।

दिल्ली सरकार ने पहले भी बहुत झूठे वादे किए हैं। सीसीटीवी कैमरे, फ्री वाई-फाई देने से लेकर हाउस टैक्स में छूट जैसी कई घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुईं। अब यह आप सरकार का नया शिगूफा है। आम आदमी पार्टी मुफ्त यात्रा का लाभ महिलाओं को दे, लेकिन छात्रों और बुर्जुगों को भी दे। इन दोनों वर्गों को ही इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने कहा कि केजरीवाल अब दिल्लीवासियों को मूर्ख नहीं बना सकेंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ही महिलाओं को मुफ्त यात्रा का झांसा दिया है।

उजड़ी जमीन बचाने को झूठी घोषणा कर रहे सीएम : भाजपा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

भाजपा ने मेट्रो व दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा की मुख्यमंत्री की घोषणा को हवाहवाई करार दिया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घोषणा मंत्री करार देते हुए उन्हें दिल्ली की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में लोगों को 70 झूठी घोषणाओं की जाल में फंसाने वाले केजरीवाल अब फिर से लोगों को भ्रमित करने की साजिश रच रहे हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने दिल्ली को नंबर वन बनाने की घोषणा की थी। विकास व अन्य किसी सराहनीय काम में तो दिल्ली नंबर वन नहीं बनी, लेकिन विश्व की सबसे प्रदूषित शहर जरूर बन गई।

मनोज तिवारी प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बेचैन हो गए हैं। महिलाओं की मुफ्त यात्रा की घोषणा तो अच्छी है, लेकिन यह पूरी तरह से हवाहवाई है। वर्तमान समय में दिल्ली में 20 हजार बसों की जरूरत है, लेकिन डीटीसी के पास सड़क पर चलाने लायक मात्र 33 सौ बसें हैं। ऐसे में वह महिलाओं को मुफ्त सफर कैसे करा सकेंगे? चुनाव नजदीक है इसलिए इस तरह की कई और घोषणाएं होंगी। संभव है कि यह घोषणा कर दी जाए कि सभी के घर के बाहर एक बस खड़ी की जाएगी ताकि लोग जब चाहें, सवारी कर सकते हैं।

मनोज तिवारी (फाइल) **मनोज तिवारी ने केजरीवाल को दिल्ली की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया**

उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शलों की तैनाती और पैनिक बटन लगाने का वादा किया था। अब हार से मुख्यमंत्री खुद पैनिक हो गए हैं और जल्दबाजी में झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है, वह स्थिति आ जाए जब किसी को किराया नहीं देना पड़े, लेकिन इसके लिए काम करना होगा।

उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 52 माह में कुछ नहीं कर सका, वह तीन-चार माह में क्या करेगा? यदि केजरीवाल कुछ करना चाहते हैं तो आयुष्मान भारत योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू करें। यदि वह नहीं करेंगे तो छह माह बाद भाजपा की सरकार आने के बाद इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा केजरीवाल के झूठ को सफल नहीं होने देगी। अपने प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से मेट्रो का किराया बढ़ाने वाले मुख्यमंत्री अब मुफ्त सफर कराने का झांसा दे रहे हैं। दरअसल अपनी उजड़ी हुई जमीन पर खाद व पानी देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वह सफल नहीं होंगे। दिल्ली के लोगों को वोट खरीदने की उनकी कोशिश से सतर्क रहना चाहिए।

जनता के बीच आज से जाएगी सरकार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो सख्ती दिखाई है, उसका असर मंगलवार से दिल्ली में दिखाई पड़ेगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली के मंत्री न सिर्फ जनता के बीच जाएंगे, बल्कि उनकी समस्याओं को सुनकर उनका तत्काल समाधान करने की कोशिश भी करेंगे। मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा समय जनता के बीच गुजारने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच मंत्री अपने विभागों का औचक निरीक्षण कर कामकाज का जायजा भी लेंगे।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले से ही विभिन्न इलाकों में पदयात्रा व जनसंपर्क कर रहे हैं। अब वह दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण कर कामकाज की गति को देखेंगे। इस बीच वह खुद भी जनता के बीच जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे।

सिसोदिया ने किया स्कूलों का निरीक्षण : उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को सात स्कूलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न हिस्सों में यह दौरे जारी रहेंगे ताकि लोगों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया जा सके। मंगलवार से सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सिग्नेचर ब्रिज सहित अन्य ढांचागत योजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा।

सत्येंद्र जैन जनता के बीच बिताएंगे ज्यादातर समय : कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन अस्पतालों, मोहल्ला क्लीनिक, सड़कों, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण की ढांचागत योजनाओं के साथ-साथ बिजली, हेल्थकेयर और लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी अन्य सेवाओं से संबंधित कामकाज का जायजा लेंगे। वह मंगलवार से अपना ज्यादातर समय जनता के बीच बिताएंगे।

न्यूनतम वेतन पर गोपाल राय का रहेगा जोर : मंत्री गोपाल राय भी मंगलवार से जनता के बीच रहेंगे। वह अपने विभागों से संबंधित विभिन्न योजनाओं और मजदूरों के हितों को लेकर उठाए गए कदमों का जायजा लेंगे। इसके अलावा राय दिल्ली में न्यूनतम वेतन लागू करने को लेकर भी विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण करेंगे।

न्यूज गैलरी

भूजल की जांच कर एक माह में सौंपे रिपोर्ट : एनजीटी

नई दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भूजल के नमूने लेकर इनकी जांच करने का आदेश दिया है। एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी और केंद्रीय भूजल बोर्ड के अधिकारियों की पूर्व में गठित की गई संयुक्त कमेटी से एक माह में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। स्थानीय निवासी महेश सक्सेना ने एनजीटी में याचिका दायर कर कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, दक्षिण दिल्ली नगर निगम जो वर्षा जल संचयन संयंत्र से भूजल को रिचार्ज करने की प्रक्रिया अपना रहे हैं, वह ठीक नहीं है। जल संचयन संयंत्र से बरसात के पानी को भूगर्भ में भेजा जाता है। इससे बरसात के पानी के साथ भारी मात्रा में गंदगी भी भूगर्भ तक पहुंचती है। इसके चलते भूजल दूषित हो रहा है। इस दलील पर ही एनजीटी ने भूजल के नमूने लेकर जांच करने को कहा है ताकि पता चल सके कि पानी में प्रदूषण का स्तर क्या है। (जासं)

पत्नी सक्षम तो तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं

नई दिल्ली : एक महिला की गुजारा भत्ता अर्जी को खारिज करते हुए अदालत ने कहा है कि पत्नी काम करने और अपनी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम है तो वह पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार नहीं है। दिल्ली की एक अदालत में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा कानून के तहत अर्जी दायर कर महिला ने अलग हो चुके पति से अंतरिम भत्ते की मांग की थी। याचिकाकर्ता महिला के मुताबिक, उसका पति 70 हजार रुपये मासिक कमाता है। उसने बताया कि वह 2016 तक दस हजार रुपये मासिक तनख्वाह पर नौकरी कर रही थी, लेकिन अब उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। पति के वकील की तरफ से दलील दी गई कि वह 35 हजार रुपये मासिक कमाता है। शिकायतकर्ता फिलहाल एक प्रतिष्ठित कंपनी में एचआर विभाग में है और जानबूझकर गलत जानकारी दे रही है। (जासं)

मुफ्त यात्रा को लेकर डीएमआरसी का मंथन शुरू

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा किस तरह दी जा सकती है, इसे लेकर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने मंथन शुरू दिया है। डीएमआरसी के अधिकारी मौजूदा प्रावधान व मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश व निकास की उपलब्ध व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विकल्प तलाशने लगे हैं।

डीएमआरसी के सूत्रों के मुताबिक इस योजना को लागू कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तकनीकी रूप से कई अड़चने सामने आ सकती हैं। सबसे बड़ी तकनीकी अड़चन ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन गेट (एएफसी) के माध्यम से स्टेशन पर प्रवेश व निकास से संबंधित है।

मेट्रो में टोकन या स्मार्ट कार्ड के माध्यम से ही यात्रियों को स्टेशन पर प्रवेश मिलता है। मौजूदा समय में एएफसी गेट का साफ्टवेयर सब्सिडी के अनुकूल अपडेट नहीं है। इसलिए मौजूदा एएफसी गेट के माध्यम से निःशुल्क यात्रा के लिए महिला यात्रियों को प्रवेश देना आसान नहीं होगा। मेट्रो स्टेशन पर मैनुअल तरीके से साधारण गेट (दरवाजे) से यात्रियों को प्रवेश देने का प्रावधान नहीं है। यदि पास के जरिये महिला यात्रियों को प्रवेश देने की सुविधा शुरू भी हुई तो इसे लंबे समय तक बरकरार रखना संभव नहीं होगा। ऐसे में एएफसी गेट के सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा या अलग नए एएफसी गेट लगाने पड़ सकते हैं।

मेट्रो में केंद्र व दिल्ली सरकार की 50-50 फीसद हिस्सेदारी है। डीएमआरसी में अधिकारी इस बात पर भी मंथन कर रहे हैं कि मेट्रो में किराये से संबंधित फैसला किराया निर्धारण कमेटी करती है। यह कमेटी केंद्र सरकार गठित करती है। कमेटी की सिफारिश के आधार पर मेट्रो बोर्ड किराये पर फैसला करता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने सब्सिडी के रूप में महिलाओं का किराया भुगतान करने की बात कही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस फैसले के सामने किराया निर्धारण कमेटी की बाध्यता आड़े नहीं आएगी। हालांकि डीएमआरसी मेट्रो में किसी भी तरह के पास की सुविधा को लागू करने के खिलाफ रहा है, लेकिन मेट्रो का किराया बढ़ने के बाद डीएमआरसी के अधिकारी कह चुके हैं कि सरकार चाहे तो कुछ खास वर्गों को किराये पर सब्सिडी दे सकती है। एक तकनीकी अड़चन यह भी है कि दिल्ली मेट्रो सिर्फ राजधानी में नहीं चलती, बल्कि एनसीआर के शहरों में भी डीएमआरसी मेट्रो का परिचालन कर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एनसीआर के स्टेशनों से मेट्रो में सफर करके दिल्ली पहुंचने वाली महिलाओं को किराया भुगतान करना होगा? बहरहाल, डीएमआरसी तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार को कुछ ही दिनों में अपना जवाब भेजेगा।

बुजुर्गों व छात्रों को किराये में छूट देने की बात कह चुका केंद्र

किराया बढ़ोतरी पर विवाद के बाद केंद्र सरकार भी बुजुर्गों व छात्रों को किराये में छूट देने की बात कह चुकी है। इसके लिए डीएमआरसी को नीति तैयार करने के लिए भी कहा गया था। किराया निर्धारण कमेटी का अगली बार गठन होने पर इस पर भी विचार किया जा सकता है।

सिस्टम में बदलाव की पहले से चल रही तैयारी

कुछ माह पहले डीएमआरसी ने बायोमेट्रिक आधारित एएफसी गेट लगाने की पहल की है। इस तरह के गेट लगाने के लिए निजी एजेंसियों को आमंत्रित किया गया है। इससे आने वाले दिनों में किसी खास वर्ग को किराये में राहत देने की योजना लागू करने में मदद मिलेगी, लेकिन बायोमेट्रिक एएफसी गेट लगने में अभी लंबा वक्त लगेगा।

ग्रे लाइन पर द्वारका से नजफगढ़ के बीच जल्द रफ्तार भरेगी मेट्रो

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

द्वारका से नजफगढ़ स्थित ढांसा बस स्टैंड के बीच फेज-तीन में निर्माणाधीन 5.83 किलोमीटर लंबी ग्रे लाइन दो चरणों में बनकर तैयार होगी। पहले चरण में द्वारका से नजफगढ़ के बीच कॉरिडोर काफी हद तक बनकर तैयार है। मेट्रो ट्रैक व स्टेशनों के फिनिशिंग का काम चल रहा है। नजफगढ़ से ढांसा बस स्टैंड के बीच कॉरिडोर के निर्माण में अभी डेढ़ साल का समय लगेगा इसलिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ढांसा बस स्टैंड तक कॉरिडोर निर्माण पूरा होने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि उससे पहले द्वारका से नजफगढ़ के बीच मेट्रो परिचालन शुरू कर देगा। उम्मीद है कि सितंबर तक ग्रे लाइन के इस कॉरिडोर पर मेट्रो रफ्तार भरने लगेगी।

फेज-तीन में पहले द्वारका से नजफगढ़ के बीच 4.29 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण शुरू हुआ था। यह कॉरिडोर दिसंबर 2016 में बनकर तैयार होना था। लेकिन जमीन विवाद के कारण निर्माण कार्य में विलंब हुआ। अब इसका करीब 95 फीसद काम पूरा हो चुका है। इस कॉरिडोर पर द्वारका, नंगली व नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। डीएमआरसी के अनुसार, नजफगढ़-ढांसा बस स्टैंड के बीच 1.54 किलोमीटर लंबे भूमिगत कॉरिडोर का अभी तक करीब 14 फीसद ही काम पूरा है। दिसंबर 2020 में इसका निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि द्वारका-नजफगढ़ कॉरिडोर पर अंतिम दौर का काम चल रहा है। ग्रे लाइन दिल्ली मेट्रो का सबसे छोटा कॉरिडोर होगा। इस पर चलने वाली मेट्रो द्वारका मेट्रो स्टेशन से ही वापस नजफगढ़ लौट जाएगी। इसलिए द्वारका मेट्रो स्टेशन इस कॉरिडोर पर ब्लू लाइन के साथ इंटरचेंज स्टेशन होगा।

जेएनयू में पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए 224 कमरों का छात्रावास बनेगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में पूर्वोत्तर के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 11 करोड़ रुपये है और इसमें 424 विद्यार्थियों की रहने की व्यवस्था होगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के बयान के मुताबिक, यह छात्रावास डेढ़ एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला होगा और इमारत के निर्माण का काम जल्द शुरू होगा। यह अपनी तरह का पहला छात्रावास है। इसमें 200 छात्रों और 200 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा दिव्यांग छात्रों के लिए 24 कमरे होंगे।

मंत्रालय के अधिकारियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह को जेएनयू छात्रावास और अन्य परियोजनाओं से जुड़े काम की प्रगति के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री को बताया गया कि जेएनयू छात्रावास के निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) निविदा जारी करने की प्रक्रिया में है। उन्हें यह भी बताया गया कि बेंगलुरु में पूर्वोत्तर की छात्राओं के लिए बनाया गया छात्रावास शुरू हो गया है।

11 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले छात्रावास में रह सकेंगे 424 छात्र-छात्राएं

दिल्ली विवि के विद्यार्थियों के लिए भी बनेगा छात्रावास : दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों और संस्थानों में पढ़ने वाले पूर्वोत्तर छात्रों के लिए रोहिणी में छात्रावास के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को जमीन के लिए 2.5 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। छात्रावास लगभग पांच एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा। बैठक के दौरान द्वारका में स्थापित किए जाने वाले पूर्वोत्तर सांस्कृतिक एवं सूचना केंद्र की स्थिति पर भी चर्चा की गई।

बीटेक छात्र ने आठवीं मंजिल से कूदकर दी जान

जागरण संवाददाता, नोएडा : गलगोटिया विश्वविद्यालय के बीटेक चतुर्थ वर्ष के छात्र ने मानसिक अवसाद के चलते आठवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। कम उपस्थिति के चलते अंतिम वर्ष में उसे परीक्षा देने से रोक दिया गया था। मूलरूप से झारखंड के धनबाद में हास्पिटल रोड (निकट दुर्गा मंदिर जमदोवा) निवासी नीरज कुमार भारती कासना कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर-पाइ स्थित एचपीसीएल सोसायटी में रह रहा था। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। नीरज दोस्तों के साथ प्रथम तल के फ्लैट में किराये पर रहता था।

शनिवार रात सोसायटी की बिजली कट गई थी। सभी छात्र खाना खाने के लिए गए थे, लेकिन नीरज नहीं गया। जब सभी लोग सो गए तो नीरज सोसायटी की आठवीं मंजिल पर गया और वहां से छलांग लगा दी। दोस्तों ने रात तीन बजे उसे जमीन पर पड़ा देखा। नीरज का एक बड़ा भाई व एक छोटी बहन है। रिश्तेदारों ने किसी तरह की कार्रवाई से इन्कार किया और शव लेकर झारखंड के लिए रवाना हो गए।

पति की लंबी आयु की कामना

वट सावित्री व्रत के अवसर पर गाजियाबाद में सुबह बरगद के पेड़ के नीचे महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा की और पति की लंबी आयु की कामना की। साथ ही सौभाग्यवती होने का वर मांगा। राजनगर एक्सटेंशन में वट पूजा करती महिलाएं। जागरण

मिशन एडमिशन

कई कॉलेज ईसीए और खेल कोटे को लेकर करते थे मनमानी, अब उन्हें प्रत्येक पाठ्यक्रम में कम से कम एक फीसद सीट देनी होगी

ईसीए और खेल कोटे से दाखिले की सीमा तय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की दाखिला समिति की सोमवार को हुई बैठक में एक्सट्रा करिकुलर एक्टीविटी (ईसीए) और खेल कोटे को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके तहत कॉलेजों में अब सभी पाठ्यक्रमों में ईसीए व खेल कोटे की सीमा निर्धारित की गई है। ईसीए व खेल कोटे की दाखिला प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है। डीयू में ईसीए व खेल कोटे के लिए पांच फीसद अतिरिक्त सीटें हैं। कई कॉलेज ईसीए में एक फीसद और खेल कोटे में चार फीसद तक दाखिला देते हैं तो कुछ कॉलेज ईसीए में दो फीसद और खेल कोटे में तीन फीसद तक दाखिला देते हैं। कुछ कॉलेज ईसीए को सीट नहीं देते थे, लेकिन अब उन्हें कम से कम एक फीसद सीट देनी होगी।

बीते कुछ वर्षों से यह देखा जा रहा है कि बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे पाठ्यक्रमों को ईसीए व खेल कोटे के छात्र ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। वहीं पंजाबी, उर्दू, हिंदी व साइंस पाठ्यक्रमों में इन कोटे के तहत कम सीटें भरती हैं। कई शिक्षकों ने यह भी कहा कि कॉलेज स्तर पर ऐसा भी होता था कि सिर्फ दो-तीन ही पाठ्यक्रमों में ईसीए व खेल कोटे के दाखिले ज्यादा कर लिए जाते थे। उदाहरण के तौर पर कॉलेज में सिर्फ पांच फीसद ही ईसीए व खेल कोटे में सीटें निर्धारित हैं। अगर किसी कॉलेज में 1200 सीटें हैं तो पांच फीसद के अनुसार 60 सीटें ईसीए व खेल कोटे की होंगी। पहले ऐसा होता था कि बीकॉम ऑनर्स पाठ्यक्रम में कुल 160 सीटें हैं तो उसमें से ईसीए व खेल कोटे की 40 से ज्यादा सीटें भर दी जाती थीं। इससे बाकी पाठ्यक्रमों में इन दोनों कोटे के तहत दाखिला नहीं हो पाता था। अब दाखिला समिति ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी पाठ्यक्रम में ईसीए व खेल कोटे के तहत दाखिले उस पाठ्यक्रम में निर्धारित की गईं सीटों के दस फीसद से ज्यादा नहीं होंगे। डीयू के अकादमिक परिषद के सदस्य प्रो. रसाल सिंह ने कहा कि दाखिला समिति ने ईसीए व खेल कोटे को लेकर जो निर्णय लिया है उससे प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। शिक्षक भी ऐसी ही व्यवस्था किए जाने की मांग कर रहे थे।

पीजी, एमफिल और पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया भी हुई शुरू

जासं, नई दिल्ली : डीयू प्रशासन ने सोमवार को परास्नातक (पीजी), पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, एमफिल व पीएचडी पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। आठ बजे तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू नहीं होने से छात्र परेशान भी दिखे। इस मामले में डीयू के अधिकारियों ने कहा कि स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के चलते डीयू की वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रैफिक इस समय बहुत ज्यादा है, जिससे पीजी रजिस्ट्रेशन के लिए दाखिला विंडो देर से खुली।

डीयू की दाखिला समिति के अनुसार 30 मई से शुरू हुई स्नातक पाठ्यक्रमों की दाखिला प्रक्रिया के तहत सोमवार तक 1,92,213 छात्र आवेदन कर चुके हैं। इनमें से 98,728 छात्रों ने दाखिला शुल्क भी जमा कर दिया है। सामान्य श्रेणी के 62,868, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16,874, एससी के 14,348, एसटी के 2,904 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1,734 छात्रों ने दाखिला शुल्क जमा कराया है।

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं मिलने से छात्र परेशान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) का दूसरा ओपन डे सोमवार को नॉर्थ कैंपस के कांफ्रेंस सेंटर में स्टूडेंट वेलफेयर के डीन कार्यालय की तरफ से आयोजित किया गया। स्टूडेंट वेलफेयर के डीन प्रो. राजीव गुप्ता, दाखिला समिति से जुड़े अधिकारी व शिकायत निवारण समिति के सदस्यों ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए। छात्रों ने सर्वाधिक सवाल आरक्षित वर्ग के प्रमाण पत्रों को लेकर किए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर आने वाली समस्याएं भी बताईं।

छात्रों ने डीयू के अधिकारियों से कहा कि वे एसडीएम व तहसीलदार के कार्यालय में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए जाते हैं तो जवाब मिलता है कि उनके पास इस प्रमाण पत्र को लेकर कोई अधिसूचना नहीं आई है। छात्रों ने कहा कि डीयू प्रशासन कह रहा है कि अगर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है तो उसकी रसीद की फोटोकॉपी अपने हस्ताक्षर के साथ दाखिला पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रसीद ही नहीं दी जा रही है। इस पर डीयू की शिकायत निवारण समिति के सदस्य डॉ. विजय वर्मा ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर विश्वविद्यालय के पास क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीनस्थ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का आदेश आया है। इस विभाग की तरफ से सभी सरकारी संस्थानों को आदेश जारी हुआ है। अगर एसडीएम और तहसीलदार की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पास इस मामले में कोई अधिसूचना नहीं आई है तो छात्र उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचें।

डीयू के कांफ्रेंस सेंटर में आयोजित ओपन डे में दाखिला संबंधित प्रश्न पूछती छात्रा। जागरण

पीएनबी घोटाले में चोकसी की याचिका पर सीबीआइ को नोटिस

मुंबई, एएनआइ : विशेष सीबीआइ अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की अर्जी पर सीबीआइ को नोटिस जारी किया है। चोकसी ने सीबीआइ जांच को अधूरा करार देते हुए दोबारा जांच की मांग की है। विशेष सीबीआइ जज यूएम मुधोलकर ने चोकसी की अर्जी पर यह आदेश देते हुए अगली सुनवाई 17 जून को तय की।

चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कोर्ट में कहा, जांच अधिकारी (आइओ) ने कई अहम पहलुओं की आधी-अधूरी जांच कर चार्जशीट दायर कर दी। अधूरी जांच से चोकसी का व्यवसाय चौपट हो गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि सीबीआइ ने उसके खिलाफ दो और 15 फरवरी, 2018 को फर्जी एफआइआर दर्ज किया था।

चोकसी के वकील ने कहा,उनके मुवक्किल की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं की गई थी। सच यह है कि पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों और ऑडिटरों की तरफ से गलती की गई थी, जांच अधिकारी ने इनकी अनदेखी की। सुनवाई के दौरान जज के सामने हमने कई खामियों को रखा। बता दें कि 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले में चोकसी के साथ ही उसका भांजा नीरव मोदी भी आरोपित है। एक साल पहले दोनों देश छोड़कर फरार हो गए थे। चोकसी ने 15 जनवरी, 2018 को एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता भी हासिल कर ली थी। जबकि, नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार किया गया है। उसके प्रत्यर्पण की कार्यवाही चल रही है।

सीबीआइ तीन माह में पूरी करे मुजफ्फरपुर कांड की जांच

सुप्रीम निर्देश ▶ बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड में दी व्यवस्था

जांच एजेंसी को धारा 377, मानव तस्करी के आरोपों की भी जांच करने को कहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ वीडियो फिल्म बनाने के आरोपों पर आइटी एक्ट के पहलुओं की भी जांच की जाएगी

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड की जांच पूरी करने के लिए सीबीआइ को और तीन महीने का वक्त दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआइ से जांच का दायरा बढ़ा कर मानव तस्करी, धारा 377 के आरोपों की भी जांच करने को कहा है।

यह आदेश जस्टिस इंदू मल्होत्रा व जस्टिस एमआर शाह की अवकाश कालीन पीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद सोमवार को दिए। सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल माधवी दीवान ने कोर्ट से जांच पूरी करने के लिए छह महीने का और समय दिए जाने की मांग की। सीबीआइ को इतना समय दिए जाने का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के वकील शेखर नाफड़े और फौजिया ने कहा कि सीबीआइ ने गत वर्ष जांच अपने हाथ में ली थी। इतना समय बीत चुका है और अब यह और छह महीने मांग रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई पहलुओं पर अभी जांच नहीं हुई है। लड़कियों के बयान हैं कि बाहर के लोग आते थे और लड़कियों का यौन शोषण करते थे। लड़कियों को बाहर भी भेजा जाता था। न्याय मित्र अपर्णा भट्ट ने कहा कि जो ट्रायल चल रहा है वह तो ठीक है लेकिन लड़कियों ने अप्राकृतिक यौनाचार के भी आरोप लगाए हैं ऐसे में धारा 377 के पहलू की भी जांच होनी चाहिए जो कि नहीं हुई। इसके अलावा लड़कियों ने यौन शोषण की वीडियो फिल्म बनाने की भी बात कही है जो आइटीएक्ट में आता है। सीबीआइ ने कहा कि वह जांच कर ही है लड़कियों के बयान जांचे जा रहे हैं कुछ अभी भी गायब हैं। दो कंकाल मिले हैं जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है कि वे कंकाल किसी पुरुष के हैं या स्त्री के। रिपोर्ट अभी आनी है।

सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआइ को जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय दिया। साथ ही कहा कि सीबीआइ चार और पहलुओं की जांच करे जिसमें मानव तस्करी, शेल्टर होम में बाहर के लोगों के आने और धारा 377 तथा आइटी एक्ट के पहलू की भी जांच करे। मामले के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर ने भी एक अर्जी दाखिल कर उसे पक्षकर बनाने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि बिहार का यह मामला सामने आने के बाद देश में सियासी पारा काफी चढ़ गया था। इस मामले को लेकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली साझा सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। उस दौरान राज्य में विपक्षी दल के रूप में भाजपा नेताओं ने भी खूब हंगामा किया था।

मालेगांव मामले में साध्वी प्रज्ञा को कोर्ट में पेश होना ही होगा

मुंबई, प्रेट्र : भोपाल से नवनिर्वाचित सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मालेगांव विस्फोट मामले में इस हफ्ते विशेष अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना ही होगा। अदालत ने सोमवार को व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका खारिज कर दी। 2008 में हुए विस्फोट मामले में प्रज्ञा आरोपित हैं।

विशेष एनआइए जज वीएस पडलकर ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि मामले के इस चरण में अदालत में उनकी व्यक्तिगत मौजूदगी आवश्यक है।अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए जो आधार बनाया गया है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जज ने यह भी कहा, इससे पहले भी आरोपित ने कई बार कोर्ट में मौजूद रहने का भरोसा दिलाया, लेकिन पेश नहीं हुई। जज ने ठाकुर के खिलाफ अभियोजन पक्ष गवाही कराने वाला है, इसलिए अदालत में उनकी मौजूदगी आवश्यक है। अदालत ने दो हफ्ते पहले ठाकुर के साथ ही दो अन्य आरोपितों लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी को एक हफ्ते के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान की थी। इन तीनों के अलावा इस मामले में मेजर (रि.) रमेश उपाध्याय, अजय रहिरकर, सुधार द्विवेदी और समीर कुलकर्णी भी आरोपित हैं और ये सभी अभी जमानत पर हैं। मालेगांव में एक मस्जिद के पास 29 सितंबर, 2008 को हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हुई थी और सौ से ज्यादा घायल हुए थे। आरोपितों के खिलाफ यूएपीए और आइपीसी (भारतीय दंड संहिता) की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं।

अजीत डोभाल फिर बने एनएसए, कद भी बढ़ा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ राज्यमंत्री की जगह अब कैबिनेट मंत्री का मिला दर्जा

▶ सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का फैसला

पिछले पांच साल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा को नया आयाम देने में अहम भूमिका निभाने वाले अजीत डोभाल अगले पांच वर्षों तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने रहेंगे। इसके साथ ही उनका ओहदा भी बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि पहले उनका दर्जा राज्यमंत्री का था। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने डोभाल को एनएसए बनाए रखने का फैसला लिया।

वीरता के लिए सबसे बड़े नागरिक सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित और आइबी के पूर्व निदेशक डोभाल ने उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की योजना बनाने और उन्हें मूर्त रूप देने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही उन्हें आंतरिक सुरक्षा तंत्र को भी चाक-चौबंद करने का श्रेय जाता है। जिस कारण पिछले पांच साल में तमाम कोशिशों के बावजूद आइएस से लेकर अलकायदा तक कोई भी आतंकी संगठन भारत में पैर जमाने में सफल नहीं हो सका और उनके मंसूबे को शुरुआती दौर में ही कुचल दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा में डोभाल की अहम भूमिका देखते हुए मोदी सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में उन्हें डिफेंस प्लानिंग कमेटी का प्रमुख बना दिया था। इसके प्रमुख कैबिनेट सचिव हुआ करते थे। एनएसए और कैबिनेट सचिव के साथ ही गृह सचिव, रक्षा सचिव, विदेश सचिव और तीनों सेना के प्रमुख इसके सदस्य हैं। यह देश की सुरक्षा में फैसला लेने वाली सबसे बड़ी निकाय है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ कूटनीतिक क्षेत्र में डोभाल ने अहम भूमिका निभाई थी। खासतौर चीन के साथ संबंधों को सुधारने का जिम्मा उनके कंधों पर था। भारत-चीन सीमा विवाद का स्थायी समाधान निकालने के लिए गठित समिति में भारत की ओर से डोभाल ही प्रतिनिधित्व करते हैं और इस सिलसिले में चीन के एनएसए के साथ उनकी कई दौर की बातचीत हो चुकी है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के अलावा भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत में लाने में केंद्रीय भूमिका निभाने का श्रेय उन्हें जाता है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में क्रिश्चियन मिशेल को भारत लाने में अजीत डोभाल और उनकी टीम ने ही मेहनत की थी। यही कारण है कि ब्रिटिश नागरिक होने के बावजूद यूएई से इसे प्रत्यर्पित कराने में सफलता मिली।

नई दिल्ली में सोमवार को नॉर्थ ब्लॉक में एक बैठक के बाद बाहर निकलते राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। प्रेट्र

कश्मीर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर अमित शाह का ध्यान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अमित शाह (फाइल)

आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा की, खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों ने दी ताजा हालात की जानकारी

गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा की ताजा हालात का जायजा लिया। साथ ही जम्मू एवं कश्मीर से जुड़े अफसरों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ विशेष बैठक की। जम्मू एवं कश्मीर और नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात अर्धसैनिक बल के प्रमुखों से अलग से मिले। शनिवार को गृह मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद गृह मंत्रालय में शाह का दूसरा दिन था।

गृह मंत्रालय में शाह की शुरुआत आंतरिक सुरक्षा के हालात पर विशेष ब्रीफिंग के साथ हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव राजीव गौबा, खुफिया ब्यूरो प्रमुख राजीव जैन और रॉ के सचिव अनिल धस्माना ने गृह मंत्री को ताजा हालात की जानकारी दी। डोभाल और राजीव जैन ने जम्मू व कश्मीर और नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के हालात के बारे में बताया तो अनिल धस्माना ने पड़ोसी देशों के हालात की जानकारी दी। वैसे तो गृह मंत्री को सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों की ओर से हर दिन ब्रीफिंग की परंपरा है, पर शाह को गृह मंत्री के रूप में पहली बार यह ब्रीफिंग दी गई। इसके बाद शाह ने जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति पर अफसरों के साथ लंबी चर्चा की। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने अगले माह शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया और उसे चुस्त-दुरुस्त करने के लिए जरूरी निर्देश दिए। बाद में उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों और जम्मू एवं कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के साथ अलग से बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। सुबह 10 बजे गृह मंत्रालय पहुंचे शाह शाम तक काम करते रहे और दोपहर का भोजन भी उन्होंने वहीं किया।

अनुकरणीय संदेश

विश्व साइकिल दिवस पर सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन, केंद्रीय भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अनूठा संदेश दिया। हर्षवर्धन और अर्जुन राम मेघवाल नई दिल्ली में साइकिल चलाकर कार्यालय पहुंचे और अपना पदभार ग्रहण किया। जबकि चंडीगढ़ में मनोहर लाल खट्टर ने घर से सचिवालय तक का सफर साइकिल से तय किया। इस तरह इन नेताओं ने पर्यावरण और शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित किया। गौरतलब है कि पर्यावरण और स्वास्थ्य चुनौतियों के मद्देनजर साइकिल का दौर लौटता दिख रहा है। प्रेट्र/जागरण

17 से लोकसभा और 20 जून से शुरू होगा राज्यसभा का सत्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति द्वारा आहूत संसद के आगामी सत्र के दौरान राज्यसभा की बैठक 20 जून से शुरू होगी। वहीं 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरू होगा। दोनों सदनों की बैठक 26 जुलाई तक चलेगी। राज्यसभा के महासचिव देशदीपक वर्मा ने एक बयान में बताया कि संसद के आगमी सत्र के मद्देनजर राष्ट्रपति ने राज्यसभा की बैठक 20 जून से बुलाई है। यह 26 जुलाई तक चलेगी।

संसद भवन। फाइल

वहीं 17 जून से शुरू हो रहे लोकसभा के पहले सत्र के शुरुआत के दो दिनों में नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। 19 जून को लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। 20 जून को 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसी सत्र में बजट पेश करेंगी।

आंध्र में सीबीआइ जांच को जगन सरकार ने दी मंजूरी

अमरावती, एएनआइ : पूर्व की तेदेपा सरकार के फैसले को पलटते हुए आंध्र प्रदेश की नई वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार ने सीबीआइ को राज्य में जांच करने की अनुमति दे दी है। वाईएसआरसीपी के नेता विजयसाई रेड्डी ने ट्वीट कर कहा है, 'चंद्रबाबू ने सीबीआइ पर प्रतिबंध लगा दिया था और आइटी को छापा मारने से रोक दिया था। अब जगन ने सीबीआइ को राज्य में अनुमति देने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि चोर को छोड़ा नहीं जाएगा। लुक आउट चंद्रबाबू।'

पूर्व की एन. चंद्रबाबू सरकार ने सीबीआइ को आंध्र प्रदेश में छापामारी करने और केंद्रीय प्रतिष्ठानों की जांच शुरू करने की आम सहमति वापस ले ली थी। यह फैसला उन्होंने पिछले वर्ष एक नवंबर को लिया था। नई सरकार ने इसी फैसले को पलट दिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब भाजपा की अगुआई वाली सरकार पर राजनीतिक फायदे के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लग रहा है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेबलिशमेंट एक्ट 1946 के नियम के मुताबिक, सीबीआइ का अधिकार क्षेत्र दिल्ली है। जांच एजेंसी किसी अन्य राज्य में वहां की सरकार की आम सहमति से कदम रख सकती है।

स्कूली शिक्षा में बदलाव किया जाएगा : रेड्डी ने कहा है कि राज्य के शिक्षा ढांचे में भी बदलाव किया जाएगा। शनिवार को बैग रहित दिवस बनाया जाएगा। खेल और शारीरिक विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। मिड डे मील में पोषक खुराक दी जाएगी। मिड डे मील के कर्मचारियों की तनख्वाह 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 की जाएगी। यह मानवता का नियम है। शराब नीति में भी बदलाव किया जाएगा।

▶ चंद्रबाबू सरकार ने लगा दिया था प्रतिबंध

जगन मोहन रेड्डी। फाइल

आशा वर्करों का वेतन बढ़ाया : मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सोमवार को राज्य में आशा कार्यकर्ताओं का वेतन 3000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। मुख्यमंत्री ने अपने कैंप कार्यालय में मेडिकल एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया।

आयुष्मान भारत योजना को लागू कराना प्राथमिकता : हर्षवर्धन

नई दिल्ली, प्रेट्र : डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया। वर्ष 2014 में भी उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बाद में मंत्रालय जगत प्रकाश नड्डा को सौंप दिया गया था।

निर्माण भवन स्थित कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद हर्षवर्धन ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के क्रियान्वयन को मजबूत करने की होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि देश के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिले।

उन्होंने कहा, ''पीएम-जेएवाई की शुरुआत से अभी तक 27 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। लेकिन अभी तक बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है।''

डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस योजना को विस्तार देने पर विचार किया जा रहा है, ताकि जो गरीब इसका लाभ पाने से वंचित रह गए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों को लाने की कोशिश की जा रही है। हमारा उद्देश्य हर गरीब तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है।

▶ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया

साइकिल से पहुंचे दफ्तर

डॉ. हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए साइकिल से अपने दफ्तर निर्माण भवन पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र ने तीन जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया है। उन्होंने लोगों से भी साइकिल का उपयोग करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि वह नियमित रूप से साइकिल से आने की कोशिश करेंगे।

साइकिल से दफ्तर जाने की अपनी तस्वीर साझा करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने ट्वीट किया, 'साइकिल परिवहन का एक सरल, सस्ता, विश्वसनीय, स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से स्थायी साधन है। संयुक्त राष्ट्र ने तीन जून को 'विश्व साइकिल दिवस' सतत विकास लक्ष्यों के लिए साइकिल के योगदान को रेखांकित करने के लिए घोषित किया है। वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए यह मेरा पसंदीदा स्पोर्ट भी है।'

सियाचिन के रखवालों पर देश को नाज

राज्य ब्यूरो, जम्मू

▶ राजनाथ सिंह ने सैनिकों की पीठ थपथपाई, शहीदों को दी श्रद्धांजलि

▶ दुर्गम हालात में मातृभूमि की रक्षा कर रहे सैनिकों के बुलंद हौसले पर गर्व है

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सियाचिन के दुर्गम हालात में पाकिस्तान और चीन से लगती सरहदों की रक्षा कर रहे सेना के जांबाजों और उनके परिवारों पर पूरे देश को नाज है। उन्होंने कहा है कि मैं उन अभिभावकों का आभार जताने के लिए उन्हें पत्र लिखूंगा जिन्होंने अपने बच्चों को सेना में भर्ती होने के लिए भेजा। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन से राजनाथ सिंह ने सोमवार को नई जिम्मेदारी की शुरुआत की।

रक्षामंत्री ने शनिवार को दिल्ली में नई जिम्मेदारी संभाली थी। रक्षामंत्री के रूप में यह जिम्मेदारी निभाने की शुरुआत उन्होंने सेना की कर्मभूमि जम्मू कश्मीर से की। जम्मू कश्मीर में इस समय सेना पाकिस्तान और चीन से लगती सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ आतंकवाद से भी लड़ रही है। ऐसे हालात में दुनिया के सबसे ऊंचे सैन्य क्षेत्र सियाचिन के आधार शिविर में सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के साथ रक्षामंत्री ने सियाचिन वार मेमोरियल स्थल पर जाकर शहीद 1100 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि देश सियाचिन के शहीदों की सेवा व उनके त्याग का हमेशा आभारी रहेगा। इस दौरान थलसेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह और सेना की चौदह कोर के जीओसी भी मौजूद थे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के सियाचिन में वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने जवानों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाया और साथ में स्नैक्स भी साझा किया। प्रेट्र

तैयारियों की भी ली थाह : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे के करीब लेह पहुंचे। सेना की चौदह कोर मुख्यालय में अधिकारियों से पाक से लगती नियंत्रण रेखा और चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा चुनौतियों और उनसे निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की भी थाह ली। वहां से रक्षामंत्री साढ़े दस बजे सियाचिन पहुंचे। उनके साथ थलसेना प्रमुख भी थे।

पुराना सपना

प्रत्येक 10 से 15 किमी के दायरे में खुलेगा एक परिसर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में की गई है सिफारिश

पांच दशक बाद फिर आई स्कूल परिसर की याद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने के लिए पांच दशक पहले जो सपना देखा गया था, वह अब तक भले ही परवान नहीं चढ़ पाया है, स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने में जुटे नीति-नियंताओं को फिर से उसकी याद आयी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में प्रत्येक 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल परिसर खोलने का सुझाव दिया गया है, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास की हरेक सुविधा मौजूद होगी। इनमें खेलकूद से लेकर संगीत, पुस्तकालय सहित पर्याप्त शिक्षक शामिल हैं।

स्कूल परिसर स्थापित करने का मकसद नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को एक ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है, जो अभी उन्हें घर के आसपास के स्कूलों में नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल इसके तहत किसी एक माध्यमिक स्कूल को ही परिसर के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया गया है। इसके मुखिया माध्यमिक स्कूल के प्रधानाचार्य होंगे। जिनके पास प्रशासनिक, वित्तीय और शैक्षणिक अधिकार होंगे। साथ ही इसके दायरे में आने वाले सभी स्कूल इसके संचालन में मदद करेंगे।

सुधर रही है देश की शिक्षा व्यवस्था। फाइल

खास बात यह है कि आजादी के बाद देश में बने पहले शिक्षा आयोग ने भी 1966 में स्कूल परिसर बनाने की सिफारिश की थी। लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाया। स्कूलों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन वहां न तो पर्याप्त शिक्षक थे, न ही कोई संसाधन। इसके चलते स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी बेहद कमजोर स्थिति में है। इसका अंदाजा यू-डीआईएसई (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन) के 2016-17 के आंकडों से लगाया जा सकता है। देश के करीब 1.19 लाख स्कूल ऐसे है, जो एक शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। वहीं 28 फीसद ऐसे सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं, जहां बच्चों की संख्या 30 से भी कम है।

किस तरह की होगी सुविधाएं

- सभी तरह के खेलकूद की सुविधा
- संगीत से जुड़ी शिक्षा की व्यवस्था
- बेहतर प्रयोगशाला
- योग शिक्षक, भाषा शिक्षक, खेल व संगीत शिक्षक आदि की व्यवस्था
- काउंसलर की व्यवस्था
- बेहतर पुस्तकालय
- सभी विषयों के शिक्षक
- अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला

घुमंतू जातियों को आरक्षण दिलाने की उठाएंगे मांग : अठावले

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआइ) के प्रमुख रामदास अठावले ने सोमवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में बतौर राज्यमंत्री चार्ज संभाला। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही घूमंतू और विमुक्त जातियों को आरक्षण दिलाने की मांग तेज करेंगे। इस संबंध में जरूरत हुई, तो वह प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में पदभार संभालने के बाद अठावले पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान आंबेडकर फाउंडेशन की ओर से संचालित की जा रही योजनाओं में वित्तीय मदद बढ़ाने के भी संकेत दिए हैं। मौजूदा समय में फाउंडेशन की ओर से एससी-एसटी वर्ग को मेडिकल सुविधा सहित अंतर-जातीय विवाह के दौरान वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जा रही है। सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण के बाद घुमंतू जातियों के लिए आरक्षण को लेकर नई मांग उठ रही है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

संसदीय चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में उथल-पुथल तय

राज्य ब्यूरो, जम्मू

संसदीय चुनाव में करारी हार के बाद जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उथल-पुथल तय है। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस का पुनर्गठन होगा।

संसदीय चुनाव में प्रदेश प्रधान जीए मीर अनंतनाग संसदीय सीट से चुनाव हार गए हैं। गांधी नगर विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रहे रमण भल्ला ने इस बार जम्मू पुंछ संसदीय क्षेत्र से संसदीय चुनाव लड़ा। वे भले ही भाजपा के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा से चुनाव हार गए, लेकिन उनको 5.55 लाख के करीब वोट मिले। ऐसे में भल्ला एक मजबूत नेता के रूप में उभर कर सामने आए है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि जम्मू संभाग और लद्दाख का कार्यवाहक प्रधान बनाया जाना है, जिसमें रमण भल्ला को प्रदेश कांग्रेस का जम्मू का कार्यवाहक प्रधान बनाया जा सकता है। जम्मू संभाग में पार्टी के कार्यवाहक प्रधान में भल्ला का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। लद्दाख में पार्टी के नेता नवांग रिगजिन जोरा तीन बार विधायक रह चुके हैं। वे पीडीपी-कांग्रेस और बाद में नेकां-कांग्रेस गठबंधन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। लद्दाख में वे कांग्रेस के एक सशक्त नेता के रूप में जाने जाते हैं। जोरा को लद्दाख का कार्यवाहक प्रधान बनाया जा सकता है।

गत दिवस पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने श्रीनगर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की। इसमें कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के नेता शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में हार के कारणों पर मंथन किया गया। एक विचार निकल कर आया कि पार्टी को राज्य के तीनों क्षेत्रों में मजबूत करने के लिए कार्यवाहक प्रधान बनाए जाएं। पार्टी की जम्मू कश्मीर मामलों की प्रभारी अंबिका सोनी बैठक में शामिल नहीं हो पाईं।

आजाद ने तीनों क्षेत्रों के नेताओं से पार्टी की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। बैठक के बारे में औपचारिक तौर पर तो कुछ जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सूत्र बताते हैं कि आजाद दिल्ली में अंबिका सोनी, पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से सलाह मशविरा करेंगे। जीए मीर को प्रधान बने चार साल से अधिक का समय बीत गया है। प्रदेश प्रधान के पद से मीर को बदलने का फैसला अभी तय नहीं है। इसका फैसला व्यापक विचार-विमर्श के बाद राहुल गांधी को लेना है।

पीडीपी से निकला कोई भी नेता वापसी के लिए तैयार नहीं

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

इन प्रमुख नेताओं ने पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार भंग होने के बाद से किया है महबूबा से किनारा

बशारत बुखारी

डॉ. हसीब द्राबू

सईद अल्ताफ बुखारी

इमरान रजा अंसारी (सभी फाइल)

अस्तित्व के संकट से जूझ रही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) को फिर से खड़ा करने के लिए महबूबा मुफ्ती की अपने पुराने साथियों से घर वापसी की अपील का असर होता नजर नहीं आ रहा है। कोई भी वापस लौटने को तैयार नहीं है। पीडीपी छोड़ने वाले कई नामी नेताओं के मुताबिक, लोगों को हीलिंग टच देने के लिए बनी पार्टी अब एक परिवार की राजनीतिक एनजीओ बन चुकी है।

गौरतलब है कि बीते साल पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के भंग होने के बाद से ही पीडीपी में अंतर्कलह जारी है। पार्टी के लगभग एक दर्जन वरिष्ठ नेता, जिनमें कई पूर्व विधायक और मंत्री भी हैं, महबूबा मुफ्ती पर तानाशाही और अक्षमता का आरोप लगाते हुए उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। कइयों ने अन्य राजनीतिक दलों में अपने लिए भविष्य तलाश लिया है। हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनाव में पीडीपी ने कश्मीर की तीन सीटों पर चुनाव लड़ा और तीनों ही जगह वह हार गई। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग पुलवामा सीट से चुनाव लड़ा और वे भी हार गईं।

चुनाव में मिली हार के बाद पीडीपी अध्यक्ष ने अपने घर पर हार के कारणों पर मंथन और संगठन को फिर से मजबूत बनाने के लिए एक बैठक में फैसला किया था कि जो भी वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, उन्हें वापस लाया जाएगा। इसके लिए उनके साथ बातचीत की जाएगी। अलबत्ता, महबूबा मुफ्ती की अपील का कोई असर होता अभी तक नजर नहीं आया है। पूर्व वित्त मंत्री डॉ. हसीब द्राबू ने पीडीपी में अपनी वापसी की किसी भी गुंजाइश से इन्कार करते हुए कहा है कि महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में पीडीपी एक राजनीतिक एनजीओ बन चुकी है। उन्होंने कहा कि संसदीय चुनाव में मिली हार से हताश महबूबा अक्सर दावा करती हैं कि पीडीपी चुनाव के लिए नहीं बनी है। अगर ऐसा है तो फिर उन्होंने आज तक विभिन्न चुनावों में हिस्सा क्यों लिया। क्या अब पीडीपी कोई सियासी एनजीओ बनने जा रही है। वे एक अक्षम सियासतदां हैं, जो दो बार सांसद रहने और राज्य का मुख्यमंत्री पद संभालने के बावजूद भी अपनी पार्टी से बाहर कोई अन्य सियासी दोस्त नहीं बना पाई हैं। वे सिर्फ जलसे जुलूस निकालने वाली सियासतदां हैं, प्रशासक नहीं। उन्होंने पीडीपी को अपने परिवार और चहेतों की जमात बना दिया है। इसमें लौटने का कोई सवाल नहीं है।

पीडीपी छोड़ नेशनल कांफ्रेंस में शामिल हो चुके पूर्व राजस्व मंत्री बशारत बुखारी का कहना है कि पीडीपी में लौटने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पीडीपी छोड़ी, तो बहुत सोच समझकर छोड़ी थी। पीडीपी अब लोगों के जम्हूरी हक के लिए लड़ने वाली जमात नहीं रही है।

पूर्व शिक्षा मंत्री सईद अल्ताफ बुखारी का इस बारे में कहना है कि मुफ्ती साहब थे तो लगता था कि पीडीपी जम्मू-कश्मीर के अवाम के लिए बनी है। उनके जाने के बाद इसमें लगातार गिरावट आई है। महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में पीडीपी कुछ लोगों की जमात बनकर रह गई है और आज वह अपने वजूद के अंतिम दौर में है। महबूबा मुफ्ती आज चाहती हैं कि जो छोड़कर गए हैं, वे वापस लौटें, वही पहले कहती थीं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जा रहे हैं, वह पीडीपी और कश्मीरी अवाम के दुश्मन हैं। ऐसे में अब वे पीडीपी और अवाम के दुश्मनों को क्यों बुलाना चाहती हैं।

पीपुल्स कांफ्रेंस का हिस्सा बन चुके गुलमर्ग के पूर्व विधायक अब्बास वानी और पट्टन के पूर्व विधायक इमरान रजा अंसारी ने कहा कि हम तो वह किश्ती ही जला चुके हैं, जो वापस पीडीपी की तरफ लेकर जाती। पीडीपी में लौटने का सवाल ही नहीं है। वह महबूबा मुफ्ती और उनके चहेतों की जमात है। यदि आज पीडीपी कश्मीर में अपने वजूद के लिए लड़ रही है तो उसके लिए महबूबा मुफ्ती और उनके कुछ सलाहकार ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने हमेशा उन लोगों की उपेक्षा की, जो पीडीपी को कश्मीरी अवाम की जुबान बनाना चाहते थे।

जस्टिस पटनायक ने सीजेआइ मामले में और सूचनाएं मांगीं

रखी बात ▶ जुलाई में रिपोर्ट सौंपने की संभावनाओं से किया इन्कार

सुप्रीम कोर्ट में मनचाही पीठ फिक्स करने समेत विभिन्न अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं जस्टिस पटनायक

जस्टिस रंजन गोगोई

जस्टिस एके पटनायक (सभी फाइल)

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई को कथित रूप से फंसाने की बड़ी साजिश के आरोपों की जांच कर रहे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एके पटनायक ने खुफिया एजेंसियों-सीबीआइ, आइबी और दिल्ली पुलिस से कुछ और सूचनाएं मांगी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत में मनचाही पीठ फिक्स करने समेत अन्य अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए जस्टिस पटनायक को नियुक्त किया था। शीर्ष अदालत में जस्टिस गोगोई के खिलाफ अमर्यादित आचरण के आरोपों की सुनवाई के दौरान वकील उत्सव सिंह बैंस ने दावा किया था कि मनचाही पीठ फिक्स करने समेत शीर्ष अदालत में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां चल रही हैं।

अवकाश पर अपने गृहनगर ओडिशा के कटक गए जस्टिस पटनायक ने फोन पर कहा कि जांच में अभी कुछ और वक्त लगेगा, क्योंकि सच्चाई जानने के लिए उन्हें कुछ और दस्तावेज की पड़ताल करनी होगी। जुलाई में रिपोर्ट सौंपने की संभावनाओं से इन्कार करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक जो भी दस्तावेज मिले हैं उसका उन्होंने अध्ययन कर लिया है, लेकिन सच जानने के लिए उन्हें कुछ और दस्तावेज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जुलाई में जब वापस दिल्ली लौटेंगे तब दोबारा जांच शुरू करेंगे। जस्टिस पटनायक ने कहा, ' मुझे तीनों - सीबीआइ, आइबी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कुछ और सामग्री मंगानी होगी। क्योंकि उनसे जो दस्तावेज मिले हैं उनको देखने के बाद मुझे लगता है कुछ और सामग्री जरूरी है।' उन्होंने कहा, 'मुझे यह पता लगाना होगा कि मुझे क्या सुराग मिल रहे हैं। जो सुराग मिल रहे हैं उसके बारे में कोई पुष्टि है या नहीं। अगर कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो मुझे एक अलग दृष्टिकोण लेना होगा। यदि अधिक सामग्री आ रही है, तो मुझे मामले को आगे बढ़ाना होगा।'

हालांकि, उन्होंने आरोपों को लेकर अब तक की जानकारी के बारे में कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह मीडिया के सामने सबकुछ नहीं बता सकते, क्योंकि इससे जांच पर असर पड़ेगा। उन्हें बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। शीर्ष अदालत के पूर्व जज ने कहा कि उन्हें सच्चाई का पता लगाना है। जब तक वह सच्चाई का पता नहीं लगा लेते वह रिपोर्ट नहीं सौंप सकते हैं। काम पूरा करने के लिए और समय की जरूरत है।

जब मोदी की प्रतिमा निहारने लगे योगी...

लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में बाइकिंग क्वीन टीम (तुमेन बाइकर्स) ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा भेंट की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ प्रतिमा को कुछ पल तक मंत्रमुग्ध भाव से निहारते नजर आए। आदित्यनाथ ने बाइकिंग क्वीन टीम को 25 देशों की बाइक यात्रा पर रवाना किया। यह टीम यात्रा में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का संदेश देगी। रंगनाथ तिवारी

2022 की जंग के लिए संगठन के नए रथ पर होंगी प्रियंका

जितेंद्र शर्मा, लखनऊ

- बड़े बदलावों के साथ शुरू होगी विधानसभा चुनाव की मुहिम
- नए कार्यकर्ता तलाश कर बनाई जाएगी नई टीम, ग्रामीण क्षेत्रों में है चुनौती

लोकसभा चुनाव में उप्र से लगभग पूरी तरह साफ हो चुकी कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव के सहारे खड़ा होना चाहती है। राष्ट्रीय नेतृत्व से शुरू हुई बदलाव की हलचल अब जमीनी स्तर तक पहुंच चुकी है। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए न सिर्फ संगठन में जिला स्तर तक फेरबदल किया जाएगा, बल्कि कार्यकर्ताओं की नई टीम भी बूथ स्तर तक बनाई जाएगी।

आक्रामक तेवर और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के ग्लैमर के भरोसे कांग्रेस लोकसभा चुनाव के मैदान में थी। उप्र से खास उम्मीदें संजोते हुए ही पार्टी ने प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रभारी बनाकर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी। मगर, मोदी लहर इस तरह चली कि कांग्रेस का वजूद ही यहां से लगभग खत्म हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेठी की अपनी पारंपरिक सीट तक नहीं बचा सके। कांग्रेस सांसद के रूप में सिर्फ संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ही रायबरेली से जीत पाईं। इस करारी शिकस्त ने कांग्रेस को झकझोर कर रख दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। हालांकि कार्यकर्ता राहुल का ही नेतृत्व चाहते हैं। प्रदेशाध्यक्ष के इस्तीफे को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है लेकिन, यह तय है कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नई सेना के साथ उतरेगी।

पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के मुताबिक, सभी जिला इकाइयों सहित फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी बदले जाएंगे। महसूस किया गया है कि बूथ स्तर पर संगठन न होने की वजह से इतनी बड़ी हार हुई। फ्रंटल संगठन पूरी तरह निष्क्रिय रहे। अब संभवतः प्रियंका की अगुआई में ही संगठन को सक्रिय कर कांग्रेस मिशन यूपी में जुटेगी। पार्टीजनों का मानना है कि अगले तीन साल तक यदि संगठन पर काम किया जाए तो कांग्रेस के लिए वापसी के रास्ते बन सकते हैं। इसके लिए न सिर्फ निष्क्रिय पदाधिकारी बदलने की तैयारी है, बल्कि जहां संगठन खत्म हो चुका है, वहां नई टीम बनाई जाएगी। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में नए कार्यकर्ताओं की तलाश बड़ी चुनौती है। हालांकि, हाईकमान के निर्देशों के चलते समीक्षा या फैसलों पर अधिकृत रूप से बोलने को कोई पदाधिकारी तैयार नहीं है।

प्रियंका गांधी वाड्रा (फाइल)

नीतीश महागठबंधन में आएं तो ऐतराज नहीं : राबड़ी देवी

राज्य ब्यूरो, पटना

रघुवंश बाबू की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता : नीरज

राज्य ब्यूरो, पटना : राजद नेता प्रो. रघुवंश प्रसाद सिंह की ओर से जदयू के महागठबंधन में शामिल होने के आमंत्रण पर बिहार सरकार में सूचना एवं जन संपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि रघुवंश बाबू पराजय की पीड़ा कम करने के लिए कुछ बोल देते हैं। उनकी बातों को तो राजद के लोग भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। दूसरे दल के लोग क्यों उनकी बातों पर भरोसा करें। कहा कि एनडीए एकजुट है। राज्य में जदयू, भाजपा और लोजपा को जनता का समर्थन मिला हुआ है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति लंबी अवधि के बाद सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कोई सकारात्मक बात कही। राजनीतिक गलियारे में देर शाम राबड़ी देवी का यह वक्तव्य चर्चा में आ गया है। राबड़ी देवी ने कहा कि महागठबंधन में अगर फिर से नीतीश शामिल होते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह निर्णय महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को करना है।

वहीं, राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने दो कदम आगे बढ़ते हुए यह कहा डाला कि तेजस्वी ने लिखित रूप से थोड़े कह दिया है कि महागठबंधन के दरवाजे नीतीश के लिए बंद हो गए हैं। रघुवंश ने कहा कि भाजपा को पछाड़ने के लिए सभी को एक साथ आना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के इफ्तार में शामिल होकर लौटते समय राबड़ी ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में नीतीश के प्रति मुलायम रवैया अपनाया। वैसे इफ्तार में नीतीश के आने से पहले ही वे निकल गईं थीं। उधर रघुवंश ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए सभी गैर भाजपा दलों को एक मंच पर आने की जरूरत है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कभी कहा था कि महागठबंधन में जदयू के लिए दरवाजे बंद है, इस सवाल पर प्रो. सिंह ने कहा, ऐसी बातें चलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि राजद, हम, वीआइपी और अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलकर एक दल बना लेना चाहिए। बेशक, इस गोलबंदी में जदयू को भी शामिल होना चाहिए।

सलमान खुर्शीद ने कहा राहुल का इस्तीफा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कांग्रेस

हैदराबाद, प्रेट्र : राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के प्रस्ताव पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया तो कांग्रेस अध्यक्ष पद पर पैदा होने वाली रिक्तता की भरपाई मुश्किल होगी। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद 25 मई को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफे का प्रस्ताव रखा था।

खुर्शीद ने कहा, अगर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल बने रहते हैं तो पार्टी की वापसी के आसार बने रहेंगे। ऐसा उनका मानना है। राहुल अगर पद छोड़ने का अपना फैसला नहीं बदलते हैं तो वह कांग्रेस के लिए असहनीय होगा। राहुल ने कहा है कि वह अभी से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। पूर्व विदेश मंत्री ने कहा, पार्टी में संगठनात्मक रूप से बहुत काम करने की जरूरत है। अध्यक्ष के रूप में राहुल की मौजूदगी से यह काम बेहतर तरीके से हो पाएगा। उम्मीद है कि राहुल कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला रद कर देंगे। लेकिन अंततः राहुल जो फैसला करेंगे, वह (खुर्शीद) उसका सम्मान करेंगे। इससे पहले खुर्शीद कह चुके हैं कि नेहरू-गांधी परिवार कांग्रेस को एकजुट रखने के लिए जरूरी है।

भाजपा विधायक ने एनसीपी की महिला नेता को पीटा

राज्य ब्यूरो/प्रेट्र, अहमदाबाद

सोशल मीडिया पर वायरल हुई गुजरात की यह घटना, विधायक ने मांगी माफी

कारण बताओ नोटिस जारी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जीतूभाई वाघाणी ने घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए विधायक से स्पष्टीकरण देने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी।

दोनों पक्षों ने दंगा और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच करके उचित कार्रवाई करेगी।
-नीरज बडगूजर, पुलिस उपायुक्त

गुजरात के नरोदा में एनसीपी की महिला नेता की पिटाई करने के बाद उससे माफी मांगकर राखी बंधवाते भाजपा विधायक बलराम थवानी। एएनआइ

गुजरात के भाजपा विधायक बलराम थवानी और उनके साथियों ने पानी की समस्या लेकर आई एक महिला एनसीपी नेता की जमकर धुनाई कर दी। घटना से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हालांकि विधायक ने माफी मांग ली है, लेकिन कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विधायक के इस कृत्य की प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने भी निंदा की है।

महिला नेता नीतू तेजवानी ने बताया कि वह कुछ दिनों पहले क्षेत्र के पार्षद और भाजपा विधायक के भाई किशोर थवानी के पास गई थी और अपने क्षेत्र की पानी की आपूर्ति बंद नहीं करने का अनुरोध किया था। उसका दावा है कि उस समय भी उसे गालियां दी गई थीं और मारा गया था। नीतू ने कहा कि जब चार-पांच दिनों तक कार्रवाई नहीं हुई तो अन्य महिलाओं संग विधायक के मेघानी नगर इलाके में स्थित कार्यालय गई। उस समय विधायक वहां नहीं थे, लेकिन उनके समर्थकों ने उसे गालियां देनी शुरू कर दीं। महिला नेता ने कहा कि जब वे लोग किशोर थवानी के खिलाफ नारेबाजी कर रही थीं, तभी विधायक बलराम थवानी आए और मेरे हाथ से मोबाइल फोन छीनकर मुझे जोरदार तमाचा मारा जिससे मैं गिर पड़ी। महिला नेता ने कहा कि विधायक ने मेरे पेट पर जहां डंडे बरसाए, वहीं चेहरे पर जूता रखकर खड़े हो गए। जब उसके पति ने रोकने की कोशिश की तो उसे पीटना शुरू कर दिया।

पूरा वाकया सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विधायक ने इसके लिए माफी मांगी और दावा किया कि महिला और उसके साथियों ने उस पर पीछे से हमला किया था, इससे गुस्से में आकर उन्होंने महिला को लात मार दी थी। थवानी ने दावा किया कि वह महिला के घर माफी मांगने गए थे और महिला नेता ने उन्हें राखी बांधी और माफ कर दिया है।

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा, वीडियो वायरल होने के 12 घंटे बाद भी मुख्यमंत्री और पुलिस सब चुप हैं। उन्होंने सीएम से माफी मांगने की मांग की है। वहीं एनसीपी नेता जयंत बोस्की ने विधायक के निलंबन के साथ ही पार्टी से निष्कासन की मांग की है।

चुनौती

सबसे पहले विधानसभा के मानसून सत्र में बजट पारित कराने की है बड़ी चुनौती, उसके बाद सहकारी संस्थाओं, मंडी समितियों, नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव भी होने हैं

सालभर होगी कमलनाथ सरकार की अग्निपरीक्षा

वैभव श्रीधर, भोपाल

भले ही लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हों पर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की अग्निपरीक्षा सालभर होती रहेगी। सबसे पहली परीक्षा विधानसभा के मानसून सत्र में हो सकती है। इसमें सरकार को बजट पारित कराना है। भाजपा की कोशिश होगी कि उसमें ही सरकार को उलझाकर फ्लोर टेस्ट की नौबत ले लाए। इसके बाद शुरू होगा चुनावों का सिलसिला, पहले सहकारी संस्थाओं और फिर मंडी समिति के चुनाव होंगे। इनसे उबरने के बाद नगरीय निकाय के चुनावों का नंबर आएगा। इनके परिणाम आने के कुछ ही दिन बाद त्रिस्तरीय पंचायराज संस्थाओं के चुनाव का शंखनाद हो जाएगा।

विधानसभा में संख्या बल करना होगा साबित : सरकार की सबसे पहली चुनौती विधानसभा के मानसून सत्र में संख्या बल साबित करने की होगी। इस सत्र में सरकार वर्ष 2019-20 का बजट पारित कराएगी। इस दौरान विपक्ष मत विभाजन की मांग करके सरकार को बहुमत साबित करने पर विवश कर सकता है। यही वजह है कि सरकार ने विधायकों को साधने के

कमलनाथ (फाइल)

प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिला सरकार इसी कड़ी का हिस्सा है। इसमें प्रभारी मंत्रियों के अधिकार बढ़ेंगे और विधायकों की पूछ-परख बढ़ेगी। स्थानीय स्तर पर तबादले से लेकर छोटे-मोटे काम जिले में ही हो जाएंगे।

सहकारी संस्थाओं और मंडी समितियों के चुनाव : मानसून बीतने के बाद प्रदेश में सवा चार हजार प्राथमिक सहकारी समिति, 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के संचालक मंडल और अपेक्स बैंक के संचालक मंडल के चुनाव प्रस्तावित हैं। सहकारी समितियों के चुनाव यूं तो गैर दलीय आधार पर होते हैं पर इनमें राजनीतिक दलों का पूरा दखल रहता है। गांव-गांव में किसानों की प्रतिनिधि संस्था होने की वजह से मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच होगा। ऐसा ही मंडी समितियों के चुनाव में होगा। प्रदेश की 257 कृषि उपज मंडियों के चुनाव बीते एक साल से टाले जा रहे हैं। सरकार के पास बारिश के बाद चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

निकाय चुनाव में भाजपा-कांग्रेस होंगे आमने-सामने : साल के अंत में 16 नगर निगम सहित ढाई सौ से ज्यादा नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव होने हैं। ज्यादातर निकायों पर भाजपा पर कब्जा है। इसलिए सरकार के लिए निकाय चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहले दलीय आधार पर होने वाले चुनाव होंगे, इसलिए सियासी नजरिये से काफी अहम होंगे। नगरीय निकायों के बाद त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं (51 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत और 23 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायत) के चुनाव होंगे। अभी ज्यादातर जिला व जनपद पंचायत अध्यक्ष भाजपा समर्थक हैं। सरकार के लिए चुनौती होगी कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की पहुंच बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं में पार्टी के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जितवाए।

झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर हम लड़ेंगे : हेमंत

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव विपक्षी महागठबंधन के सारे दल मिलकर लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने प्रत्याशी उतारेगा। सोमवार को झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास पर केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बाबत फैसला हुआ। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया था। पूर्व में ही इस बाबत बात हुई थी कि विधानसभा चुनाव झामुमो के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में होगा। साथी दलों के साथ बैठकर इस माह के अंत तक सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया जाएगा। पहले से ही इस बाबत फ्रेमवर्क हो चुका है। हेमंत ने यह भी कहा कि वे विपक्षी महागठबंधन में वामदलों को भी शामिल किए जाने के पक्षधर हैं। इस मसले पर भी समान विचारधारा वाले दलों संग बातचीत की जाएगी। आगे की रणनीति तैयार करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक 15-16 जून को दुमका में होगी।

छत्तीसगढ़ में माननीयों के लिए अब भी बची है कुर्सी की उम्मीद

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने निगम-मंडल के पदों से विधायकों का पत्ता भले ही काट दिया है, लेकिन न केवल विधायकों, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी संतुष्ट करने के लिए पार्टी के पास लगभग 800 पद खाली पड़े हैं। पार्टी सूत्रों की मानें तो सरकार और पार्टी नेतृत्व चाहेगा कि इन सभी पदों को नगरीय निकायों के चुनाव से पहले भर दिया जाए, ताकि अच्छा काम करने वाले नेता-कार्यकर्ता स्थानीय चुनाव में भी अच्छा परफॉर्मेंस दें। हालांकि, इन पदों पर नियुक्ति बड़ी चुनौती है, क्योंकि पद के अनुपात में दावेदार कहीं ज्यादा हैं।

12 से 13 विधायक बनाए जा सकते हैं संसदीय सचिव : पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में 11 विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर उन्हें मंत्री पद का दर्जा दिया गया था। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने इस का विरोध किया था। मौजूदा परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर इसके खिलाफ कोर्ट तक गए थे। कोर्ट ने आदेश दिया था कि संसदीय सचिव बने रहेंगे, लेकिन उन्हें अधिकार और अतिरिक्त सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इसी आदेश के आधार पर कांग्रेस भी संसदीय सचिवों की नियुक्ति करेगी। पार्टी के 68 विधायकों में से मुख्यमंत्री और 11 मंत्रियों को छोड़ दिया जाए, तो 56 विधायक संसदीय सचिव बनने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सरकार 12 या 13 संसदीय सचिव बना सकती है। वहीं, मंत्रिमंडल में भी एक पद खाली है। वरिष्ठ विधायक उसके लिए भी लॉबिंग करेंगे।

छह माह के लिए कार्यकर्ता बनेंगे नामांकित पार्षद : सरकार के 126 निगम-मंडल और प्राधिकरणों में विधायकों की दावेदारी खत्म होने के बाद कार्यकर्ताओं के लिए 300 पदों का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया का कहना है कि जल्द ही सभी 168 नगरीय निकायों में नामांकित पार्षद (एल्डरमैन) का मनोनयन होगा। नगर निगम में न्यूनतम आठ, नगर पालिका में न्यूनतम पांच और नगर पंचायतों में न्यूनतम तीन एल्डरमैन बनाने का प्रावधान है।

19 जून से हरिद्वार से भारत दर्शन रेल सेवा शुरू करेगा रेलवे। देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराने के बाद दस दिनों की यात्रा 28 जून को हरिद्वार में ही होगी संपन्न। इसके लिए प्रति व्यक्ति 9450 रुपये किराया तय किया गया है।

आदतन दुष्कर्मियों के लिए फांसी की सजा सही : कोर्ट

शक्ति मिल दुष्कर्म केस ▸ बांबे हाई कोर्ट ने दोषियों की याचिका खारिज की

तीनों ने आइपीसी की धारा 376 (ई) की संवैधानिक वैधता को दी थी चुनौती

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने सोमवार को भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की संशोधित धारा 376 (ई) की संवैधानिक वैधता को सही ठहराया, जिसके तहत बार-बार दुष्कर्म करने वालों (आदतन दुष्कर्मियों) को उम्रकैद या फांसी की सजा दी जा सकती है। 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के बाद आइपीसी की इस धारा में संशोधन किया गया था।

जस्टिस बीपी धर्माधिकारी और रेवती मोहिते डेरे की खंडपीठ ने 2013 के सनसनीखेज शक्ति मिल सामूहिक दुष्कर्म मामले के तीन दोषियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया। तीनों ने धारा 376 (ई) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, जिसके तहत 2014 में सत्र अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी।

सेंट्रल मुंबई स्थित बंद पड़ी शक्ति मिल के परिसर में तीनों-विजय जाधव, कासिम बंगाली और सलीम अंसारी ने 22 अगस्त, 2013 को 22 वर्षीय फोटो पत्रकार से सामूहिक दुष्कर्म किया था। जबकि, 31 जुलाई, 2013 को इसी मिल परिसर में तीनों ने 18 साल की एक टेलीफोन ऑपरेटर से सामूहिक दुष्कर्म किया था। इन तीनों के अलावा इस मामले में अदालत ने सिराज खान को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि एक नाबालिग को सुधार गृह में भेजा था।

बांबे हाई कोर्ट (फाइल)

खंडपीठ ने कहा, 'हमारा मानना है कि आइपीसी की धारा 376 (ई) से संविधान का उल्लंघन नहीं होता और इसलिए इस मामले में इसे हटाने की जरूरत नहीं है।' केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत से कहा कि बहुत विचार-विमर्श और चर्चा के बाद कानून में संशोधन किया गया था और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 के जरिये पेश कोई भी प्रावधान असंवैधानिक नहीं था। खंडपीठ के इस फैसले के बाद अब हाई कोर्ट की दूसरी पीठ के सामने दोषियों की दूसरी याचिका पर सुनवाई होगी। इस याचिका में तीनों ने सत्र अदालत के फांसी की सजा देने के फैसले को चुनौती दी है। इनकी सजा को बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार ने भी याचिका दायर की है।

कठुआ दुष्कर्म मामले की सुनवाई पूरी फैसला 10 को

जासं, पठानकोट : जम्मू-कश्मीर के कठुआ में दुष्कर्म व हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय में एक साल से चल रही सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई। न्यायाधीश डॉ. तेजविंदर सिंह 10 जून को फैसला सुनाएंगे।

राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहे इस मामले के सांप्रदायिक रूप लेने पर केस को जम्मू-कश्मीर से पंजाब के पठानकोट स्थानांतरित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष न्यायाधीश ने पिछले एक साल से लगातार सुनवाई की। सोमवार सुबह करीब 11 बजे सातों आरोपितों विशाल जगोत्रा, एसपीओ सुरेंद्र कुमार, दीपक खजूरिया, सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, सांझी राम, कांस्टेबल तिलक राज और प्रवेश कुमार को गुरदासपुर जेल से कड़ी सुरक्षा में अदालत ले जाया गया। आखिरी दिन चार घंटे तक बहस हुई। बचाव पक्ष के वकील अंकुर शर्मा ने बताया कि बहस पूरी हो चुकी है। अदालत 10 जून को फैसला सुनाएगी। अगर कोई दस्तावेज छूट गया है तो मंगलवार को रिवर्टल होगा। हालांकि अभियोजन का कहना है कि न्यायाधीश छह जून को फैसले की तारीख बताएंगे।

ग्वालियर के कलेक्टर की अनूठी शर्त, हथियार चाहिए तो हरियाली बढ़ाइए

नईदुनिया, ग्वालियर : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए अनूठी शर्त का आदेश कलेक्टर अनुराग चौधरी ने लागू किया है। इसके तहत शस्त्र लाइसेंस के लिए आए आवेदन को स्वीकृति तभी मिलेगी, जब आवेदक एक महीने में 10 पौधे लगाएगा। इन पौधों की जांच पटवारी करेगा। आवेदक को पौधों संग ली गई सेल्फी भी आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

जिले में हरियाली बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन ने हथियार लाइसेंस में पौधरोपण की अनिवार्यता की शर्त जोड़ दी है। आवेदक को 10 पौधे लगाने होंगे और एक माह तक इनकी देखरेख के बाद इनके संग ली गई सेल्फी आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। इसके बाद जिला प्रशासन वेरीफिकेशन कराएगा, तब लाइसेंस की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही जिले में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में और भी प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में कलेक्टर चौधरी ने जौरासी की पहाड़ी पर 700 पौधे लगवाए हैं। वहीं, शहर में एक प्रतिशत फॉरेस्ट ग्रीनरी बढ़ाने का निर्णय भी कलेक्टर ने लिया है।

जिले में 28 हजार से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस : ग्वालियर जिले में 28 हजार से ज्यादा लाइसेंसी हथियार हैं, जिनमें से करीब 3000 पिस्टल-रिवॉल्वर के हैं। जिले के मुरार क्षेत्र में सबसे ज्यादा लाइसेंसधारी हैं।

अब शस्त्र लाइसेंस तभी जारी होगा, जब आवेदक 10 पौधे लगाएगा। इसके साथ ही एक माह तक उनकी देखभाल कर उनकी फोटो दिखाएगा। फोटो व पटवारी के माध्यम से सत्यापन भी किया जाएगा। यह शर्त हर किसी के लिए होगी।

अनुराग चौधरी, कलेक्टर, ग्वालियर

राम मंदिर निर्माण के लिए अब नहीं करनी पड़ेगी और प्रतीक्षा : चंपत राय

जागरण संवाददाता, अयोध्या

राम मंदिर निर्माण के लिए अब और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने सोमवार को मणिरामदास जी की छावनी में संतों की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मध्यस्थता से हल करने के प्रयासों को आड़े हाथों लिया। कहा कि रामजन्मभूमि या किसी की भी जन्मभूमि की अदला-बदली नहीं हो सकती। यदि, दूसरा पक्ष कोई मस्जिद चाहता है तो वह ऐसी जगह बने कि पीढ़ी दर पीढ़ी विवाद का कारण न बने। उन्होंने स्पष्ट किया कि अयोध्या विवाद के समाधान के लिए गठित मध्यस्थता पैनल की भूमिका पक्षकारों का पक्ष जानकर सुप्रीम कोर्ट को राय देने तक है, फैसला तो कोर्ट को ही देना है। इस बीच विहिप उपाध्यक्ष ने राममंदिर पर दावेदारी को लेकर सफाई भी दी। कहा, राम मंदिर बनने पर विहिप की ओर से कोई पुजारी नहीं होगा, न ही मंदिर की भूमि पर उसका कोई दावा होगा। उस जमीन के मालिक तो भगवान राम ही होंगे और विहिप की भूमिका सिर्फ मंदिर की लड़ाई लड़ने तक है।

इससे पूर्व संतों के उद्‌बोधन से राममंदिर निर्माण के प्रति उनकी बेसब्री झलकी। तय हुआ कि संत प्रधानमंत्री से भेंटकर उन्हें अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे। भाजपा के सह मीडिया प्रभारी आकाशमणि ने कहा कि मंदिर निर्माण की भावना से प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा अभिसिंचित है और अब यह फलीभूत होने को है। अध्यक्षता रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास ने की। बैठक सोमवार देर शाम तक चली। इस मौके पर महंत सत्येंद्र दास, आचार्य वरुण दास, अंतर्राष्ट्रीय संगठनमंत्री दिनेशचंद्र, केंद्रीय सलाहकार पुरुषोत्तम नारायण सिंह, रामलला के सखा त्रिलोकीनाथ पांडेय, विहिप प्रवक्ता शरद शर्मा, चरनजीत सिंह आदि मौजूद रहे।

15 जून को संत भरेंगे हुंकार : रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष मणिरामदास जी की छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास के सात दिवसीय जन्मोत्सव समारोह के समापन अवसर पर 15 जून को संत मंदिर निर्माण के लिए हुंकार भरेंगे। हालांकि, इस दिन आयोजित होने वाली धर्म संसद से पहले सोमवार को संतों की बैठक के दौरान महंत नृत्य गोपाल दास ने भरोसा जताया कि इस सरकार में राममंदिर का निर्माण सुनिश्चित होगा।

राम मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या स्थित मणिरामदास जी की छावनी में विमर्श करते संत। जागरण

राम मंदिर मुद्दा गरमाएंगे दंडी संन्यासी

शरद द्विवेदी, प्रयागराज : केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की दोबारा ताजपोशी होते ही श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण का मामला गरमाने लगा है। सरकार राम मंदिर निर्माण मसले को दरकिनार न करे, उसके लिए संत-महात्मा सक्रियता बढ़ाने लगे हैं। राम मंदिर मुद्दे पर अभी तक मौन रहने वाले दंडी संन्यासी भी मुखर हो गए हैं। अखिल भारतीय दंडी संन्यासी प्रबंधन समिति ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राम मंदिर मुद्दे पर मिलने का समय मांगा है। प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलकर मंदिर निर्माण को लेकर किए गए प्रयासों की जानकारी लेकर अपना सुझाव देगा।

सर्च ऑपरेशन में नंदा देवी चोटी पर दिखे पांच शव

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़

▸ वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सर्च अभियान पर निकले दल ने खींचे फोटो

▸ रेस्क्यू कर लाए गए दो विदेशी पर्वतारोही भी खोजबीन दल में शामिल रहे

जिला प्रशासन ने नंदा देवी चोटी आरोहण के दौरान लापता हुए पर्वतारोहियों की तलाश अभियान में सोमवार को सफलता मिलने का दावा किया है। बताया कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर से की गई सर्च में चोटी पर पांच शव देखे गए। शव लापता आठ सदस्यीय पर्वतारोही दल में शामिल सदस्यों के होने का अंदेशा जताया जा रहा है। रेस्क्यू पूरा होने पर ही असलियत सामने आ पाएगी। सेना व आइटीबीपी के साथ मिलकर शवों को चोटी से निकालने के लिए रणनीति पर विचार किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने केंद्र और राज्य सरकार से इस संबंध में दिशा निर्देश मांगे हैं।

रविवार को रेस्क्यू कर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ लाए गए चार पर्वतारोहियों में से दो जैचरे क्वेन और मार्क थॉमस को साथ लेकर वायु सेना के हेलीकॉप्टर से सोमवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एवलांच वाले इलाके में पांच शव नजर आए। हेलीकॉप्टर से ही इन शवों के फोटो लिए गए। अधिक दूरी से फोटो लिए जाने के कारण मृतकों की पहचान नहीं हो पा रही है। आशंका है कि शव लापता पर्वतारोहियों के हो सकते हैं।

इधर, शवों की फोटो और अन्य जानकारियों के बाद जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सेना और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक की। नंदा देवी चोटी पर पड़े इन शवों को निकालने के लिए विचार विमर्श कर रणनीति तय की गई। जिलाधिकारी ने केंद्र और राज्य सरकार को पूरे मामले की जानकारी देकर आवश्यक दिशा निर्देश मांगे हैं। डीएम जोगदंडे का कहना है कि शवों को बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण है। वहां भेजी जाने वाली टीम की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जरूरी है।

आठ पर्वतारोही हैं लापता : नंदा देवी ईस्ट को फतह करने के लिए ब्रिटेन , अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के पर्वतारोहियों का 12 सदस्यीय दल दिल्ली से रवाना हुआ था। इनमें लाइजन ऑफिसर के रूप में अल्मोड़ा निवासी चेतन पांडेय भी शामिल हैं। 26 मई को नंदा देवी क्षेत्र में आए भारी एवलांच के चलते पर्वतारोही लापता हो गए थे। इनमें से चार बेस कैंप में थे, उन्हें रविवार को वायुसेना की टीम ने रेस्क्यू कर लिया था। अन्य आठ का कोई पता नहीं चल पाया है। इनमें ब्रिटेन के चार, अमेरिका के दो और आस्ट्रेलिया के एक पर्वतारोही के साथ ही भारतीय पर्वतारोहण संस्थान का एक लाइजन अफसर शामिल है। यह अभियान हिमालयन एन एंड ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड ने आयोजित किया था।

पिथौरागढ़ से सोमवार को नंदा देवी चोटी आरोहण में लापता हुए सात विदेशी समेत आठ पर्वतारोहियों की वायुसेना के हेलीकॉप्टर से तलाश की गई। जागरण

तमिलनाडु सरकार ने कर्मचारियों के लिए तय किया ड्रेस कोड

चेन्नई, एएनआइ : तमिलनाडु सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया है। इसके मुताबिक उन्हें तमिल संस्कृति या किसी भारतीय पारंपरिक पोशाक में कार्यालय आना होगा। महिलाओं को जहां सादे रंग की साड़ी, सलवार-कमीज, कुर्ते के साथ चूड़ीदार पायजामा के साथ दुपट्टा पहनना होगा, वहीं पुरुषों को पैंट-शर्ट में आना होगा। जींस-टीशर्ट आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रमुख सचिव गिरिजा वैद्यनाथन के दस्तखत से जारी यह आदेश कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने 28 मई को जारी किया। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई पुरुष अधिकारी किसी अदालत या ट्रिब्यूनल के सामने पेश होता है तो उसे पैंट-शर्ट के साथ बंद गले का कोट पहनना होगा। अगर वह खुला कोट पहनता है तो उसे टाई पहननी होगी और इनके साथ पहने जाने वाला पैंट-शर्ट सादे रंग का होना चाहिए। अगर कोई महिला ट्रिब्यूनल के सामने पेश होती है तो उसे साड़ी या फिर दुपट्टे के साथ सलवार-कमीज, कुर्ता-चूड़ीदार पायजामा पहनना होगा।

लोकसभा अध्यक्ष की दौड़ में मेनका, राधा मोहन और वीरेंद्र

▸ संभावित उम्मीदवारों में जुएल ओराम और एसएस अहलूवालिया का नाम भी शामिल

▸ कटक से सांसद भृर्तुहरि महताब के नाम पर भी हो रहा विचार

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, राधामोहन सिंह और वीरेंद्र कुमार सहित कई वरिष्ठ नेताओं को इस पद की दौड़ में शामिल माना जा रहा है। संभावित उम्मीदवारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम एवं एसएस अहलूवालिया के भी नाम शामिल हैं। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

आठ बार की सांसद मेनका गांधी भाजपा की सबसे अनुभवी लोकसभा सदस्य हैं और वह अध्यक्ष पद के लिए स्वाभाविक विकल्प हैं। 17वीं लोकसभा में सबसे अनुभवी सांसद होने से उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष चुना जा सकता है। राधामोहन सिंह भी छह बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं और उन्हें भी अध्यक्ष पद के लिए एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सिंह की संगठन पर गहरी पकड़ है तथा उनकी छवि विनम्र एवं सबको साथ लेकर चलने वाले नेता की है। सूत्रों के मुताबिक वीरेंद्र कुमार भी छह बार के सांसद हैं और उनकी दलित छवि उनके पक्ष में काम कर सकती है।

अहलुवालिया पिछली सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री थे और विधायी मामलों में उनकी जानकारी के कारण वह विख्यात हैं। भाजपा नेताओं के एक वर्ग का मानना है कि पार्टी नेतृत्व दक्षिण भारत से किसी नेता का चयन कर सबको हैरत में डाल सकता है। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद बीजू जनता दल (बीजद) को इस बार दिया जा सकता है और कटक से सांसद भृर्तुहरि महताब का नाम इस पद के लिए विचार किया जा रहा है। महताब को 2017 में सर्वोत्तम सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 16वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष पद पर अन्नाद्रमुक के एम थंबी दुरई को आसीन किया गया था।

वाड्रा अमेरिका व नीदरलैंड में करा सकेंगे इलाज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ विशेष अदालत ने छह सप्ताह के लिए विदेश जाने की दी सशर्त मंजूरी

▸ बड़ी आंत में ट्यूमर से पीड़ित वाड्रा को लेनी है चिकित्सकीय सलाह

मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित और संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को विशेष अदालत ने चिकित्सकीय आधार पर छह सप्ताह के लिए अमेरिका और नीदरलैंड जाने की अनुमति दे दी है।

राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने वाड्रा पर कई पाबंदियां भी लगाई हैं। वाड्रा ने अपनी अर्जी में कहा था कि वह लंदन में अपना इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विरोध के बाद उन्होंने अपनी बात वापस ले ली। इसके बाद उन्हें अमेरिका और नीदरलैंड जाने की अनुमति दी गई।

विशेष अदालत ने वाड्रा से कहा कि वह जहां रहेंगे, वहां का पता और फोन नंबर जाने से पहले अदालत को बताएंगे। 25 लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा कराएं और भारत वापस आने के बाद 24 घंटे के भीतर अदालत को सूचित करें। वह न तो जांच को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और न ही किसी भी गवाह को बहकाने का प्रयास करेंगे।

रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी आंत में ट्यूमर है। सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें दूसरी जगह से भी सलाह लेने को कहा था। इस कारण उन्होंने लंदन जाने की अनुमति मांगी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में कहा कि लंदन में ही वाड्रा की विवादित संपत्ति की जांच चल रही है। इलाज के लिए लंदन जाना सिर्फ बहाना है। वाड्रा के वकीलों की दलील थी कि जांच एजेंसी चाहे तो चुनिंदा जगहों पर जाने की पाबंदी लगा सकती है और वाड्रा वहां नहीं जाएंगे। बाद में लंदन के बजाय किसी अन्य देश की दलील को अदालत ने मंजूर कर लिया। ईडी के मुताबिक वाड्रा की लंदन में कुछ संपत्ति है, जो जांच के घेरे मे है। यह संपत्ति हथियार डीलर संजय भंडारी से खरीदी गई है।

रॉबर्ट वाड्रा (फाइल)

वाड्रा को ईडी से फिर समन जारी

नई दिल्ली, एएनआइ : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को मंगलवार को हाजिर होने के लिए कहा है। जांच एजेंसी ने उन्हें दिल्ली एनसीआर, बीकानेर में कथित भूमि कब्जा और विदेश में संपत्ति से संबंधित मामले में पूछताछ के लिए समन किया है। 30 मई को भी वाड्रा इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने हाजिर हुए थे। इसी दिन उन्होंने कहा था कि झूठे आरोपों से अपना नाम बाहर आने तक वह सभी सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले हर समन का पालन करेंगे।

अपने फेसबुक पोस्ट में वाड्रा ने कहा था, 'अभी तक मैं 11 बार पेश हो चुका हूं और करीब 70 घंटे पूछताछ हो चुकी है। भविष्य में भी मैं हमेशा की तरह सहयोग करता रहूंगा। जबतक मेरा नाम सभी झूठे आरोपों से मुक्त नहीं हो जाता तबतक मैं ऐसा करता रहूंगा। मैं भारतीय न्यायपालिका में भरोसा करता रहूंगा।'

सोमवती अमावस्या पर गंगा में लाखों ने लगाई डुबकी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार

सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार और ऋषिकेश में पुण्य की डुबकी लगाई। तड़के चार बजे से ही हरकी पैड़ी समेत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देर शाम तक घाटों पर स्नान का क्रम चलता रहा। हरिद्वार के जिला प्रशासन ने दावा किया कि शाम चार बजे तक 40 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके थे। इसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक के साथ ही संवेदनशील स्थानों पर पुलिस तैनात रही। इसके बावजूद शहर पूरी तरह पैक रहे और जाम ने यात्रियों को पसीना-पसीना कर दिया।

हरिद्वार में उमड़े आस्था के इस सैलाब ने 2010 के कुंभ की याद ताजा कर दी। भीड़ ने सारे अनुमान धराशायी कर दिए। रविवार से ही श्रद्धालुओं का हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। रविवार रात को इसमें और तेजी आई। गंगा मैया के जयकारों के साथ सुबह चार बजे से ही हरकी पैड़ी, सर्वानंद घाट, कुशावर्त घाट, मालवीय घाट, बिरला घाट, अलकनंदा घाट और प्रेम नगर आश्रम समेत विभिन्न घाटों पर पुण्य की डुबकियां लगनी शुरू हो गईं। श्रद्धालुओं ने गंगा पूजन के साथ सूर्य को अर्घ्य देकर दान भी किया। सनातनी मान्यता के अनुसार अमावस्या पर पितृों के निमित्त कर्मकांड भी किए गए। सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु नारायणी शिला और कुशावर्त घाट पर उमड़े। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट, मुनि की रेती, लक्ष्मण झूला और स्वर्ग आश्रम में गंगा तटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचने से शहरों में जाम की स्थिति पैदा हो गई।

हरिद्वार में सोमवार को सोमवती अमावस्या पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। धर्मनगरी में हरकी पैड़ी समेत अन्य स्नान घाट में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। जागरण

पहल

प्रवासी भारतीयों को जड़ें खोजने में मदद करेगा पर्यटन विभाग

उत्तराखंड सरकार ने बनाई योजना, हरिद्वार, बदरीनाथ, केदारनाथ में पंडों का लिया जाएगा सहयोग, मॉरीशस के लोगों से की जाएगी इसकी शुरुआत

राज्य ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड पर्यटन विभाग अब प्रवासी भारतीयों की भारत में उनकी जड़ों को खोजने में मदद करेगा। इसकी शुरुआत फिलहाल मॉरीशस में बसे अप्रवासी भारतीयों से की जा रही है। मॉरीशस दूतावास इच्छुक लोगों अपने पूवर्जों के नाम व गांव आदि की जानकारी यहां भेजेगा। हरिद्वार, बदरीनाथ और केदारनाथ में सैकड़ों सालों से बन रही बही में इन्हें तलाशा जाएगा। उम्मीद जताई जा रही कि ऐसे में कई अप्रवासियों को उनकी जड़ें यानी भारत में उनके मूल निवास स्थान के संबंध में जानकारी मिल सकेगी।

सोमवार को विधानसभा में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और मारीशस के उच्चायुक्त जगदीश्वर गोवर्द्धन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी साझा की। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पुरातन काल से लोग हरिद्वार, बदरीनाथ व केदारनाथ आते रहे हैं। यहां पंडों द्वारा बनाई जाने वाली पोथियों में इन यात्रियों के नाम दर्ज होते हैं। ऐसे में यदि कोई अपने पूर्वजों अथवा गांव के नाम जानते होंगे तो वह यहां आकर इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि मॉरीशस स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में भारत से मॉरीशस गए सभी लोगों के रिकॉर्ड हैं। मॉरीशस से ये रिकॉर्ड भारत मंगाए जाएंगे ताकि इन स्थानों पर लोग अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी हासिल कर अपनी जड़ों के बारे में भी जान सकें।

इस दौरान मॉरीशस के उच्चायुक्त जगदीश्वर गोवर्द्धन ने बताया कि उनका देश जल्द ही उत्तराखंड पर्यटन विभाग से एक करार पर हस्ताक्षर करेगा। इसके तहत मॉरीशस से भारत आने वाले तीर्थ यात्रियों को पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस में छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा साहसिक पर्यटन, आर्थिक व सांस्कृतिक विरासत का आदान-प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मॉरीशस भी उत्तराखंड से आने वाले यात्रियों को इसी तरह की छूट देगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि अभी करार के मसौदे का अध्ययन किया जाएगा और फिर इसके बाद करार को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसी माह मॉरीशस से 80 लोग भारत आए थे और अब सितंबर में 200 लोगों का एक दल फिर भारत व उत्तराखंड भ्रमण पर आएगा। उन्होंने कहा कि मॉरीशस के अलावा उत्तराखंड बाली, सूरीनाम, फिजी व त्रिनिदाद आदि अन्य ऐसे देशों से जहां भारतीय प्रवासी हैं, उनके साथ करार कर उनके पूर्वजों को ढूंढने में भी मदद करेगा।

कण्वाश्रम को विकसित करने को मिले 20 करोड़ रुपये : पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि चक्रवर्ती सम्राट भरत की कोटद्वार स्थित जन्मस्थली को विकसित करने के लिए केंद्र ने 20 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत यहां महाराज भरत की विशाल प्रतिमा और वैदिक गांव का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द यह कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

चारधाम को प्राचीनतम यात्रा मार्ग घोषित करने की तैयारी

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटन विभाग चारधाम यात्रा मार्ग को प्राचीनतम यात्रा मार्ग के रूप में प्रचारित और घोषित करवाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसके लिए आमजन का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके तहत जिसके पास भी ऐसे दस्तावेज, फोटोग्राफ अथवा पांडुलिपि हों, जिसमें इस मार्ग का जिक्र हो वह पर्यटन विभाग को उपलब्ध करा सकता है। इसके लिए विभाग द्वारा उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा।

सतपाल महाराज (फाइल)

कोटे की दुकानों से अतिरिक्त चीनी व अनाज देने पर विचार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार कोटे की दुकानों (पीडीएस) से 16.3 करोड़ लोगों को रियायती दर पर एक किलोग्राम अतिरिक्त चीनी देने की योजना बना रही है। इससे सरकारी खजाने पर 4,727 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। यही नहीं मानसून से पहले सरकारी गोदामों को खाली करने के लिए लोगों को अतिरिक्त अनाज देने पर भी विचार किया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक सरकार के गठन के बाद पिछले हफ्ते हुई कैबिनेट की पहली बैठक में लोगों को अतिरिक्त चीनी देने के खाद्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया था। सरकार ने मंत्रालय से पीडीएस के जरिए लोगों को चीनी के साथ ही अतिरिक्त अनाज (गेहूं या चावल) भी देने पर विचार कर नया प्रस्ताव बनाने को कहा था। फिलहाल, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाइ) के तहत 2.5 करोड़ परिवारों को 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी मुहैया कराई जाती है। मंत्रालय ने 16.29 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थी परिवारों को एक किलोग्राम चीनी मुहैया कराने का प्रस्ताव बनाया है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय एक या दो किलोग्राम अनाज देने पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार हर महीने 80 करोड़ लोगों को रियायती दरों पर पांच किलोग्राम अनाज मुहैया कराती है।

कार्डधारकों को अतिरिक्त अनाज देने पर विचार इसलिए किया जा रहा है, ताकि सरकारी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के गोदामों को बरसात से पहले खाली कराया जा सके। एफसीआइ के गोदाम अनाज से अटे पड़े हैं, यहां तक कि खुले में भी अनाज रखे गए हैं।

केरल में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के पांच जून तक पहुंचने का अनुमान है। इसको देखते हुए एफसीआइ की चिंता बढ़ गई है और वह बड़े ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा अनाज देने लगी है। लेकिन खुले बाजार में कम कीमत पर अनाज उपलब्ध होने से व्यापारी एफसीआइ से अनाज खरीदना नहीं चाहते।

न्यूज गैलरी

दरार मिलने पर एयर इंडिया के विमान को उड़ान भरने से रोका

नई दिल्ली : एयर इंडिया के बोइंग 777 विमान में उसके प्रवेश द्वार के दाहिने कोने के नीचे छोटा सा दरार पाए जाने के बाद उसे उड़ान भरने से रोक दिया गया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर विमान के लैंड होने के बाद दरार पाया गया। एयर इंडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी राष्ट्रीय विमान कंपनी कहा है कि कुल 210 यात्रियों में से 100 के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ये यात्री इसी विमान से लौटने वाले थे। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, 'बी 777 विमान वीटी-एएलएच सैन फ्रांसिस्को पहुंचा। निरीक्षण के दौरान प्रवेश द्वार दो के दाहिने कोने के निचले हिस्से में एक छोटा सा दरार पाया गया। (प्रेट्र)

राजस्थान में सरकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में चल गई पोर्न क्लिप

जयपुर : राजस्थान के शासन सचिवालय में सोमवार को एक सरकारी बैठक में अजीब स्थिति बन गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हो रही इस बैठक में अचानक एक पोर्न क्लिप चल गई और बैठक में शामिल सभी लोग असहज हो गए। सचिवालय में सोमवार को खाद्य विभाग के रसद अधिकारियों की बैठक थी और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सभी जिलों के अधिकारी जुड़े हुए थे। इसी दौरान एक पोर्न क्लिप प्ले हो गई। बैठक में विभाग की प्रमुख सचिव मुग्धा सिन्हा भी मौजूद थी। विभाग की ओर से महानिदेशक एनआईसी को जांच के लिए लिखा गया है। (जासं)

कश्मीर में मुठभेड़, ओजीडब्ल्यू और एक आतंकी हुआ ढेर

आतंक पर अंकुश ▸ नाका तोड़ भाग रहे थे आतंकी, एक हुआ फरार

कुलगाम में हिंसक तत्वों पर बल प्रयोग, दो लोग जख्मी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

दक्षिण कश्मीर स्थित शोपियां के चित्रीगाम में रविवार मध्य रात्रि नाका तोड़ भाग रहे आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। वहीं, उनका एक साथी बचकर भाग निकला। इस घटना के बाद कुलगाम और शोपियां में पैदा तनाव को देख प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। इसी बीच, तरीगाम, कुलगाम में हिंसक तत्वों को काबू करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। झड़पों में दो लोग जख्मी हो गए।

यह मुठभेड़ रविवार आधी रात के बाद शोपियां के मुलु चित्रीगाम से तुरकवांगन को ओर जाने वाले मार्ग पर हुई। सेना की 44 आरआर के जवानों ने नाका लगाया हुआ था। इस दौरान टवेरा वाहन को देख जवानों ने उसे रुकने का संकेत किया। लेकिन चालक वाहन की गति तेज करते हुए नाका तोड़ा भागने लगे। इस दौरान वाहन में सवार आतंकियों ने जवानों पर गोली भी चलाई। नाका पार्टी ने जवाबी फायर किया। इसमें टवेरा में सवार एक आतंकी और चालक मारे गए। जबकि एक अन्य आतंकी निकटवर्ती खेतों में भाग निकला। मारे गए आतंकी की पहचान फिरदौस अहमद बट पुत्र मोहम्मद जमाल बट निवासी पोनिवा कुलगाम के रूप में हुई है। वह अप्रैल के पहले हफ्ते में लापता हुआ था। बताया जाता है कि वह लश्कर में सक्रिय हुआ था। वहीं, टवेरा चालक का नाम सज्जाद अहमद डार पुत्र गुलाम हसन डार निवासी वामपोरा कुलगाम के रूप में हुई है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मारा गया आतंकी फिरदौस एक सूचीबद्ध आतंकी था। सज्जाद अहमद उसका ओवरग्राउंड वर्कर था। दोनों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों के हवाले कर दिए हैं।

मुठभेड़ के बाद पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त कार्यदल ने तरीगाम में तलाशी अभियान चलाया। जवानों को घेराबंदी करते देख बड़ी संख्या में स्थानीय युवक घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने जिहादी नारे लगाते हुए सुरक्षाबलों पर पथराव शुरू कर दिया। सुरक्षाबलों की बार-बार चेतावनी देने के बावजूद जब हिंसक तत्व शांत नहीं हुए तो जवानों ने भी लाठियों और आंसूगैस का सहारा लेकर उन्हें खदेड़ा।

दो आतंकियों के दिखने का वीडियो वायरल

बलबीर सिंह जम्वाल, किश्तवाड़

सोशल मीडिया पर दो आतंकियों के दिखने का वीडियो वायरल होने से लोग दहशत में हैं। गुप्तचर एजेंसियों ने क्षेत्र में फिर से आतंकियों के सक्रिय होने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर के गुप्तचर विभाग ने किश्तवाड़ पुलिस व अन्य सुरक्षाबलों को पत्र लिखकर अलर्ट कर दिया है। गुप्तचर एजेंसियों ने अपने अधिकारियों को जानकारी दी है कि दो आतंकी किश्तवाड़ शहर में प्रवेश कर चुके हैं या दाखिल होने की फिराक में हैं। उन्होंने सूचित किया है कि पाडर इलाके में दो संदिग्ध लोगों को देखा गया है, जिनके पास एक एके-47 राइफल है और दूसरे का कद करीब छह फुट है। वह एक मई को पडियारना, डुल से होते हुए किश्तवाड़ में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है। यह कोई नहीं कह सकता।

माओवादियों ने जन अदालत लगा ग्रामीणों को पीटा, एक की मौत

जागरण संवाददाता, बड़गड़ (गढ़वा) : अर्से से शांत पड़े नक्सल संगठन झारखंड में फिर अपना सिर उठाने लगे हैं। दुमका, सरायकेला के बाद गढ़वा में माओवादियों ने खौफ फैलाने की कोशिश की है। रविवार देर शाम जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों ने जनअदालत लगाई। इसमें पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर ग्रामीणों को पीटा गया। इस पिटाई से एक ग्रामीण की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जिस ग्रामीण की मौत हुई है वह खपरीमहुआ गांव निवासी फागु किसान का पुत्र जितेंद्र किसान (25) बताया जा रहा है। वहीं घुरी गांव निवासी फलबीया बाखला का घायल पुत्र दिलीप तिर्की (30) का इलाज उसके परिजन स्थानीय स्तर पर करा रहे हैं। जानकारी के अनुसार मृत्युंजय दस्ते के माओवादियों ने खपरीमहुआ गांव से जितेंद्र किसान को बंधक बना लिया। संदीप मिंज को भी बंधक बना लिया गया। संदीप वाहन चालक है। शनिवार की रात अपहरण के बाद नक्सलियों ने दोनों को रात भर साथ घुमाया। रविवार की दोपहर माओवादियों ने संदीप के भाई दिलीप को पहाड़ी पर बुलवा लिया। दिलीप ने बताया कि माओवादी जितेंद्र से उसके पास पुलिस रायफल होने की बात कह कर बंदूक की मांग कर रहे थे। वहीं जितेंद्र बंदूक हम दोनो भाइयों के पास होने की बात कह रहा था। उसने बताया कि मेरे हाथ बांधकर दो बजे से पांच बजे शाम तक लगातार बंदूक की मांग करते हुए नक्सली लाठी-डंडे से उसकी पिटाई करते रहे, जिससे जितेंद्र की मौत हो गई।

नहीं रहीं किशोर कुमार की पहली पत्नी व अभिनेत्री रूमा गुहा

जागरण संवाददाता, कोलकाता

रूमा गुहा ठाकुरता। फाइल फोटो

महान गायक किशोर कुमार की पहली पत्नी मशहूर बंगाली अभिनेत्री व गायिका रूमा गुहा ठाकुरता नहीं रहीं। 84 साल की रूमा का निधन सोमवार सुबह कोलकाता के बालीगंज स्थित उनके आवास पर हुआ। रूमा कुछ दिन पहले ही कोलकाता लौटीं थी। वह पिछले तीन माह से अपने बेटे अमित कुमार के साथ रह रही थीं।

उनके निधन की जानकारी देते हुए उनके बेटे अयान गुहा ठाकुरता ने बताया कि सोमवार सुबह तकरीबन छह बजे उनका निधन हुआ। उन्होंने आगे बताया कि कुछ सालों से मां अधिक उम्र होने के कारण बीमार चल रही थीं।

गौरतलब है कि रूमा गुहा का जन्म कोलकाता में साल 1934 में हुआ था। उन्होंने 1951 में सुरों के सरताज किशोर कुमार से शादी की थी। हालांकि, रूमा और किशोर कुमार की शादी ज्यादा नहीं चल पाई थी। दोनों का छह साल में ही तलाक हो गया था, जिसके बाद रूमा ने अरूप गुहा ठाकुरता से शादी कर ली थी। अरूप और उनकी एक बेटी है श्रोमोना गुहा ठाकुरता, जो एक गायक हैं। उनके बेटे अमित कुमार भी मशहूर गायक रहे हैं।

ममता पहुंचीं शोक संवेदना व्यक्त करने : उनके निधन की सूचना मिलने के बाद उनके आवास पर पहुंची राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुई मुख्यमंत्री ने कहा कि रूमा गुहा ठाकुरता के निधन से सदमे में हूं। सिनेमा और संगीत की दुनिया में उनका अमूल्य योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परजनों और चाहनेवालों के साथ मेरी संवेदना है।

60 से अधिक फिल्मों में किया अभिनय : रूमा मशहूर फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की भतीजी थीं। उन्होंने करीब 60 से अधिक फिल्मों में काम किया था। महान निर्देशकों जैसे सत्यजीत रे, तपन सिन्हा, तरुण मजूमदार, राजेन तरफदार, अपर्णा सेन और मीरा नायर द्वारा बनाई गई फिल्मों में उन्होंने अभिनय कर खुद को स्थापित किया था। साल 1944 में आई हिंदी फिल्म 'ज्वार भाटा' से उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसके निर्देशक अमिया चक्रवर्ती थे। बांग्ला में उन्हें 'गंगा', 'अभिजान', 'बालिका वधू', और 'संघर्ष' जैसी फिल्मों से खास पहचान मिली। साल 2006 में वह आखिरी बार मीरा नायर की अंग्रेजी फिल्म 'द नेम्सकी' में नजर आई थीं। इसके अलावा कई फिल्मों में उन्होंने गाने भी गाए।

आजम खां ने दिया विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के रामपुर से लोकसभा के लिए चुने गए आजम खां ने सोमवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही अपना दल के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए संगम लाल ने भी विस सदस्यता छोड़ दी है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा पहुंचे कुल 11 विधायकों में से अब तक तीन त्यागपत्र दे चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने इस्तीफा मंजूर कर विधानसभा की सीटें रिक्त होने की सूचना निर्वाचन आयोग को भेज दी है। इससे पूर्व बसपा के जलालपुर सीट से विधायक बने रितेश पांडेय भी त्यागपत्र दे चुके हैं।

भाजपा गठबंधन के नौ और सपा व बसपा के एक-एक विधायक को निर्वाचित होकर लोकसभा में पहुंचने का मौका मिला है। योगी सरकार के तीन मंत्री भी सांसद चुने गए। इसमें लखनऊ कैंट की विधायक एवं पर्यटन और महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी, कानपुर की गोविंदनगर सीट के विधायक व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा मंत्री सत्यदेव पचौरी-कानपुर तथा फीरोजाबाद के टूंडला विधायक व पशुधन मंत्री प्रो. एसपी सिंह लोकसभा चुनाव जीत गए।

पाकिस्तान से भेजे गए थे अमृतसर में मिले ग्रेनेड

जागरण संवाददाता, अमृतसर

▸ एसएसपी ने कहा, ड्रग मनी से खरीदे गए थे वारदात के लिए भेजे गए ग्रेनेड

▸ अभी पकड़ में नहीं आए संदिग्ध आतंकी केएलएफ चीफ हरमीत ने भेजे ग्रेनेड

ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी से पहले आतंकी वारदात के लिए भेजे गए ग्रेनेड मामले में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। ये ग्रेनेड पाकिस्तान में बैठे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के चीफ हरमीत सिंह पीएचडी ने भेजे थे।

एसएसपी (देहाती) विक्रमजीत दुग्गल ने बताया कि अभी तक की जांच में सामने आया है कि भारत-पाक सीमा पर सटे गांवों में रहने वाले तस्करों ने हेरोइन की कन्साइमेंट ठिकाने लगाने के बाद मिली ड्रग मनी केएलएफ चीफ हरमीत सिंह तक पहुंचाई है। उस पैसे से ग्रेनेड, पिस्तौल और गोली खरीदकर पंजाब में आतंक बरपाने की साजिश रची गई है। उन्होंने बताया कि विगत में पकड़े गए दो जासूस मलकीयत सिंह व प्रिंसदीप सिंह, तीन नशा तस्करों और बब्बर खालसा के दो आतंकियों रविंदरपाल सिंह व जगदेव सिंह के साथ ग्रेनेड मिलने की इस घटना के तार जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ही नहीं कई अन्य देशों में बैठे हरमीत जैसे आतंकी सोशल मीडिया के जरिए युवकों का ब्रेन वाश कर रहे हैं। निरंकारी भवन पर हमला इसका ताजा उदाहरण है।

कैसे और कहां से आए ग्रेनेड, जांच जारी : एसएसपी दुग्गल ने कहा कि केएलएफ चीफ हरमीत पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। रविवार सुबह बरामद दो ग्रेनेड भी उसी के इशारे पर यहां पहुंचाए गए थे। अभी यह पता नहीं लग पाया है कि यह ग्रेनेड पाकिस्तान से यहां पहुंचे हैं या फिर जम्मू-कश्मीर से। पता लगाया जा रहा है कि ये ग्रेनेड कहां तैयार किए गए।

आरोपित पकड़ से दूर, मोबाइल से मिले कई सुराग

इस मामले में फरार युवकों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एसएसपी ने दावा किया कि आरोपितों के मोबाइल से पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पीजी मेडिकल ईडब्ल्यूएस कोटे पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : उच्चतम न्यायालय सोमवार को कुछ मेडिकल छात्रों की उन याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया जिसमें उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए महाराष्ट्र में पीजी मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए फिर से मेरिट सूची तैयार करने के बाद नए सिरे से काउंसलिंग का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति एमआर शाह की अवकाशकालीन पीठ मंगलवार को इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है।

नई याचिकाओं में से एक सागर सारदा द्वारा दायर की गई है और इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च अदालत ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी है। इस तथ्य को देखते हुए 'नई सीट मैट्रिक्स' और दाखिला के लिए नए सिरे से काउंसिलिंग आदि की अनुमति दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि 31 मई की समय-सीमा हमें परेशान कर रही है जो पीजी मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की खातिर इस अदालत द्वारा तय की गई है। पीठ ने कहा कि छात्रों को इस उद्देश्य के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत नहीं भागना चाहिए।

सलमान की 'भारत' पर रोक की मांग खारिज, कल होगी रिलीज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, सिर्फ लाभ लेने के मकसद से दायर की याचिका

▸ याचिका सूचीबद्ध होने से पहले मीडिया को जारी करने पर लगाई फटकार

आगामी 5 जून को रिलीज होने वाली अभिनेता सलमान खान की फिल्म भारत की रिलीज रोकने के मांग हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायमूर्ति जेआर मिधा व न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि अदालत का मत है कि याचिका सिर्फ लाभ लेने के लिए दायर की गई है। याची विकास त्यागी ने फिल्म नहीं देखी है। पीठ ने याचिकाकर्ता की इसके लिए खिंचाई की कि उसने अदालत के समक्ष याचिका के सूचीबद्ध होने से पहले ही मीडिया में जारी कर दिया।

याचिका के अनुसार प्रतीक और नाम के अनुचित उपयोग रोकथाम अधिनियम के तहत किसी भी व्यापार, व्यवसाय, पेशे के लिए या फिर किसी भी पेटेंट के शीर्षक में भारत नाम का उपयोग प्रतिबंधित है। संविधान के अनुसार भारत देश का आधिकारिक नाम है और इसे फिल्म का नाम देना अनुचित है। याचिकाकर्ता का कहना है इस फिल्म या इस फिल्म से जुड़े किसी भी चरित्र का नाम हमारे महान देश के नाम पर रखना उचित नहीं है।

याची ने आरोप लगाया कि यह हमारे महान देश की सांस्कृतिक और राजनीतिक छवि को बिगाड़ रहा है। उसका यह भी आरोप है कि देश के नाम से सलमान खान के पात्र की तुलना की गई है, ऐसे में संवाद को बदला जाना चाहिए। उसने कहा कि हजारों सालों से चली आ रही परंपरा और संस्कृति वाले देश को किसी एक पात्र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने याची की फिल्म की रिलीज रोकने की मांग खारिज कर दी।

भारत फिल्म का पोस्टर।

स्क्रिप्ट चोरी के आरोप में अभिनेता आयुष्मान खुराना तलब

मुंबई, प्रेट्र : फिल्म की स्क्रिप्ट चोरी की शिकायत के बाद ठाणे पुलिस ने पूछताछ के लिए बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना और दो अन्य लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। दो अन्य लोग निर्देशक अमर कौशिक और निर्माता दिनेश विजान हैं। ये देश के प्रसिद्ध प्रोडक्शन हाउस मैडकॉक फिल्म्स का हिस्सा हैं।

मुंबई के उपनगर मीरा रोड निवासी निर्देशक कमलाकांत नानक चंद्र ने तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामला उस समय का है जब चंद्रा एक फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, जिसका निर्देशन उन्हीं को करना था। उसने कहानी की स्क्रिप्ट वाट्सएप पर खुराना को भेजी थी। आरोप है कि आयुष्मान ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट कौशिक और विजान को दे दी और उन्होंने इस पर फिल्म बनाने की शुरुआत कर दी। शिकायत पर पुलिस ने जल्द से जल्द तीनों से अपना पक्ष रखने को कहा है। इस बीच खुराना के वकीलों ने स्क्रिप्ट चोरी के आरोपों को सिरे से नकारा है। उनका कहना है कि वह लोग जिस स्क्रिप्ट पर फिल्म बना रहे हैं वह पूरी तरह असली है। खुराना के वकीलों ने कहा कि शिकायतकर्ता इस मुद्दे पर कोर्ट भी गए थे, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली है।

प. बंगाल के बर्द्धमान जिले से सीरियल किलर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बर्द्धमान

पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्द्धमान जिले के कालना थाना की पुलिस ने सीरियल किलर कामरूज्जमान सरकार को गिरफ्तार किया है। उसकी तलाश पूर्व बर्द्धमान जिला की पुलिस आठ माह से कर रही थी। वह पूर्व बर्द्धमान जिले के कालना, मेमारी, मंतेश्वर थाना क्षेत्र के अलावा हुगली जिले के बलागढ़ व पांडुआ इलाके में वारदात को अंजाम दे चुका है। केवल पूर्व बर्द्धमान में बारह महिलाओं पर हमला किया था, जिसमें छह की मौत हो गई थी। लेकिन, वारदात को अंजाम देने के बाद वह कोई सुबूत नहीं छोड़ता था, इस कारण पुलिस को गिरफ्तार करने में इतना समय लगा। सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

पुलिस अधीक्षक भास्कर मुखर्जी ने कहा कि मूलरूप से मुर्शिदाबाद जिले का निवासी आरोपित सरकार लूट के मकसद से वारदात को अंजाम देता था। वह कालना के नादनघाट थाना इलाके में रहकर पुराना सामान बेचने का कार्य करता था, उसी की आड़ में वह महिलाओं को निशाना बनाकर लूट को अंजाम देता था। कालना में पहली वारदात पिछले वर्ष 2018 को हुई थी, जहां एक चैन से सांस रोककर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद इस वर्ष जनवरी में कालना इलाके में ही वैसी ही वारदात हुई। वह कालना, मेमारी, मंतेश्वर थाना इलाका में एक दर्जन वारदात कर चुका। इसमें केवल घर में अकेली रहने वाली महिलाओं को ही सरकार ने निशाना बनाया था। बार-बार हो रही इस तरह की वारदात से पुलिस के सामने यह स्पष्ट हो गया था कि एक ही व्यक्ति एक ही अंदाज में वारदात कर रहा है। ऐसे में कई सीसीटीवी फुटेज, जख्मी महिलाओं से पूछताछ कर आरोपित का स्केच बनाकर जांच शुरू की गई। अंत में रविवार की दोपहर वह कालना के देवीपुर इलाके से पुलिस की गिरफ्त में आ गया। वह किसी वारदात को अंजाम देने के लिए बाइक पर बैग लेकर जा रहा था, तभी पकड़ा गया। उसके बैग से लोहे की चैन, रॉड बरामद हुई है। इससे पुलिस को संदेह हो गया कि यही सीरियल किलर है। पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ के बाद उसके घर पर छापा मारा, जहां से सोने-चांदी के आभूषण बरामद हुए। पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या की बात को स्वीकार भी किया। जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया।

केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने की सड़क हादसे में घायल परिवार की मरहम पट्टी

गुरप्रेम लहरी, बठिंडा

अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी के आग बुझाने के बाद केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी मानवीयता की मिसाल पेश की है। उन्होंने गड्ढे में गिरे घायल परिवार को न केवल प्राथमिक चिकित्सा की बल्कि अस्पताल भी पहुंचाया। बठिंडा के बीड़ तालाब वासी गुरदीप सिंह अपनी पत्नी प्रवीण, पोती लक्ष्यदीप व पौत्र जगजीत व नवदीप के साथ स्कूटर पर कालझराणी जा रहे थे। गांव से थोड़ा पहले सड़क पर गड्ढा होने के कारण स्कूटर फिसल गया और पूरा परिवार परिवार घायल हो गया। दो बच्चों के सिर पर भी चोट आई थी। रविवार रात करीब 9.30 बजे

बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर मानसा से रविवार रात बादल गांव स्थित अपने घर जा रही थीं। कालझरानी गांव के पास उन्होंने इस परिवार को देखा। वह गाड़ी से उतरकर उनके पास गईं। केकेंद्रीय मंत्री ने गाड़ी में से फर्स्ट एड किट मंगवाई और घायलों की खुद मरहम पट्टी की। इसके बाद उन्हें बादल के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने मौके से ही डीसी बी श्रीनिवासन को फोन कर गड्ढों को भरने व सड़क की मरम्मत कराने के आदेश दिए। पंजाबी-अंग्रेजी मिश्रित बोली में उन्होंने कहा कि ए बिग टोएया इन द सड़क, इसको ठीक करवाओ। उनकी बातचीत की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। सोमवार दोपहर हरसिमरत ने स्पष्ट किया कि असल में जब वह डीसी को फोन कर रही थीं तो पंजाबी में बोल रही थीं। तभी ख्याल आया कि डीसी तो साउथ इंडियन हैं। उनको पंजाबी समझ नहीं आती होगी तो उन्होंने यह बोल दिया। उस समय कोई उचित शब्द नहीं सूझ रहा था।

बठिंडा में हादसे में घायल बच्चे की मरहम पट्टी करतीं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर। वीडियोग्रैप

सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के लिए दी धरने की धमकी

जागरण संवाददाता, बठिंडा : केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सोमवार देर शाम सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता 18 वर्षीय युवती को मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आरोपितों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वह मंगलवार को पुलिस के खिलाफ धरना देंगी। पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया भी उनके साथ थे। पीड़ित युवती, उसकी मां, नानी और नाना को साथ लेकर केंद्रीय मंत्री ने मीडिया को बताया कि युवती के साथ करीब ढाई माह पहले दुष्कर्म हुआ था। 23 मार्च को 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान व मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बावजूद आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया गया।

प्रबुद्ध मुस्लिमों ने अल्पसंख्यकों पर मोदी के नजरिये को सराहा

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली

▸ कमाल फारुखी व मदनी समेत 19 बुद्धिजीवियों ने पीएम को लिखा पत्र

▸ 26 मई के भाषण का किया जिक्र, नए कार्यकाल की सफलता की कामना की

▸ मोदी ने कहा था कि अल्पसंख्यकों को छलावे में रखकर उन्हें भ्रमित किया गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार में आने के बाद बदलाव की बयार महसूस की जाने लगी है। शिक्षा, समाज व संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे 19 प्रबुद्ध मुस्लिम लोगों के समूह ने मोदी को पत्र लिखकर अल्पसंख्यकों के प्रति उनके नजरिये की सराहना की है। साथ ही माह-ए- रमजान में सरकार के नए कार्यकाल की सफलता की कामना भी की है।

इस समूह का नेतृत्व करने वाले कमाल फारुखी उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, जो मोदी सरकार के तीन तलाक पर रोक के फैसले का विरोध कर रहा है। समूह में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव महमूद मदनी, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डा. जफरुल इस्लाम खान, प्रोग्रेसिव मुस्लिम सोशल सर्कल जयपुर के अध्यक्ष व पूर्व आइएएस एआर खान, हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष व दिल्ली के पूर्व मुख्य आयुक्त आयकर कैसर शमीम, वर्ल्ड एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष व अंजुम इस्लाम मुंबई के सीईओ शबी अहमद, आइआइटीयन व मऊ के मॉर्डन पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष शाहिद अनवर, शिक्षाविद व लेखक कलीमुल हाफिज समेत कुल 19 प्रबुद्ध लोग हैं।

पत्र में 26 मई को सेंट्रल हाल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण का जिक्र है जिसमें उन्होंने वोट बैंक की खातिर राजनीतिक दलों द्वारा देश के अल्पसंख्यकों को छलावे में रखकर उन्हें भ्रमित और भयभीत रखने का जिक्र किया था। साथ ही शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थिति पर चिंता जताते हुए मोदी ने सभी चुने हुए सांसदों से अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने पर जोर दिया। पत्र में प्रधानमंत्री द्वारा शिक्षा व स्वास्थ्य, कौशल विकास और अल्पसंख्यकों पर हमला करने वालों को सजा दिलाने की मांग की गई है।

तैयारी

वनों में आग की घटनाओं से त्रस्त उत्तराखंड वन महकमा क्लाउड सीडिंग तकनीक पर कर रहा विचार, प्रमुख वन संरक्षक जय राज के अनुसार अगले साल से शुरू हो सकता है कृत्रिम वर्षा का सिलसिला

कृत्रिम बारिश से बुझेगी जंगलों की आग

राज्य ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड में हर साल वनों में लगने वाली आग से परेशान वन महकमा अब क्लाउड सीडिंग (कृत्रिम बारिश) तकनीक अपनाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इसे लेकर विभाग ने होमवर्क प्रारंभ कर दिया है। वन विभाग के मुखिया प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) जय राज के अनुसार इस तकनीक के उपयोग के मद्देनजर वित्तीय संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संभव है कि अगले साल से फायर सीजन में जंगलों की आग बुझाने के लिए कृत्रिम बारिश का इस्तेमाल हो।

71 फीसद वन भूभाग वाले उत्तराखंड में हर साल फायर सीजन (15 फरवरी से मानसून आने तक) जंगलों के धधकने से बड़े पैमाने पर वन संपदा तबाह होती आ रही है। आग के विकराल रूप धारण करने पर इसे बुझाने के लिए महकमे को इंद्रदेव का मुंह ताकना पड़ता है। इस साल की ही बात करें तो फरवरी से अप्रैल तक मौसम के साथ देने से आग की 88 घटनाएं हुई थीं, मगर एक मई से अब तक इनमें 1731 का इजाफा हो गया। 2521 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

जंगलों में लगी आग से उठता धुंआ। फाइल फोटो

हर साल की इस दिक्कत को देखते हुए वन महकमा अब कृत्रिम बारिश के विकल्प को लेकर गंभीर हुआ है। सोमवार को वन मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में पीसीसीएफ जय राज ने कहा कि क्लाउड सीडिंग तकनीक ऐसी है, जिससे कहीं के बादल को कहीं लाकर बारिश कराई जा सकती है। जंगल की आग पर नियंत्रण के लिए सबसे बेहतर विकल्प है और विदेशों में कई जगह इसका प्रयोग भी होता है।

पीसीसीएफ कहते हैं कि क्लाउड सीडिंग को लेकर विभाग ने होमवर्क शुरू कर दिया है। इस संबंध में बातचीत चल रही है। अब कृत्रिम बारिश तकनीक के इस्तेमाल के मद्देनजर वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था जुटाने पर भी फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि सबकुछ ठीक रहा तो अगले साल से फायर सीजन में जंगलों की आग बुझाने में क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। पीसीसीएफ ने इस फायर सीजन में विभाग की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी।

क्या है क्लाउड सीडिंग : क्लाउड सीडिंग उस प्रक्रिया को कहा जाता है, जिसमें कृत्रिम तरीके से बादलों को बारिश के अनुकूल बनाया जाता है। क्लाउड सीडिंग के लिए आसमान में बादल होना जरूरी है। इन पर सिल्वर आयोडाइड या ठोस कार्बन डाईआक्साइड को छोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में बादल नमी सोखते हैं और फिर बारिश होने लगती है।

आला हजरत खानदान में सुलह की कोशिश जारी

जागरण संवाददाता, बरेली

दरगाह आला हजरत के सज्जादानशीन और उनके सगे चचेरे भाई में मारपीट के मुकदमे की चर्चा दुनियाभर के सुन्नी बरेलवी मुसलमानों के बीच फैल चुकी है। वे इसे लेकर सोशल मीडिया के जरिये प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच सुलह की कोशिशें भी शुरू हुईं, जो फिलहाल कामयाब नहीं हो सकी हैं। अभी भी कोशिश जारी है। पुलिस ने भी मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। दरगाह आला हजरत के सज्जादानशीन मुफ्ती मुहम्मद अहसन रजा खां उर्फ अहसन मियां ने अपने चाचा उस्मान रजा खां उर्फ अंजुम मियां और चचेरे भाई शीरान रजा खां के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा रविवार को कोतवाली में दर्ज कराया था। शनिवार को दरगाह की रजा मस्जिद में जश्न-ए-कुरान मुकम्मल होने के दौरान विवाद हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद रविवार की रात पुलिस दरगाह पर पहुंची थी। साक्ष्य जुटाए और दोनों पक्षों से पूछताछ भी की है। दरगाह आला हजरत सुन्नी मुसलमानों का मरकज (केंद्र) माना जाता है। भारत के साथ दुनिया भर में यहां के मुरीद हैं। सज्जादानशीन के साथ मारपीट की खबर सोमवार को सोशल मीडिया के जरिये दुनियाभर के मुरीदों तक पहुंच गई। वाट्सएप, फेसबुक पर मुरीद घटनाक्रम पर दुख जाहिर करते हुए सुलह की जरूरत जता रहे हैं।

खानदान का दूसरा पक्ष सक्रिय : सज्जादानशीन ने अपनी तहरीर में दरगाह प्रबंधन का वक्फ ट्रिब्यूनल में मुकदमा दर्ज होने का जिक्र किया है। इसी रंजिश को मारपीट का कारण बताया है। इससे मुकदमे लड़ने वाला खानदान का दूसरा पक्ष भी सक्रिय हो गया है।

ऐसे हुआ विवाद : शनिवार की रात दरगाह की रजा मस्जिद में कुरान मुकम्मल होने का जश्न चल रहा था। आरोप है कि शीरान रजा खां को नात पढ़ने के लिए माइक नहीं मिला। उन्होंने एक नातख्वाह को तमाचा जड़ दिया।

75 वर्ष बाद हरियाणा के दो शहीदों की अस्थियां वतन लाई गईं

जेएनएन, हिसार : द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली में शहीद हुए झज्जर जिले के सिपाही हरि सिंह और हिसार के नंगथला गांव निवासी पालुराम की अस्थियां सेनाधिकारियों की मौजूदगी में सोमवार को उनके गांव पहुंचाई गईं। वहां दोनों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। झज्जर में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने हरि सिंह की अस्थियों पर पुष्प अर्पित करते हुए उनको नमन किया। कहा, हमें नौगांव के अमर शहीद हरि सिंह की शहादत पर नाज है।

13 सितंबर 1944 को हुए थे शहीद: सैन्य अधिकारियों ने बताया कि सिपाही हरि सिंह और पालुराम 13 सितंबर 1944 को शहीद हुए थे। इनकी अस्थियां इटली में फ्लोरेंस के नजदीक पोगिओ आल्टो में मिले थे। इनकी पहचान को लेकर 1996 से लेकर 2010 तक इंक्वायरी चली। युद्ध में गायब हुए जवानों की सूची के आधार पर वर्ष 2017 में जांच दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोनों वीर योद्धा हरियाणा के सिपाही हरि सिंह व पालुराम हैं।

70 फीसद होटल मनाली के बुक हो चुके हैं। स्कूल-कॉलेजों में छुट्टियों के मद्देनजर प्रदेश में जून में सैलानियों की तादाद बढ़ने लगी है। लोकसभा चुनाव की वजह से इस साल अप्रैल व मई फीका रहा है।

'जय श्रीराम' पर तथागत के निशाने पर ममता

बोले राज्यपाल ▶ जो लोग राजनीतिक फायदे के लिए इस नारे की निंदा कर रहे हैं वे हिंदू बंगालियों के शत्रु हैं

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए जा रहे 'जय श्रीराम' के नारों को लेकर राजनीति पूरे उफान पर है। इस बीच मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने बिना नाम लिए अपने ट्विटर हैंडल के जरिये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिये कहा कि 'जय श्रीराम' की निंदा करने वाले हिंदू बंगालियों के शत्रु हैं। उधर, 'जय श्रीराम' के नारे को लेकर जारी घमासान के बीच ममता ने फेसबुक व ट्विटर के डीपी पर जय हिंद-जय बांग्ला लिख लिया है। भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी को 'गेट वेल सून कार्ड' भेजने का निर्णय लिया है।

तथागत रॉय ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'हम बंगाली, जो दुर्गापूजा करते हैं, उनका दूसरा नाम अकाल बोधन है। राक्षसों के विनाश के लिए भगवान श्रीराम ने देवी दुर्गा की पूजा-अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। ऐसे में जो लोग 'जय श्रीराम' के उद्घोष की निंदा करते हैं, वे मूर्ख होने के साथ ही हिंदू बंगालियों के शत्रु भी हैं।'भाजपा कार्यकर्ताओं के 'जय श्रीराम' का नारा लगाने पर पिछले दिनों भड़कीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर (डीपी) बदल दी। अब उनकी डीपी में स्वतंत्रता संग्रामी, शिक्षाविदों की फोटो के साथ जय हिंद, जय बांग्ला लिखा

तथागत रॉय फाइल

है। बता दें कि ममता के साथ ही उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने भी अपनी डीपी बदल दी है।

दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक अनुभवी नेता हैं, लेकिन राज्य में 'जय श्रीराम' के नारे पर उनका व्यवहार असामान्य और अजीब है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा के प्रदर्शन से सीएम ममता बनर्जी बौखला गई हैं । सुप्रियो ने कहा कि वह और आसनसोल के लोग ममता बनर्जी को 'गेट वेल सून' के कार्ड भेजेंगे। बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह द्वारा ममता को 'जय श्रीराम' लिखे 10 लाख पोस्टकार्ड भेजने की घोषणा के बाद राज्य के खाद्य मंत्री एवं उत्तर 24 परगना जिला तृणमूल अध्यक्ष ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कार्यकर्ताओं व समर्थकों से अर्जुन सिंह को फेसबुक पर 'जय हिंद' व 'जय बांग्ला' लिखकर भेजने का आह्वान किया है।

जय श्रीराम बोलने पर कर्मचारी का तबादला

जागरण संवाददाता, कोलकाता : पश्चिम बंगाल में जय श्रीराम बोलने पर एक कर्मचारी का तबादला करने का मामला सामने आया है। यह वाकया कोलकाता में कॉलेज स्ट्रीट स्थित कलकत्ता विश्वविद्यालय का है। विवि में भाजपा समर्थित कर्मचारी संगठन का आरोप है कि विवि परिसर में जय श्रीराम बोलने की वजह से उनके एक साथी कर्मचारी का तबादला हरिनघाटा कर दिया गया है। उक्त कर्मचारी वाइस चांसलर के दफ्तर में कार्यरत था। पीड़ित कर्मचारी ने बताया कि उसका दोष सिर्फ इतना है कि उसने विवि परिसर में जय श्रीराम बोला था। हरिनघाटा उसके घर से काफी दूर है। उसे अब आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यह सब बदले की भावना से किया गया है। पिछले सप्ताह डीए भत्ता व छठे वेतन आयोग की मांग को लेकर विवि परिसर में भाजपा कर्मचारी संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया था, जहां कर्मचारियों ने जय श्रीराम व भारत माता की जय के नारे लगाए थे।

बंगाल में नहीं थम रहा तृणमूल-भाजपा समर्थकों में संघर्ष

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- वीरभूम, हुगली व मुर्शिदाबाद में दोनों दलों में हुआ टकराव
- हुगली में तीन जख्मी, पूर्व मेदिनीपुर जिले में भाजपा ने निकाली रैली

पश्चिम बंगाल में आम चुनाव के बाद भी राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। वीरभूम, हुगली व मुर्शिदाबाद में सोमवार को सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में टकराव हुआ है। गोलीबारी व झड़पों में हुगली में तीन जख्मी हो गए हैं। पूर्व मेदिनीपुर जिले में भाजपा ने विरोध में रैली निकाली है।

लोकसभा चुनाव में वीरभूम जिले के बोलपुर समेत अन्य स्थानों पर भाजपा को भारी समर्थन मिलने के बाद विजय जुलूस निकालने को लेकर तृणमूल और भाजपा के बीच सियासी रंजिश शुरू हो गई है। हाल ही में सिउड़ी, कांकड़तला समेत अन्य जगहों में सियासी संघर्ष के बाद अब इलमबाजार में सत्ताधारी पार्टी और विरोध दल भाजपा के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट व बमबाजी हुई। इसमें कई लोग जख्मी हो गए। तृणमूल का आरोप है कि पार्टी कार्यालय पर कब्जे के लिए हमला किया गया है, जबकि भाजपा ने इसको तृणमूल की गुटबाजी बताया। तनाव के मद्देनजर गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है। उधर, तृणमूल नेता को पीटने के आरोप में पुलिस ने दो भाजपा कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है।

हिंसा की आंच से हुगली जिला भी गरमा उठा है। जिले के आरामबाग इलाके के मलयपुर घर गोआल और गोघाट इलाके के नकुंडा इलाके में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थक भिड़ गए। दोनों घटनाओं में दोनों तरफ के तीन लोग जख्मी हो गए। जिला तृणमूल नेतृत्व ने भाजपा पर उनके समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ पूर्व मेदिनीपुर जिले के खेजुरी में पिछले तीन दिनों से तृणमूल-भाजपा में चल रहे संघर्ष के कारण भारी तनाव है। इस बीच सोमवार को भाजपा के जिलाध्यक्ष तपन माइती के नेतृत्व में खेजुरी में मोटरबाइक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपाई शामिल हुए। उन्होंने 'जय श्रीराम' के नारे लगाए। मुर्शिदाबाद जिले के नउदा में अज्ञात लोगों ने तृणमूल के नेता संजीत राय को गोली मार दी।

सरकार ने चाय, कॉफी और शराब से दूर रहने की सलाह दी

नई दिल्ली, प्रेट्र : देशभर में गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को ढीले व हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने, घर में रहने और चाय, कॉफी व शराब जैसे पेय पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी गई है। सरकार ने कहा है कि गर्म हवाएं सेहत पर बुरा असर डाल सकती हैं।

एडवाइजरी में लोगों से कहा गया है कि बाहर निकलते समय छाता, टोपी या तौलिया लेकर चलें। थोड़ी-थोड़ी देर पर पानी तथा लस्सी, नींबू पानी व जूस जैसे नमक मिले पेय पीते रहें। सरकार ने ओआरएस घोलकर पीने की सलाह भी दी है। एडवाइजरी में लोगों को तरबूज, खरबूज, खीरा और संतरा आदि खाते रहने को भी कहा गया है। लोगों को पर्दे, पंखे, कूलर या एसी के इस्तेमाल से कमरे का तापमान भी सही रखने की सलाह

गर्मी में बचें चाय-कॉफी से। प्रतीकात्मक

दी गई है। एडवाइजरी के मुताबिक, तबियत में किसी भी तरह की गड़बड़ी महसूस होने पर व्यक्ति को तत्काल ठंडी जगह पर ले जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के मामले में सतर्कता बरतने को कहा गया है। सरकार ने दोपहर 12 बजे से तीन बजे के बीच बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है।

ओडिशा में आंधी का कहर, आठ की मौत

जेएनएन, भुवनेश्वर : फणि तूफान के कहर से अभी ओडिशा के कई जिले पूरी तरह उबर भी नहीं पाए थे कि मौसम ने अपना कहर फिर बरपाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के अलग-अलग हिस्सों में आ रही आंधी और तूफान से काफी नुकसान हुआ है। रविवार रात आए आंधी व तूफान के कारण भी कोरापुट, केंदुझर, जाजपुर और गंजाम जिले में आठ लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार शाम को भी बारिश के साथ आई तेज आंधी ने सुंदरगढ़ व झारसुगुड़ा में काफी नुकसान पहुंचाया। सुंदरगढ़ में जहां दर्जनों पेड़, एसबेस्टस व झोपड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं वहीं झारसुगुड़ा जिले के बेलपहाड़, बंधबहाल तथा लखनपुर ब्लॉक क्षेत्र में जमकर तबाही हुई।

न्यूज गैलरी

ईद पर नमाज को तीन घंटे फ्री रहेगा ताजमहल में प्रवेश

आगरा : ईद-उल-फितर पर नमाज के लिए आगरा के ताजमहल में प्रवेश तीन घंटे फ्री रहेगा। सुबह सात से 10 बजे तक स्मारक में देशी-विदेशी पर्यटक स्मारक में बिना टिकट के प्रवेश पा सकेंगे। अधीक्षण पुरातत्वविद वसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि चांद के अनुसार पांच या छह जून को जिस दिन भी ईद होगी, उसी दिन सुबह ताजमहल में प्रवेश पर टिकट नहीं लगेगा। (जासं)

सहनशीलता दिवस घोषित हो प्रकाश पर्व : अमरिंदर

चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व 12 नवंबर को राष्ट्रीय सहनशीलता दिवस घोषित करने की अपील की है। पीएम को लिखे पत्र में कैप्टन ने कहा है कि गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म के जिन मूल सिद्धांतों की बुनियाद रखी थी उसमें मानवता की समानता, निष्काम सेवा, हरेक का भला शामिल है। सिखों के पहले गुरु साहिब जी प्यार, करुणा व सहनशीलता के प्रतीक हैं। उनकी महान शिक्षाएं आज भी उतनी ही सार्थक हैं, जितनी पहले थीं। (राब्यू)

गोताखोरों की संवेदनहीनता से डूबकर तीन बच्चों की मौत

बदायूं : गोताखोरों की संवेदनहीनता के चलते सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान को आए राजस्थान के चचेरे-तहेरे दो भाइयों समेत तीन बच्चों की मौत हो गई। हालांकि सात को गोताखोरों और नहा रहे लोगों ने सकुशल निकाल लिया। राजस्थान के जिला दौसा में थाना वादीक्यूलारी इलाके के गांव निहालपुरा निवासी केशराम और उनके भाई चेतराम अपने परिवारों के साथ गंगास्नान को आए थे। उनके साथ गांव के 40 अन्य लोग थे। केशराम का बेटा दिलकुश (11) और चेतराम का बेटा नितिश (10) स्नान के दौरान पिलर के पास भंवर में फंस गए। यह देख वहां मौजूद निजी गोताखोरों से परिजनों ने बच्चों को निकालने का आग्रह किया लेकिन, गोताखोर पहले रुपये देने की बात पर अड़े रहे। 10 मिनट बाद गोताखोर पानी में गए और कुछ देर बाद दोनों बच्चों को बाहर निकाल लाए, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। उधर, शिवम (4 वर्ष पुत्र नेम सिंह निवासी भैसाना गांव, धौलपुर, राजस्थान की भी गंगा में डूबने से मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव लेकर घर चले गए। (जासं)

बड़े काम का एएन-32 विमान

दो इंजन वाला एएन 32 विमान भारतीय एयरफोर्स में बड़े काम का माना जाता है। यह रूसी विमान एएन-26 का आधुनिक वर्जन है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय रूस और भारत के बीच दोस्ताना संबंध और भारतीय वायुसेना की जरूरतों को देखते हुए इसे मंगाया गया था। कम और मध्यम हवाई दूरी के लिए सैन्य साजो-सामान पहुंचाने, आपदा के समय घायलों को अस्पताल लाने-ले जाने और युद्ध के समय जावनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

540 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने की क्षमता

16,800 किलोग्राम वजन ढोने की क्षमता

2,500 किमी उड़ान सीमा

78 फीट विमान की लंबाई

50 यात्रियों को ले जाने की क्षमता।

28 फीट विमान की ऊंचाई

रूसी विमान एएन-26 का आधुनिक वर्जन है दो इंजन वाला भारतीय एन 32 विमान। प्रतीकात्मक

दुनिया में इस्तेमाल

दुनिया के 10 देशों में 240 से अधिक एएन विमान संचालित किए जा रहे हैं। भारत में 105 विमान अभी सेवा में हैं।

लापता होने की पहली घटना

25 मार्च, 1986 को पहली बार इस विमान के लापता होने की घटना सामने आई थी, जब सोवियत संघ से एक डिलीवरी उड़ान के दौरान यह विमान कथित तौर पर हिंद महासागर में गायब हो गया था। वहीं 2016 में चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रहा यह विमान लापता हो गया था। इसमें भारतीय वायुसेना के 12 जवान, 6 क्रू-मेंबर, 1 नौसैनिक,1 सेना का जवान और एक ही परिवार के 8 सदस्य मौजूद थे। इसकी तलाश में 1 पनडुब्बी, 8 विमान और 13 पोत लगाए गए थे। इस विमान का लापता होना एक गुत्थी बन गया था। इसका न मलबा मिला था, न यात्री।

झारखंड में पूर्व स्वास्थ्य सचिव और उनके भाई को हुई जेल

जागरण संवाददाता, रांची

- 1.76 करोड़ रुपये मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी की विशेष अदालत में किया सरेंडर
- पूर्व सचिव सहित पांच अन्य के खिलाफ 2012 से चल रहा मामला, 12 जून को होगा जमानत पर फैसला

1.76 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ. प्रदीप कुमार एवं उनके भाई राजेंद्र कुमार ने सोमवार को ईडी की विशेष अदालत में सरेंडर किया। जहां से दोनों भाइयों को जेल भेज दिया गया। इससे पूर्व अभियुक्तों की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई। मामले में डॉ. प्रदीप कुमार की याचिका पर बहस पूरी हो गई। जमानत पर फैसले के लिए 12 जून की तिथि निर्धारित की गई है।

वहीं राजेंद्र कुमार के मामले में आंशिक बहस हुई। इस मामले की भी अगली सुनवाई 12 जून निर्धारित की गई है। इसके अलावा राजेंद्र कुमार ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी अदालत में सरेंडर किया। बता दें कि मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने 2012 में पूर्व स्वास्थ्य सचिव सहित पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी से जुड़े मामले में एक जून को एक अभियुक्त श्यामल चक्रवर्ती ने भी सरेंडर किया था जिसे जेल भेज दिया गया। बाकी अभियुक्तों को सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में नंदलाल, धर्मेंद्र कुमार धीरज और एनके केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया है।

अभियोजन पक्ष ने जमानत देने का किया विरोध : सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से दोनों भाइयों को जमानत देने का विरोध किया गया। विशेष लोक अभियोजक एसआर दास ने यह कहते हुए जमानत का विरोध किया कि दोनों की जमानत याचिका हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में ही खारिज कर दी हैं। इनके खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं। विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि इसी मामले में एक अभियुक्त श्यामल चक्रवर्ती को जेल भेजा गया है, जबकि उससे ज्यादा सुबूत इनके खिलाफ हैं। मालूम हो कि डॉ. प्रदीप कुमार ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तीन जून तक स्थानीय अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया था। प्रदीप कुमार चर्चित दवा घोटाला में ट्रायल फेस कर रहे हैं।

हरियाणा में गड्ढे में गिरी कार, एक परिवार के चार की मौत

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : गांव धांगड़ से बीकानेर स्थित मुकाम धाम जा रहे परिवार की कार टायर फटने से पलटकर गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में दादी-पोती और बहू समेत चार लोगों की मौत हो गई। वहीं पिता-पुत्र का इलाज चल रहा है। हादसा बीकानेर जिले के कातर गांव के समीप हुआ।

गांव धांगड़ निवासी संजय कुमार अपनी पत्नी रजनी देवी (30), बेटे यश, चचेरी बहन डिंपल (22), दादी बुग्गी देवी (80), दादी की बहन हिसार के आजाद नगर निवासी कांकरी देवी (65) के साथ स्विफ्ट कार में रविवार को सालासर गए थे। वह रात को सालासर पहुंच गए। वहां बालाजी के दरबार में मत्था टेकने के बाद सोमवार तड़के करीब तीन बजे वह भी बीकानेर स्थित मुकाम धाम के लिए रवाना हो गए। सोमवती अमावस्या पर मुकाम धाम में बड़ा मेला लगाता है। सुबह करीब साढ़े नौ बजे जब मुकाम धाम से 30 किलोमीटर पहले गांव कातर के पास पहुंचे तो अचानक कार का टायर फट गया। इससे कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में बुग्गी देवी व डिंपल की मौके पर ही मौत हो गई। चार अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

कश्मीर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली तो करेंगे यात्रा का बहिष्कार

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर आर्गेनाइजेशन ने श्राइन बोर्ड को दी चेतावनी
- हर हाल में 15 जून से कश्मीर में प्रवेश करने की अनुमति देने की उठा रहे मांग

श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर आर्गेनाइजेशन ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को चेतावनी दी है कि अगर लंगर लगाने वालों के ट्रकों को कश्मीर में 15 जून से प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली तो यात्रा का बहिष्कार किया जाएगा। यही नहीं, बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जाएगा।

श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 21 जून से पहले लंगरों के राशन और अन्य सामग्री के ट्रकों को कश्मीर में प्रवेश करने की अनुमति न देने का फैसला किया है।

वहीं, लंगर आर्गेनाइजेशन बोर्ड से आग्रह कर चुकी है कि 21 जून से पहले ट्रकों को कश्मीर में प्रवेश करने की अनुमति मिले, लेकिन बोर्ड नहीं माना। अब बोर्ड और लंगर आर्गेनाइजेशन के बीच तनातनी बढ़ गई है। चंडीगढ़ में रविवार को आर्गेनाइजेशन की जनरल बॉडी की बैठक हुई थी, जिसमें इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। जनरल बॉडी ने कोई भी फैसला लेने के लिए प्रधान विजय ठाकुर और महासचिव राजन गुप्ता को अधिकृत किया। दोनों ने कोर कमेटी के साथ सलाह मशविरा करने के बाद कड़ा फैसला लिया है।

महासचिव ने कहा कि 2018 में बाबा अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी। उस समय लंगर वालों को 18 जून तक संबंधित जगहों पर पहुंचने के लिए कहा गया था। इस बार यात्रा एक जुलाई से शुरू हो रही है और 21 जून से पहले जवाहर टनल को क्रॉस करने की इजाजत नहीं है।

लंगर वालों को संबंधित जगहों पर 27 जून को पहुंचने के लिए कहा गया है। ऐसे में लंगर लगाने के लिए मात्र चार दिन मिलेगा। पिछले साल 11 दिन मिला था। पवित्र गुफा, पंजतरणी, पिस्सुटॉप और शेषनाग जैसे शिविरों में पहुंचने और लंगर स्थापित करने में समय लगता है। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि अगर बोर्ड 15 जून से एंट्री की अनुमति नहीं देता तो लंगर संगठन यात्रा का बहिष्कार करेगा। गौरतलब है कि श्राइन बोर्ड के फैसले के विरोध में जम्मू और पंजाब में प्रदर्शन भी हो चुके हैं।

नैनी से साबरमती जेल भेजा गया बाहुबली अतीक अहमद

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : बाहुबली नेता अतीक अहमद को सोमवार को अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अतीक को पहले प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल से वाराणसी एयरपोर्ट लाया गया। इसके बाद हवाई मार्ग के जरिये उसे अहमदाबाद ले जाया गया। अतीक को गुजरात की किसी जेल में शिफ्ट करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसी आदेश पर कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने गुजरात सरकार से संपर्क कर अतीक को अहमदाबाद जेल में शिफ्ट करने का निर्णय लिया। अहमदाबाद के सरदार पटेल एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह भारी पुलिस बल के बीच पहुंचे डॉन अतीक अहमद ने बाहर आते ही लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इसी दौरान उसके गले में किसी ने गुलाब की माला डाल दी। हालांकि वैन में बैठने से पहले ही पुलिस ने इसे उतरवा लिया। विमान में अतीक के साथ बैठे उसके बेटे उमर ने बताया कि उसके पिता को वाराणसी से हवाई मार्ग द्वारा एयरपोर्ट लाया गया और इसके बाद जेल ले जाया गया। बता दें कि अतीक अहमद पर लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल को गुर्गों से अगवा कराकर देवरिया जेल में पीटने का आरोप है।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का अनोखा संदेश.....

अंतरराष्ट्रीय समर फेस्टिवल के पहले दिन रिज मैदान पर आंगनवाड़ी की 650 महिलाओं ने सामूहिक पहाड़ी नाटी कर समाज को ये संदेश दिया। पहली बार रंग बिरंगे परिधानों में महिलाएं एक साथ शिमला के रिज मैदान पर जुटी। इस दौरान बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। महेंद्र ठाकुर

तैयारी

डस्ट स्वीपर मशीन से उठाई जाएगी सड़कों से धूल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिया है सड़कों को साफ करने का प्रस्ताव

सड़क की धूल इकट्ठा कर बनाई जाएंगी ईंटें

यादवेन्द्र शर्मा, शिमला

हिमाचल में सड़क पर चलते समय अब आपको धूल से बचने के लिए मुंह ढकने की जरूरत नहीं होगी। धूल के एक-एक कण को डस्ट स्वीपर मशीन से उठाया जाएगा। इस धूल का इस्तेमाल इंटरलॉक टाइल बनाने में इस्तेमाल होगा। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी और पहाड़ों की रानी शिमला में मशीन का ट्रायल किया गया है जो सफल रहा है।

ट्रायल के दौरान एक निजी कंपनी की मशीन ने सड़क की धूल के छोटे से छोटे कण को उठाया। यह मशीन बड़ी सड़कों में सफाई करने के साथ तंग गलियों से भी धूल को एकत्रित कर सकती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगमों, शहरी निकायों व विभागों को सार्वजनिक निजी सहभागिता के साथ सफाई करने या अपने स्तर पर मशीनें खरीदकर सड़कों को साफ करने का प्रस्ताव दिया है। नगर निगम, शहरी निकाय व विभिन्न विभाग इस धूल से इंटरलॉक टाइल्स बनवाकर या खुद बनाकर इन्हें बेचकर लाखों रुपये की आमदनी कर सकेंगे।

ये है सड़कों से धूल साफ करने वाली मशीन। जागरण

एक लीटर पेट्रोल से आठ हजार वर्गमीटर की सफाई

ट्रायल के दौरान करीब नौ लाख रुपये की चार फीट चौड़ी डस्ट स्वीपर मशीन ने एक लीटर पेट्रोल से आठ हजार वर्गमीटर की सफाई की। मशीन धूल, मलबे, पत्तियों व कंकड़ को एक साथ साफ कर सकती है। धूल साफ करने वाले यंत्र के अलावा इसमें कूड़ा कचरा खींचने वाले यंत्र भी लगे हैं। मशीन वैक्यूम क्लीनर की तरह धूल व कचरे को अपने अंदर खींचती है। इसमें नालियां साफ करने वाले यंत्र भी लगे हैं।

शहरों में हवा प्रदूषित

हिमाचल प्रदेश में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसमें करीब 80 फीसद योगदान सड़कों की धूल व उद्योगों से निकलने वाले धुएं का है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में प्रदेश के शहरों में हवा प्रदूषित पाई गई है। शहरों में रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (आरएसपीएम) का स्तर निर्धारित 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से अधिक पाया गया है।

सड़कों को साफ रखने का आदेश एनजीटी ने भी दिया है। सड़कों से धूल साफ करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

-आरके पुरुथी, सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

कैसे बनेगी इंटरलॉक टाइल : इंटरलॉक टाइल तैयार करने के लिए प्लास्टिक वेस्ट के साथ धूल व मिट्टी मिलाई जाएगी। इसमें सड़कों से एकत्रित धूल का इस्तेमाल होगा।

क्या होगा लाभ : सड़कों की धूल से प्रदूषण फैलने के साथ दमा रोगियों को दिक्कत होती है। सड़कों किनारे स्थित खाद्य पदार्थों की दुकानों व ढाबों में खाने पर भी सड़कों की धूल गिरती है। इससे लोग दूषित भोजन खाने से बीमार होते हैं। सड़कों से धूल का एक-एक कण उठने पर प्रदूषण कम होगा और दमा रोगियों को भी राहत मिलेगी। सड़कों के किनारे स्थित दुकानों पर भी खाने में धूल नहीं गिर सकेगी। इंटरलॉक टाइलों का इस्तेमाल सड़कों, फुटपाथ या अन्य कच्चे रास्तों पर किया जाएगा।

हरियाणा में भतीजे की हत्या में चाचा को मिली उम्रकैद

संवाद सहयोगी, हरियाणा (जगाधरी)

दिवाली के दिन आठ वर्षीय यतिन की हत्या के बाद आंखें निकालने के मामले में कोर्ट ने उसके चाचा गोबिंदपुरी निवासी राहुल त्यागी को अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। यह फैसला जिला और सत्र न्यायाधीश बिमलेश तंवर की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि जघन्य अपराध को देखते हुए दोषी को ज्यादा से ज्यादा सजा देनी जरूरी है। अगर इससे कम सजा की तो समाज में गलत संदेश जाएगा।

एडवोकेट राजीव चावला और सतीश गर्ग के मुताबिक 19 अक्टूबर 2017 को गोबिंदपुरी में आठ साल के यतिन की निर्मम हत्या को देखकर हर किसी का दिल दहल गया था। पुलिस के अनुसार राहुल पहले यतिन को छत पर बने कमरे में ले गया। कमरा बंद कर चाकू से उसकी गर्दन काट दी और फिर आंखें भी निकाल लीं। इसके बाद लोहे की रॉड से कई वार किए, जिससे सिर के कई टुकड़े हो गए। हत्या के बाद राहुल कमरा बंद कर फरार हो गया। मगर दशहरा ग्राउंड के पास वह गिर गया, वहां पर लोगों ने उसे देखकर पुलिस को सूचित किया।

अवैध संबंध के शक में की थी हत्या : गोबिंदपुरी में यतिन के पिता अमरजीत और पिता के चचेरे भाई राहुल त्यागी का मकान साथ-साथ है। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। एक दिन राहुल ने अपनी पत्नी का फोटो अमरजीत के मोबाइल में देखा। इस पर उसे शक हो गया कि दोनों के बीच संबंध हैं। अमरजीत को सबक सिखाने के लिए राहुल ने आठ साल के यतिन की हत्या की साजिश रची और दिवाली के दिन साजिश को अंजाम दे डाला। कोर्ट में सोमवार को सजा सुनाने के दौरान राहुल गुमसुम खड़ा रहा। इस दौरान राहुल का कोई परिजन कोर्ट परिसर में नजर नहीं आया। परिजनों ने उसकी पैरवी भी नहीं की। राहुल को सरकारी खर्च पर वकील मुहैया कराया गया था।

Downloaded from: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 4 जून 2019

दैनिक जागरण
माता-पिता ईश्वर का साक्षात स्वरूप हैं

न्याय की बात

अपना पदभार ग्रहण करते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपनी यह पुरानी प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उनके मंत्रालय की भूमिका सीमित नहीं रहेगी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि फिलहाल ऐसी ही स्थिति है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में सरकार कोलेजियम की सिफारिशों पर मुहर लगाने तक ही सीमित है। यह अभी हाल में देखने को भी मिला। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम की ओर से भेजे गए दो नामों पर सरकार ने आपत्ति जताई तो उसे खारिज कर यही दो नाम फिर से आगे बढ़ा दिए गए। चूंकि सरकार के सामने और कोई उपाय नहीं था इसलिए उसने वही किया जो कोलेजियम की ओर से चाहा जा रहा था। एक तरह से कानून मंत्रालय ने पोस्ट ऑफिस जैसा ही काम किया। यह स्थिति बदली जानी चाहिए, क्योंकि दुनिया के किसी भी श्रेष्ठ लोकतांत्रिक देश में न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्तियां नहीं करते। बेहतर हो कि सुप्रीम कोर्ट भी यह समझे कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में कोलेजियम व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों और मान्यताओं के अनुकूल नहीं है। निःसंदेह न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं स्वायत्त होना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में खुद को जवाबदेही और पारदर्शिता से परे रखे। इसका औचित्य इसलिए भी नहीं बनता, क्योंकि खुद सर्वोच्च न्यायालय यह मान चुका है कि कोलेजियम व्यवस्था दोष रहित नहीं है। क्या कोई बताएगा कि आखिर इस व्यवस्था के दोष कब दूर होंगे?

समस्या केवल यही नहीं है कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां उस कोलेजियम व्यवस्था के तहत हो रही हैं जिसकी विसंगतियां सामने आ चुकी हैं। समस्या यह भी है कि न्यायिक क्षेत्र की अन्य अनेक विसंगतियां भी दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। न्याय हासिल होने के बजाय तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम रहना एक हकीकत है। यह हकीकत निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक है। आखिर न्याय के लिए प्रतीक्षारत करोड़ों लोगों की चिंता कौन कर रहा है? यह ठीक नहीं कि चिंता के नाम पर कार्यपालिका और न्यायपालिका एक-दूसरे को नसीहत देती दिखें। आखिर दोनों पक्ष मिलकर न्यायिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई ठोस रूपरेखा तैयार करने के लिए आगे क्यों नहीं आते? यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि कानून मंत्री के रूप में रविशंकर प्रसाद इस बार न्यायिक सुधारों को गति देने के मामले किन्हीं ठोस उपायों पर अमल करते हुए दिखें। चूंकि उनके पास कानून मंत्रालय के साथ-साथ सूचना-प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्रालय भी है इसलिए उन्हें यह अवश्य देखना चाहिए कि आधुनिक तकनीक और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके न्यायिक तंत्र के उस मकड़जाल को कैसे काटा जाए जो करोड़ों लोगों की परेशानी का कारण है और जिसके चलते हमारी न्याय प्रणाली अपनी सुस्ती के लिए बदनाम है। एक वकील होने के नाते कानून मंत्री इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि मुकदमों को लंबित रखने के तौर-तरीके किस तरह न्याय प्रणाली का अलिखित हिस्सा बन गए हैं। यह ठीक नहीं कि जब हर क्षेत्र में सुधारों पर जोर है तब न्यायिक क्षेत्र में सुधार बहस तक सीमित हैं।

युवाओं को जगाएं

नशे को लेकर बिहार में काफी जागरूकता बढ़ रही है, यह सुखद संकेत है। इस मामले में दूसरे राज्यों के लिए भी बिहार प्रेरक बन रहा है। पहले की तुलना में बिहार के गांव-गिरांव, कस्बों और शहरों में लोग तंबाकू, तंबाकू निर्मित उत्पादों और शराब-गांजे जैसी नशीली वस्तुओं से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक हो रहे हैं। शराबबंदी ने बिहार में नशे को लेकर जो माहौल बनाया है, उसका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। अध्ययन के मुताबिक 2009-10 में राज्य में 53.5 फीसद लोग तंबाकू का सेवन करते थे, जबकि 2016-17 में मात्र 25.9 फीसद लोग ही तंबाकू का सेवन करते पाए गए। राज्य के 13 जिले पटना, मुंगेर, दरभंगा, कटिहार, समस्तीपुर, लखीसराय, वैशाली, मधेपुरा, जहानाबाद, मधुबनी, गोपालगंज, सहरसा एवं खगड़िया को तंबाकूमुक्त घोषित किया जा चुका है। जिले का तंबाकूमुक्त घोषित होना, दरअसल प्रतीकात्मक है। ऐसा नहीं कि इन जिलों में एक भी व्यक्ति तंबाकू का सेवन नहीं कर रहा होगा, लेकिन सरकार का अपना पैमाना है, जिसके आधार पर यह घोषणा की गई है। सौ प्रतिशत न सही, लेकिन बड़ी संख्या में लोग तंबाकू से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूक हुए हैं तो यह बड़ी बात है। इसे और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि देश में तंबाकू के सेवन करने से प्रतिवर्ष 12 लाख लोगों की मौत हो रही है। मुंह के कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू का सेवन है। तंबाकू से गला, फेफड़े, मूत्राशय, गुर्दा आदि का कैंसर हो रहा है। हृदय और रक्त संबंधी परेशानी हो रही है। कई मरीजों में प्रजनन संबंधी समस्या भी तंबाकू के सेवन से बढ़ रही है। पिछले दिनों राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा था कि स्कूलों एवं बच्चों को तंबाकू से दूर रखने के कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सक एवं पारा मेडिकल कर्मचारी विद्यालयों में जाकर बच्चों को तंबाकू से होने वाले नुकसान से अवगत करा रहे हैं।

कांग्रेस को भारी पड़ी उसकी भाषा

ए. सूर्यप्रकाश

जनादेश से स्पष्ट है कि कांग्रेस ने चुनाव अभियान में जितनी बदजुबानी की उसका प्रदर्शन उतना ही खराब रहा। घोर असंवेदनशीलता पर मतदाताओं ने उसे कड़ा सबक सिखाया

लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। भाजपा की यह भारी-भरकम जीत जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और निर्णायक नेतृत्व के पक्ष में सकारात्मक मतदान की परिचायक है उतनी ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके साथियों द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित भाषा में चलाए गए अभियान के खिलाफ नकारात्मक वोटिंग की भी प्रतीक है।

नेहरू-गांधी परिवार दशकों से लुटियन दिल्ली के बंगले में रहता आया है। इस बीच ऐसा दौर भी आया जब इस परिवार के पास कोई अधिकार नहीं बचा कि वह यहां मिले बंगले में रहे। फिर भी यह सिलसिला चलता रहा। नेहरू-गांधी परिवार इसे अपनी थाती मानता रहा है। वह दिल्ली के हृदय स्थल माने जाने वाले इस इलाके को मोदी के लायक नहीं समझता। वहीं मोदी जबसे नेहरू-गांधी परिवार के प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरे हैं तबसे यह परिवार और उसके कुछ खास दरबारी मोदी के खिलाफ हमलावर होने में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा भी लांघते रहे हैं। वे यह भी दोहराते रहे कि मोदी में प्रधानमंत्री बनने वाली कोई 'विशिष्ट बात' नहीं है। वह तो बस चाय बेचने के लिए ही ठीक हैं। जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ही नेहरू-गांधी परिवार उन्हें निशाना बनाता आया है। इसी कड़ी में सोनिया गांधी ने उन्हें 'मौत का सौदागर' तक कह दिया था।

तब से मोदी लगातार जुबानी हमले झेल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तो राहुल गांधी ने उन्हें 'चोर' तक कहना शुरू कर दिया। अपने गरीब परिवार की मदद के लिए मोदी ने बचपन में रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय भी बेची है। उनकी ऐसी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उनकी आलोचना में तो कांग्रेस को और ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। वैसे तो नेहरू-गांधी परिवार महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन के मूल सिद्धांतों को ही अपनी राजनीतिक विरासत होने का दावा करता रहा है, लेकिन मोदी पर उनकी टिप्पणियां उससे मेल नहीं खातीं। मतदाता को मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियां अपमानजनक और मन को ठेस पहुंचाने वाली लगीं। इससे लगा कि साधन-संपन्न कुलीन नेहरू-गांधी परिवार वंचित वर्ग के एक साधारण व्यक्ति के उभार का मखौल उड़ा रहा है। ऐसे में लोकतंत्र ने अपना असर दिखाते हुए देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल को उसकी घोर असंवेदनशीलता का कड़ा सबक सिखाया।

ऐसे में चुनावी नतीजों से स्पष्ट है कि कांग्रेस ने अभियान में जितनी बदजुबानी की उसका प्रदर्शन उतना ही खराब रहा। आखिर इन नतीजों का कांग्रेस पार्टी और उस पर काबिज नेहरू-गांधी परिवार के लिए क्या निहितार्थ है?

दरअसल पुरानी आदतें जल्दी से पीछा नहीं छोड़तीं और कांग्रेस ने गरिमा के साथ हार को स्वीकार भी नहीं किया और वह अब भी हकीकत से मुंह फेर रही है। वर्ष 2004 में महज 26.53 प्रतिशत वोटों के साथ 145 सीटें पाकर कांग्रेस सत्ता में आई। वर्ष 2009 में उसे 28.55 प्रतिशत वोट मिले और 206 सीटें हासिल हुईं। इस तरह सोनिया गांधी अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री रहीं और औसतन 28 प्रतिशत लोकप्रिय वोटों के साथ देश पर दस साल शासन किया। फिर भी इस पार्टी के नेता 2014 में मोदी सरकार के औचित्य पर सवाल उठाते रहे कि उसे महज 31.34 फीसद मत मिले हैं जबकि हकीकत में भाजपा को 282 सीटें हासिल हुई थीं। वे फिर से मोदी की हालिया जीत पर सवाल उठा रहे हैं जबकि भाजपा ने 37.40 प्रतिशत वोटों के साथ 303 सीटें हासिल की हैं। उसका कहना है कि 60 प्रतिशत मतदाताओं ने मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट दिया है। यह पूरी तरह निराधार है, क्योंकि भाजपा राजग का हिस्सा है और इस गठजोड़ को 45 प्रतिशत वोट हासिल हुए हैं।

ये दलीलें बहुत संदिग्ध हैं। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू को भी 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव में केवल 45 प्रतिशत वोट मिले थे। उस समय लोकसभा की 489 सीटों में से कांग्रेस ने 364 सीटें हासिल की थीं। पार्टी को विपक्ष की ओर से कोई चुनौती भी नहीं मिली थी। उस समय छोटे-छोटे दलों वाला विपक्ष पूरी तरह छिन्न-भिन्न था। तब भाजपा के पूर्व स्वरूप भारतीय जनसंघ को मात्र तीन सीटें मिली थीं। यानी कांग्रेस को मिली सौ सीटों पर जनसंघ को एक सीट हासिल हुई थी। 1957 में कांग्रेस की सीटें बढ़कर 371 हो गईं और उसे 48 फीसद मत मिले। 1962 में फिर 45 प्रतिशत मत मिले और सीटें भी घटकर 361 रह गईं। अब मौजूदा हालात पर गौर करें तो भाजपा के नेतृत्व वाले राजग ने लोकसभा में 358 सीटें हासिल की हैं जिनमें से 303 अकेले भाजपा की हैं। दूसरे पायदान पर रही कांग्रेस 52 सीटों के साथ उससे बहुत पीछे है जिसकी स्थिति में पिछली लोकसभा की 44 सीटों की तुलना में मामूली सुधार हुआ है। अभी तक के सभी चुनावों में कांग्रेस की पहचान अखिल भारतीय पार्टी की रही जो देश के सभी कोनों से जीतकर आती रही। अब उसकी यह जगह भाजपा ले रही है।

अवधेश राजपूत

मतदाताओं की परिपक्वता इस चुनाव का सबसे खास पहलू बनकर उभरी है। ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने अपनी पसंद को लेकर परिपक्वता का पूरा परिचय दिया। पांच महीने पहले ही भाजपा हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में चुनाव हार गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वहां मतदाताओं ने भाजपा को निर्णायक जनादेश दिया। यह राज्य और राष्ट्रीय स्तर के चुनावों में स्पष्ट रूप से अंतर को निर्धारित करता है। इस मायने में ओडिशा का जनादेश तो और भी अलग है जहां मतदाता लोकसभा और विधानसभा के लिए एक साथ दो अलग-अलग मशीनों पर मतदान कर रहे थे। राज्य की 21 लोकसभा सीटों में यहां की जनता ने 12 सीटों पर बीजू जनता दल को कामयाबी दिलाई तो आठ सीटें भाजपा के खाते में गईं। हालांकि राज्य विधानसभा में स्थिति एकदम उलट रही जहां 146 में से 113 सीटें बीजू जनता दल को मिलीं जो 75 फीसद सीटों से भी अधिक हैं। यहां भाजपा को केवल 23 सीटों के साथ ही संतोष करना पड़ा। इस प्रकार लोकसभा में जहां मोदी के पक्ष में हवा चल रही थी तो राज्य के नेतृत्व के लिए नवीन पटनायक स्पष्ट रूप से जनता की पहली पसंद थे।

ऐसी परिपक्वता हमारे लोकतंत्र के लिए बेहतर है, क्योंकि राज्य और स्थानीय स्तर के चुनाव अक्सर जाति और अन्य विभाजनकारी मुद्दों पर लड़े जाते हैं जबकि लोकसभा चुनाव एक नेता, एक पार्टी और एक ऐसे विचार के इर्दगिर्द केंद्रित होते हैं जो इन दरारों को भरता है। इससे जीतने वाली पार्टी के लिए कहीं अधिक उदार मतदाताओं का आधार तैयार होता है।

भाजपा स्पष्ट रूप से अपना विस्तार कर रही है। अगर उसके विस्तार की यही गति बरकरार रही तो अगली बार चुनावी नक्शे में वह कांग्रेस का वही करिश्मा दोहराती नजर आएगी जो 1957 और 1962 में नेहरू के दौर में कांग्रेस ने किया था। तब लगभग हर राज्य में उसके सांसद थे। अब कांग्रेस को आत्ममंथन में जुटना चाहिए जिससे वह पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के उपाय तलाशे। बिल्कुल वैसे जैसे 1984 में दो सीटों पर सिमटने के बाद भाजपा ने किया था।

(लेखक प्रसार भारती के चेयरमैन एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

गुणवत्तापरक रोजगार की दरकार

डॉ. भरत झुनझुनवाला

हम नए तकनीकी आविष्कारों को नहीं रोक सकते तो हमें यह देखना होगा कि उनमें पर्याप्त रोजगार सृजित हो सकें

एटीएम के आने से बैंक में कैशियर की नौकरियां कम हो गईं। मोबाइल फोन के आने से एसटीडी बूथ का धंधा चौपट हो गया। ऐसी अंतहीन मिसालें हैं। मगर इसकी हकीकत यही है कि नई तकनीक अपने साथ जहां कुछ पुराने रोजगारों को समाप्त करती है तो वहीं कुछ नई किस्म की नौकरियां भी सृजित करती है। यानी तकनीक के साथ रोजगार पर बड़ा संकट नहीं आया है। मसलन एटीएम आया तो उसके रखरखाव और संचालन के क्षेत्र में नौकरियां सृजित हुईं तो मोबाइल फोन के आने से उनकी मरम्मत का काम कई लोगों की आजीविका चला रहा है। कुल मिलाकर नई तकनीक हमेशा कुछ न कुछ हलचल भी मचाती है और आने वाले समय में इससे जुड़ी उठापटक और तेज होने के आसार हैं। इस कड़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ का नाम बड़े जोर-शोर से लिया जा रहा है। इसमें शोध के लिए वैज्ञानिकों की जरूरत कम होगी। स्वचालित गाड़ियों से वाहन चालकों का रोजगार चौपट हो सकता है। हम इन नए अविष्कारों को रोक नहीं सकते हैं और उन्हें रोकना भी नहीं चाहिए। प्रश्न इन तकनीकी आविष्कारों को रोकने का नहीं है। प्रश्न है कि नए कार्यों में नए रोजगारों का पर्याप्त मात्रा में सृजन हो। एम्प्लॉयमेंट एनालिसिस नाम की वेबसाइट के अनुसार 1900 में अमेरिका में 1,09,000 घोड़ा गाड़ी चलती थीं और बिजली मिस्त्री नगण्य थे। 2002 में घोड़ा गाड़ी शून्य प्राय हो गईं जबकि बिजली मिस्त्रियों की संख्या 8,82,000 हो गई। यानी जितना पुराने रोजगार का हनन हुआ उससे दस गुना नए रोजगार सृजित हुए।

अर्थशास्त्रियों के बीच सहमति नहीं है कि नई हलचल से कितने रोजगारों का हनन होगा। कार्ल बेनेडिक्ट द्वारा किए गए एक अध्ययन में आकलन किया गया कि अमेरिका के 47 प्रतिशत रोजगार संकट में पड़ सकते हैं। विश्व बैंक ने इस आकलन का गहन अध्ययन कराया और अनुमान लगाया कि केवल नौ प्रतिशत रोजगार का हनन होगा। यदि 47 प्रतिशत रोजगार का हनन होता है और 60 प्रतिशत रोजगार नए बनते हैं तो सुखद है। यदि नौ प्रतिशत का हनन होता है और केवल चार प्रतिशत नए बनते हैं तो दुखद है। अतः हमारा ध्यान होना चाहिए कि नए रोजगार सृजित हों।

मैं आशावादी हूं। मुझे भरोसा है कि कितने भी पुराने रोजगारों का हनन हो, उससे ज्यादा नए रोजगार बन सकते हैं। मान लीजिए कोई किसान अपनी फसल के लिए सप्ताह में छह दिन काम करता था। अब बिजली, ट्रैक्टर और इंटरनेट ने उसके लिए संभव बना दिया है कि वह चार दिन के काम से भी उतना ही उत्पादन कर सकता है। इससे दो दिन अतिरिक्त मिल गए। इन दो दिनों में वह कोई नया काम सीखकर उससे फायदा उठा सकता है। यानी समय के सदुपयोग से नए रोजगारों का सृजन होगा।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के एक अध्ययन के अनुसार नई तकनीकों के कारण उच्च क्षमता के इंजीनियरों के रोजगार का भारी मात्रा में सृजन होगा। मध्यम क्षमता के कर्मियों की जरूरत बहुत कम हो जाएगी और निम्न क्षमता के कर्मियों के रोजगार में भी वृद्धि होगी। आने वाले समय में केवल उच्च और निम्न वर्ग रह जाएंगे। माध्यम वर्ग का सफाया हो जायेगा। अतः चुनौती इस बात की है कि हम उच्च क्षमता के अधिक संख्या में रोजगार बनाएं।

उच्च रोजगार नई तकनीकों पर आधारित होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिकी दबदबे का मूल कारण है कि अमेरिकी सरकार ने नई तकनीकों के विकास को व्यापक आर्थिक समर्थन दिया है। जैसे इंटरनेट का आविष्कार अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा दिए गए अनुदान से हुआ था। परमाणु ऊर्जा का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी सेना द्वारा किया गया था, लेकिन अपने देश में सरकार अनुदान उन लोगों को देती है जो नई तकनीक के सृजन को रोकते हैं। कुछ समय पहले एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर से चर्चा हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपका मन कैसे लगता है? वह बोले कि मैं तो 40 साल से 'कुछ न करने' का आदी हो गया हूं। उन्हें 1.50 लाख रुपये प्रति माह का वेतन मिलता होगा। वैज्ञानिक बताते है कि यदि कोई वैज्ञानिक वास्तव में शोध करना चाहता है तो पूरी व्यवस्था उसका विरोध करने लगती है। कारण कि यदि एक वैज्ञानिक ने नई खोज कर ली तो बाकी तमाम शिथिल पड़े वैज्ञानिकों के कार्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। सभी वैज्ञानिक कार्य न करें तो किसी को भी परेशानी नहीं है, लेकिन 100 में से यदि दो काम करें तो 98 की नौकरी पर संकट आता है। इसलिए हमारी सरकार उन 98 लोगों के हितों की रक्षा करती है जोकि तकनीकी आविष्कार नहीं होने देते हैं। यही कारण है कि देश में इतने सस्ते मूल्य पर उच्च वैज्ञानिक उपलब्ध होने के बावजूद हम तकनीकी आविष्कार में पीछे हैं। भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में जाकर अच्छा कार्य करते हैं और अपने देश में अपनी ही सरकार उन्हें अच्छा कार्य करने से रोकती है।

राजग सरकार वाईफाई को पूरे देश में फैलाएगी जो कि सही दिशा में कदम है, लेकिन रोजगार सृजन तभी हो पाएगा जब शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। पहली बात है कि विश्वविद्यालयों में राजनीतिक दबाव में कुलपतियों की नियुक्ति पर रोक लगानी चाहिए। सरकार को अधिकार है कि अपनी विचारधारा के अनुरूप लोगों को नियुक्त करें, पर अपनी विचारधारा के अक्षम लोगों की नियुक्ति उचित नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था वैचारिक भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो गई है। सरकार को चाहिए कि पहले सक्षम लोगों का पैनल बनाए। उसके आधार पर ही नियुक्ति का निर्णय ले।

दूसरा काम यह है कि सभी विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थाओं में अध्यापकों एवं वैज्ञानिकों को स्थायी नौकरी देने के स्थान पर पांच वर्षीय अनुबंध पर रखा जाए। मैं फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में पढ़ता था। हमारे 40 में से केवल दो प्रोफेसरों को स्थायी नियुक्ति दी गई थी। बाकी सभी का पांच वर्ष पर मूल्यांकन होता था और उसी आधार पर नवीनीकरण। मूल्यांकन में छात्रों, एक बाहरी संस्था और अपने ही सहयोगियों तीनों की सहभागिता होनी चाहिए। तीसरा कदम है कि शैक्षिक संस्थाओं को दी जा रही रकम को उनके द्वारा किए गए कार्य से जोड़ देना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में प्रोफेसरों के कितने पर्चे प्रकाशित हुए, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स से कितनी रकम जुटाई, इत्यादि को देखते हुए ही इन संस्थाओं को रकम देनी चाहिए। इन कदमों को लागू कर नई सरकार भारत में उच्च कोटि के तमाम रोजगार का सृजन भी कर सकेगी और भारत वास्तविक मायने में महाशक्ति भी बन सकेगा।

(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलूर के पूर्व प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अहिंसा

अहिंसा का अर्थ प्रेम होता है। किसी को न सताना, न मारना। प्राणिमात्र को दुख न देना ही अहिंसा है। हिंसा दो प्रकार की होती है-स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल हिंसा है-किसी को मार डालना, अंग-भंग कर देना, शोषण एवं अपमानित करना, व्यंग्य एवं ताने मारना, शस्त्रों का प्रयोग करना आदि। सूक्ष्म हिंसा है-मन में किसी के प्रति दुर्भाव रखना, घृणा करना, राग-द्वेष रखना, किसी को मानसिक रूप से सताना। दूसरे शब्दों में कहें तो मन में सूक्ष्म हिंसा भरी रहना, जो जरा सी चिंगारी देखते ही बारूद की भांति भभक उठे। आज सर्वत्र हिंसा का दावानल सुलग रहा है। इसी स्थिति से त्राण पाने का उपाय है-अहिंसा।

योग की आठ सीढ़ियों में प्रथम सीढ़ी अहिंसा है। हम परिवार में रहते हैं। समाज में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में हमारा सैकड़ों लोगों से संपर्क होता है। व्यवहार में अहिंसा की साधना का श्रीगणेश यहीं से किया जा सकता है। घर-परिवार, समाज, पड़ोस में, जहां कहीं भी किसी व्यक्ति के संपर्क में हम आएं तो लोगों से प्रेम से मिलें, प्रेम का व्यवहार करें। हमारा आचरण प्रेममय हो। व्यवहार-बातचीत प्रेममय ही हो। यह सत्य है कि प्रेम का मार्ग जटिल होता है। उसमें त्याग करना होता है, बलिदान करना पड़ेगा, निजी स्वार्थ छोड़ना होगा। उसमें सहनशीलता, उदारता, क्षमा, करुणा, दया और नम्रता जैसे सद्गुणों का विकास करना होता है। अर्थात प्रेम को जीवन में उतारना ही अहिंसा का पदार्थ-पाठ है। यदि हमारे हृदय में प्रेम भर जाए, फिर तो हिंसा अपने आप चली जाएगी।

किसी को मारने की, सताने की, कष्ट पहुंचाने की भावना तभी बढ़ती-पनपती है, जब हम उसे 'पराया' समझने लगते हैं। क्या अपनों को कोई सताता या कष्ट पहुंचाता है? यदि हम सभी लोगों को 'अपना' स्वीकार कर लें तो अहिंसा की साधना सफल हो जाएगी। फिर तो समस्त विश्व एक कुटुंब बन जाएगा। 'मेरा'-'तेरा' का कोई भाव नहीं होगा। हम विश्व परिवार के सदस्य बन जाएंगे। हमारा किसी से झगड़ा, घृणा और विरोध नहीं होगा। हमारे जीवन, वाणी, व्यवहार से अहिंसा-धर्म स्वयमेव मुखरित होने लगेगा। कठिन तो है, फिर भी यह साधना करने जैसी है। आइए, सच्चे मन से हम, सच्चे हृदय से इस अहिंसा धर्म के पालन का व्रत ले लें।

डॉ. विजय प्रकाश त्रिपाठी

जहरीली शराब का धंधा

अंशुमाली रस्तोगी

देश में शराब के सेवन से न जाने कितनी मौतें होती हैं, फिर भी इसकी बिक्री में कहीं कोई कमी नहीं आ रही है

सूरत के कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग की लपटें अभी शांत भी नहीं हो पाई थीं कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जहरीली शराब ने 23 लोगों की जान ले ली। कोई तीन माह पहले भी इसी जगह जहरीली शराब 91 लोगों का जीवन लील चुकी है। शराब समाज और इंसान के लिए नासूर है। न जाने कितनी मौतें शराब के सेवन से देश में होती हैं फिर भी न तो इसकी बिक्री में कहीं कोई कमी आई है न पीने वालों में। खुद को संभ्रांत कहने वाला तबका तो शराब पीने-पिलाने को अपनी शान समझता है। वह यह सोचने की भी जहमत नहीं फरमाता कि जिस जहर को वह पी रहा है उसके नुकसान कितने भयाभय हैं।

जहरीली शराब का धंधा उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हर जगह जोरों पर है। यह तब है जब अवैध शराब के धंधे पर लगाम कसने के लिए सरकार ने आबकारी अधिनियम में बदलाव करते हुए नकली शराब से हुई मौत के मामले में आरोपी को सजा-ए-मौत तक का प्रावधान किया है। साथ ही अधिकारियों की मिलीभगत और लापरवाही पाए जाने पर बर्खास्तगी का भी प्रावधान है, लेकिन यहां नियम-कानून को मानता कौन है? हर बड़ी घटना के बाद कुछ अधिकारियों पर बर्खास्तगी की गाज गिरती जरूर है, पर थोड़े दिनों में हालात सामान्य होते ही वही सब फिर से चालू हो जाता है। बेशर्मी की हद यह है कि डर न अधिकारियों के मन में रह गया है न संलिप्त गुनहगारों के। डंके की चोट पर शराब का अवैध कारोबार जारी है। देते रहिए आप व्यवस्था को दोष यहां सुनने वाला है कौन? मौत का कारोबार बेखटक जारी है। शराब एक ऐसा धीमा जहर है, जो धीरे-धीरे हमें भीतर से गलाता जाता है। कुछ इस जहर से समय रहते संभल जाते हैं, जो नहीं संभल पाते उनके लिए अंतिम रास्ता मौत का ही बचता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की शराब एवं स्वास्थ्य स्टेटस रिपोर्ट (2018) के अनुसार विश्व में वर्ष 2016 में शराब से 30 लाख मौतें हुईं। इसमें पुरुषों की 23 लाख और महिलाओं की 7 लाख मौतें शराब के कारण हुईं। कच्ची शराब का सबसे ज्यादा चलन गांवों-देहातों में है। सस्ती शराब के लालच में वे क्या पी रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता। कुछ पलों के वास्ते दिल को खुश करने या गमों को भुलाने के लिए शराब की शरण में जाना, मौत के मुंह में जाने जैसा है। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से बर्बाद हुए परिवारों को न्याय जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन किसी का बेटा, किसी का पति तो जहर की भेंट चढ़ ही गया। उन्हें तो वापस कोई नहीं ला सकता। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि कच्ची शराब पर पाबंदी लग ही जाएगी या लोग पीना छोड़ देंगे।

शराबबंदी के लिए चाहे जितने नियम-कानून बना लिए जाएं, कुछ लोगों ने तो जैसे कसम ही खा रखी है कि वे कुछ नहीं मानेंगे? चंद पैसों के लिए वे किसी की जिंदगी से खेल जाने में भी नहीं हिचकते। यह तो तब है जब शराब के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में कितना-कितना विज्ञापनों में कहा-बताया जाता है, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं कर सकता जिन्हें इस जहर को हर कीमत पर पीना ही पीना है। चाहे वे अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठें या उनका परिवार ही क्यों न उजड़ जाए। बाकी दिल की तसल्ली को कहते-मानते रहिए कि शराब बुरी बला है, इससे बचें।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

देश में आया चुनावी बदलाव

'मुस्लिम महिलाओं ने भी मुमकिन बनाई जीत' शीर्षक से लिखे अपने लेख में एमजे अकबर ने मोदी सरकार की जनहितैषी नीतियों के प्रति मुस्लिम महिलाओं के बढ़ते आकर्षण को जिस चुनावी बदलाव के रूप में रेखांकित किया है, वह अब इस देश की हकीकत बनता जा रहा है। वस्तुतः 'बांटो और राज करो' की नीति का अनुसरण करने वाली कांग्रेस ने बहुत दिनों तक अल्पसंख्यक के नाम पर मुस्लिम वर्ग को इस देश की बहुसंख्यक जनता से अलग करते हुए यही दोहराया कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। जबकि 2014 में पूर्ण बहुमत से आने वाली मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास की समावेशी नीति के अनुरूप केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को बिना किसी भेद-भाव के देश की सवा सौ करोड़ जनता के लिए लागू किया और उसको भ्रष्टाचारमुक्त तरीके से धरातल तक पहुंचाया। कश्मीर में पाक-पोषित आतंकवाद पर प्रहार करते हुए उन्होंने देश के शांतिप्रिय मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं होने दिया। पहली बार आतंकग्रस्त कश्मीर घाटी को छोड़कर देश के किसी हिस्से में आतंकी बम विस्फोट नहीं हुए। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर देश के किसी हिस्से में कोई सांप्रदायिक दंगा भी नहीं हुआ। इस बदलाव ने देश के मुस्लिम वर्ग को यह सोचने के लिए विवश कर दिया कि मुस्लिम वर्ग का हित देश की मुख्यधारा से कटकर अल्पसंख्यक के झूठे तमगे में नहीं है, बल्कि देश के साथ जुड़कर मोदी की विकासपरक नीतियों को आत्मसात करने में है। मुस्लिम वर्ग का यह मानसिक बदलाव मोदी की प्रचंड जीत का कारण बना। इस बदलाव ने विपक्ष की चुनावी रणनीति को ध्वस्त करते हुए मोदी के सुशासन के प्रति जैसा विश्वास व्यक्त किया, वह परिणामजनक रहा। यह

मेलबाक्स

चुनावी बदलाव विपक्ष के लिए अकल्पनीय था। कर्नाटक की तरह चुनाव के बाद एकजुट होने की प्रक्रिया में जुटने वाले विपक्ष को यह उम्मीद नहीं थी कि इस बार के चुनावी बदलाव से उनके सभी जातीय और सांप्रदायिक समीकरण धराशायी हो जाएंगे। यह चुनावी बदलाव देश के हित में रहा, क्योंकि इससे देश के लिए जरूरी पूर्ण बहुमत की केंद्र सरकार बन गई।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

सौदेबाजी स्वीकार नहीं

भाजपा गठबंधन के सहयोगी दलों को साथ लेकर चल रही है, लेकिन सहयोगी दल उसकी मजबूरी नहीं हैं। मजबूत और पूर्ण बहुमत वाली सरकार के तानाशाही रवैया अख्तियार करने की अशंका रहती है, लेकिन देश के लोकतंत्र में ऐसा हो पाना न तो सरल है और न ही अच्छा। पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी नीतियों को ठीक से लागू कर पाती है। गठबंधन की सरकारों में सौदेबाजी ज्यादा होती है। भाजपा सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चल रही है। इसके साथ ही दबाव की राजनीति वह स्वीकार नहीं करेगी। यह भी पार्टी ने साफ कर दिया है।

युधिष्ठिर लाल कक्कड़, गुरुग्राम

विकास के नाम पर वोट

23 मई का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। उस दिन भारत की जनता ने यह सिद्ध कर दिया कि वह धर्म-जाति बंधन से मुक्त होकर विकास के मुद्दे पर वोट करती है। उसने न केवल जातिवाद के आरोप को नकारा, बल्कि वंशवाद एवं परिवारवाद की धज्जियां भी उधेड़ दी। जातिवादी गठबंधनों को निरुत्साहित किया। भाजपा ने अपने बलबूते दोबारा पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। सहयोगी दलों को भी अधिक सफलता प्राप्त हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के विधान सभा चुनावों में अपनी पराजय से भी भाजपा को फायदा ही हुआ। कांग्रेस को इतने अल्प समय के शासन में ही सत्ता विरोधी क्रोध का शिकार होना पड़ा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के उपचुनावों में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उससे सीख लेते हुए पार्टी ने कारगर उपाय किए और वहां भी जीत हासिल की।

dharmendranath.rastogi@gmail.com

ई-रिक्शा चालकों की मनमानी

दिल्ली विवि के नार्थ कैंपस के मेट्रो स्टेशन पर ई-रिक्शा वाले मनमानी कर रहे हैं। आमतौर पर यहां से किसी भी कॉलेज में आने-जाने के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपये निर्धारित है, लेकिन ये छात्र-छात्राओं से 20 रुपये वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं, चार सवारी के स्थान पर पांच-छह सवारी बैठा रहे हैं। इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस व अन्य संबंधित विभाग संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करें, जिससे उनकी मनमानी पर रोक लग सके।

विजय कुमार धनिया, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

आजकल

बड़ी चुनौती क्यों बन गई है लू

आंकड़ा है कि 1992 से 2016 के बीच देश में सिर्फ लू से मरने वालों की संख्या 25 हजार से ज्यादा रही है। इसके बावजूद लू को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जाता। यहां तक कि भारतीय मौसम विभाग भी लू के गंभीर थपेड़ों के बावजूद चेतावनी के रूप में रेड अलर्ट घोषित नहीं करता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकारों को शायद लू की कोई फिक्र इसलिए नहीं होती, क्योंकि इससे प्रभावित होने या मरने वालों में ज्यादातर गरीब ही होते हैं?

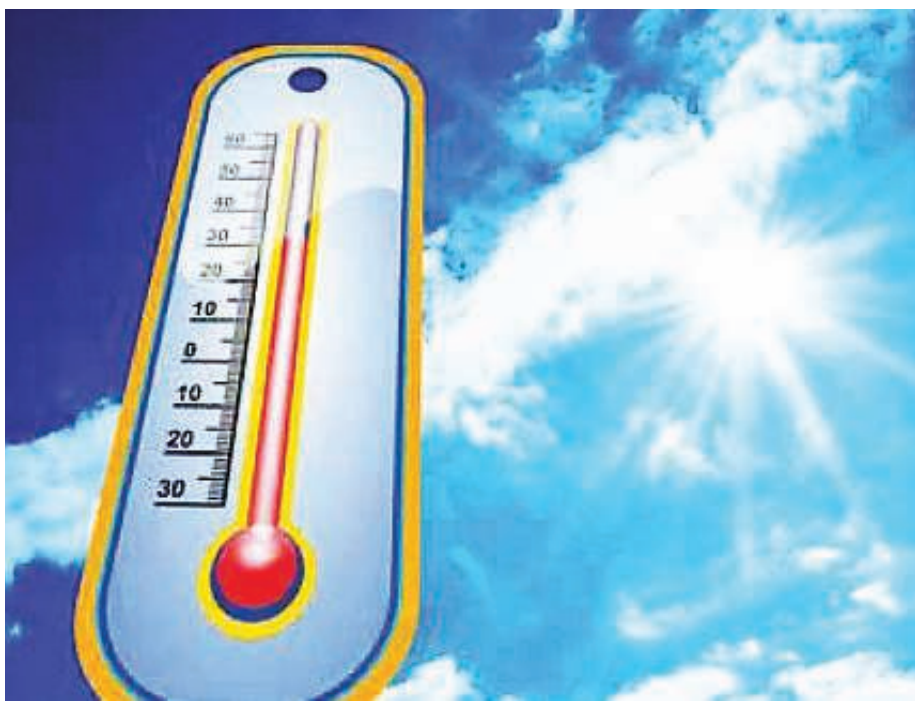

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था एफएसआइ ग्लोबल से संबद्ध

देश भयंकर गर्मी और लू की चपेट में है। उत्तर भारत के मैदानी इलाके हों या दक्षिण के पठार, हर जगह लोग गर्मी से परेशान हैं। इस मौसम में लोगों को पहाड़ से राहत मिलती थी, पर अभी तो हालत यह है कि पहाड़ भी तप रहे हैं। वहां जंगलों की आग ने अलग से समस्या खड़ी कर दी है, जो धुएं के साथ अतिरिक्त गर्मी पैदा करके लू की आपदा को और बढ़ा रही है। मौसम विभाग ने यलो अलर्ट घोषित कर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी यूपी और राजस्थान के लोगों को सचेत किया है कि उन्हें अभी गर्मी का प्रकोप सहना ही होगा। दिनोंदिन चढ़ते पारे से दक्षिण और पश्चिम राज्यों तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी लोगों का हाल-बेहाल है। भीषण गर्मी तेलंगाना में तीन हफ्तों में 17 लोगों की जान ले चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में 30 मई को तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस (पालम वेधशाला) दर्ज कर दावा किया गया कि यह दिल्ली में पिछले आठ साल में मई महीने का सबसे ऊंचा तापमान था। वर्ष 2013 के बाद पहली बार पारा इस स्तर पर पहुंचा है। कोई नहीं जानता कि अब गर्मी कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी और लू की बढ़ती ताकत कैसा रंग दिखाएगी, क्योंकि तीखी गर्मी और प्रलयंकारी लू को अभी हमारे देश में राष्ट्रीय आपदा नहीं माना जाता है और इसकी भीषणता को यलो-ऑरेंज अलर्ट तक सीमित कर दिया जाता है। सवाल है कि लू कहां से आती है? हमारा देश और समाज इससे आखिर कैसे निपट सकता है? और क्या इसे अब एक राष्ट्रीय आपदा के तौर पर देखने की जरूरत नहीं बन गई है, क्योंकि साल-दर-साल बढ़ते पारे से होने वाले नुकसान बढ़ते ही जा रहे हैं?

मौसम विभाग कहता है कि जब हवा में नमी नाममात्र बी नहीं हो तो ऐसी स्थितियों में आसमान में तपता सूरज शुष्क हवा को बहुत तेजी से गर्म करता है। इन स्थितियों में सतह के नजदीक रहने वाली हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है और लू के थपेड़ों में बदल जाती है। वैज्ञानिकों का मत है कि अगर गर्मियों में तापमान औसत से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहता है तो इन हालात में लू पैदा होने यानी हीट वेव और एक्सट्रीम हीट वेव की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। दावा किया जा रहा है कि पिछले एक दशक में लगातार गर्मी कायम रहने की जैसी स्थितियां इधर बनी हैं, वैसी पहले कभी नहीं हुईं। इसमें एक भूमिका मौसमी परिघटना अल नीनो की भी देखी जा रही है, जिसकी सक्रियता के बारे में मौसम विभाग पहले ही सचेत कर चुका है।

असल में अल नीनो के कारण प्रशांत महासागर का पानी बेहद गर्म हो गया है, जिससे समुद्री हवाएं एशियाई भूभाग की ओर मुड़ नहीं पा रही हैं जो यदि यहां आ जाएं तो उनसे जमीनी सतह का तापमान कम हो सकता है। हालांकि इसे इस तरह भी देखा जा रहा है कि यह प्रचंड गर्मी मानसूनी बादलों के आने का रास्ता बना रही है। यूं तीखी गर्म हवाओं की शक्ल में चलती लू को पहचानना मुश्किल नहीं है, लेकिन परिभाषा में देखना चाहें तो सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक लू यानी हीट वेव सामान्य रूप से रहने वाले अधिकतम तापमान से कहीं ज्यादा तापमान होने के दौरान देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में मार्च से जून के बीच चलने वाली गर्म हवा है। भारतीय मौसम विभाग ने लू या गर्म हवाएं चलने के संबंध में जो पैमाने तय किए हैं, उनमें से एक मानदंड के अनुसार मैदानी इलाकों में जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी इलाकों में पारा 30 डिग्री से ऊपर हो जाए तो लू चलने के आसार बनते हैं। वैसे तो अब हर किस्म के अतिवादी मौसम के नए से नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, पर तथ्यों के मुताबिक 2001 से 2010 का दशक रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म दशक था। लगता है कि 21वीं सदी का बीतता हुआ यह दूसरा दशक इस मामले में और भी आगे निकल सकता है।

उल्लेखनीय बात यह है कि गर्मी और लू के मामले में शहर देश के गांव-देहात से आगे निकलने को हैं, बल्कि अब तो दावा किया जा रहा है कि 'अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट' नामक प्रभाव शहरी आबादी के लिए हालात और मुश्किल कर रहा है, क्योंकि सीमेंट-कंक्रीट से बने इमारत की शक्ल वाले इन जंगलों में गर्मी सोखने के कम और गर्मी बढ़ाने के ज्यादा उपाय किए जा रहे हैं। इमारतों में लगे एयरकंडीशनर, फ्रिज और वॉटर कूलर जैसे इलेक्ट्रिकल सामान अपने आसपास के वातावरण में इतनी गर्मी फेंकते हैं जिनसे शहरों का तापमान गांवों की तुलना में 1 से 3 डिग्री ज्यादा तक बढ़ जाता है। इस पर सड़क पर रेंगती लाखों कारों का धुआं हालात को और बिगाड़ने वाला साबित होता है जो शहरों को ग्रीन हाउस गैसों के चैंबर में बदलकर सारी गर्मी शहरों के ऊपर ही कैद हो जाने देता है।

हालांकि मौसम की चाल समझने वाले कहते हैं कि अगर मानसून के फायदे लूटने हैं तो हमें गर्मी और लू को सहन करना ही होगा। ऐसे में अच्छा उपाय यही है कि यथासंभव लू का असर कम करने वाले इंतजाम किए जाएं। गर्मी का विज्ञान कहता है कि इंसानी शरीर 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहने करने योग्य बना है। जब आसपास का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो एक विपरीत प्रक्रिया शुरू हो जाती है और शरीर ऊष्मा को एकत्र करना शुरू कर देता है। फिर भी प्रकृति ने मानव शरीर की त्वचा से होकर जाने वाली पसीने वाली ग्रंथियों के जरिए एक प्रभावी शीतक प्रणाली बनाई है। जब शरीर गर्म होने लगता है तो शरीर से पसीना निकलने लगता है। जब जल वाष्पित होता है तो शरीर ठंडा होने लगता है। यह भौतिकी के उसी मूल सिद्धांत के अनुरूप है, जो कि मिट्टी के घड़ों में पानी को ठंडा रखता है।

शरीर का मूल तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाने के बाद भी कोई व्यक्ति बिना रुके बेहद गर्म स्थितियों में काम करता रहता है तो उसे लू लग जाती है और यह आमतौर पर एक घातक स्थिति होती है। लू लग जाने के बाद शरीर से पसीना आना बंद हो जाता है और तब सिर्फ आपात उपचार ही एकमात्र हल रह जाता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब भीतरी या बाहरी कारण से इस तापमान में ऊंच-नीच होती है। ऐसे में लू के दौरान गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए हर व्यक्ति दिन में औसतन 4 से 6 लीटर पानी पीए और हल्के रंग वाले कपड़े धारण करे। शरीर में पानी की कमी हो जाने की सूरत में आठ-दस लीटर पानी किसी इलेक्ट्रॉल के साथ पीना चाहिए।

इस गर्मी और लू की एक बड़ी विडंबना और भी है। असल में हर साल सैकड़ों मौतों के बावजूद केंद्र या राज्य सरकार के स्तर से इसका कोई ऐलान नहीं होता कि गर्मी से बचाने के लिए उनकी ओर से क्या उपाय किए जा रहे हैं। आंकड़ा है कि 1992 से 2016 के बीच देश में सिर्फ लू से मरने वालों की संख्या 25 हजार से ज्यादा रही है। इसके बावजूद लू को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जाता। यहां तक कि भारतीय मौसम विभाग भी लू के गंभीर थपेड़ों के बावजूद 'कोड रेड' चेतावनी के रूप में रेड अलर्ट घोषित नहीं करता है। यदि वह ऐसा करे तो इससे सरकार पर गर्मी से बचाने के आपातकालीन उपाय लागू करने का दबाव बनता है। सरकारों को शायद लू की कोई फिक्र इसलिए नहीं होती, क्योंकि इससे प्रभावित होने या मरने वालों में ज्यादातर गरीब ही होते हैं? यही नहीं, लू हमारी राष्ट्रीय चिंता में भी बड़ी मुश्किल से अटती है।

कहां गया प्याऊ और शर्बतों का सहारा

एक दौर था जब शहरों और कस्बों में हर दूसरे-तीसरे चौराहे पर लगे प्याऊ और किसी सेठ की तरफ से मुफ्त बांटा जाने वाला शर्बत तमाम गरीब-मजलूमों को लू की गर्मी सहन करने की ताकत देता था। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि गर्म मौसम की चपेट में आकर होने वाली मौतों का आंकड़ा गर्मी के प्रकोप के बजाय इस वजह से ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मौसम की मार से बचाने वाला हमारा जो सामाजिक तंत्र था, वह तार-तार हो गया है। धर्मार्थ प्याऊ जैसी जो चीजें गरीब तबके को हलक को जानलेवा हो जाने की हद तक सूखने से बचाती थीं, बाजारू ताकतों के आगे वे सब हवा हो गई हैं। हालात ये हैं कि आज आम आदमी प्यास बुझाने के वास्ते एक लीटर पानी के लिए न्यूनतम 15-20 रुपये चुकाने को बाध्य है।

गर्मियों का मौसम आते ही बसों, ट्रेनों और सार्वजनिक उपस्थिति वाली सभी जगहों पर अब यह आम बात हो गई है कि वहां बोतलबंद या सौ-दो सौ मिलीलीटर के पाउच तक में बिकने वाले पानी के दर्शन तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई सार्वजनिक हैंडपंप या नल (टैप) चालू हालत में दिखाई नहीं देता कि जिसका पानी पीकर तृप्त हुआ जा सके और जिसे पीने से बीमारियों के किसी खतरे का अहसास भी न हो। देश में अरसे तक परंपरा यह रही है कि रेल स्टेशनों, बस अड्डों और तमाम सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ हुआ करते थे। रेल स्टेशनों पर तो बाकायदा 'पानी पांडे' नाम से एक कमर्चारी नियुक्त रहता था, जो ट्रेन आने पर यात्रियों को मुफ्त में पानी पिलाया करता था। ऐसी सभी जगहों पर घड़ों में रखा साफ पेयजल भी लोगों को मुफ्त मिलता था। उसे पीकर लोग तृप्त होते थे, पानी पिलाने और उसकी व्यवस्था करने वाले को दुआ देते थे।

प्यासे को पानी पिलाना आज भी पुण्य का काम माना जाता है, पर ऐसे प्याऊ अब सिर्फ तीज-त्योहारों पर ही नजर आते हैं। इनके स्थान पर अब तकरीबन हर जगह बोतल या प्लास्टिक की थैलियों में सीलबंद पानी ही ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। देश में दान-पुण्य की परंपरा का एक बड़ा पहलू उस गरीब और वंचित तबके की कहे-अनकहे मदद से जुड़ा रहा है, जिसके सहारे ये लोग भूख और कुटिल मौसम की मार से किसी हद तक लड़ सकें। दुनिया ऐसे ही कायदों से चलती आई है जिसमें कुछ लोग कमाई हुई दौलत का एक हिस्सा उन लोगों की मदद में खर्च करते थे जिन्हें या तो कुदरत ने इस लायक नहीं बनाया कि वे कुछ काम करके अपना पेट भर सकें या इतने गरीब हैं कि सर्दी-गर्मी के अतियों में खुद को महफूज रख पाने के उपाय नहीं कर पाते।

दानी महात्मा लोग तो पेड़ लगवाने से लेकर धर्मशाला-अस्पताल बनवाने का काम इसीलिए करते थे कि प्रकृति में चिड़िया-जीवों से लेकर इंसानों तक को वह जरूरी मदद मिल जाए, जिसके बगैर उनका जीना ही मुहाल हो जाता है।

यह भी एक विरोधाभासी विडंबना है कि सर्दियों में हर जगह से गरीबों के लिए रैन बसेरा बनाने की मांग उठती दिखाई देती है, सरकारी प्रबंधों के अलावा गैरसरकारी संगठन अपने स्तर पर इसकी व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं, पर गर्मियों में शीतल छांह देने वाला प्रबंध भी उतना ही जरूरी है-यह कोई नहीं सोचता। पहले शहरों तक में सड़क किनारे मौजूद घने-फलदार पेड़ इस भूमिका को निभा देते थे, पर अब तो तेज शहरीकरण की चाहत ने ऐसे वृक्षों का ही सफाया कर दिया है। ऐसे में तेज धूप में चलते इंसानों को कोई ठौर मिलना तो दूर, पक्षियों के बसेरे भी उजड़े हुए हैं।

खरी-खरी

हार के साइड इफेक्ट

डॉ. अतुल चतुर्वेदी

विद्वान कहते हैं कि जीत और हार जीवन के दो किनारे हैं। इस विषय में ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं। आमतौर पर राजनेताओं की खाल इतनी मोटी होती है कि हार के चाबुक का उन पर कोई खास असर होता नहीं। एक-आध चिंतन शिविर या समीक्षा बैठक के बाद बात आई-गई हो जाती है। पार्टी पुराने ढर्रे पर लौट आती है और कार्यकर्ता पुरानी खोल में लौट जाते हैं। हार के बाद मनुष्य प्रायः दार्शनिक हो जाता है और कई तरह के चिंतन उभरते हैं। कुछ ठीकरे ढूंढे जाते हैं तो कुछ सिर भी, ताकि उन सिरों पर इन ठीकरों को फोड़ा जा सके। इसके उपरांत प्रायः आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। भीतरघात, सांगठनिक कमजोरी, कुटुंब मोह, नेतृत्व पर प्रहार, सत्ता पक्ष पर संसाधनों का दुरुपयोग जैसे कारण तलाश कर उनकी आड़ में मुंह छुपाने की असफल कोशिश की जाती है। मीडिया की पंच लाइनें इसमें उत्प्रेरक का काम करती हैं, सूपड़ा साफ, धराशायी, चारों खाने चित्त, लहर, आंधी जैसे विशेषण एवं भाववाचक संज्ञाएं निराश पार्टी का मनोबल रसातल में पहुंचा देती हैं। अखबार हार के कई रूप बताते हैं, मसलन करारी, अप्रत्याशित, शर्मनाक।

फिलहाल हम चर्चा शर्मनाक हार पर ही केंद्रित रखेंगे, क्योंकि जनमत की दृष्टि में अप्रत्याशित जैसा तो कुछ था ही नहीं। जब मुकाबला कांटे का हो तो हार नजदीकी कही जा सकती है, पर यहां तो पलड़ा ही ऊंचा और नीचा था। यदि कोई नेता दिल पर ले लेता है तो इस्तीफा दे देता है। फिर इस्तीफों की झड़ी लग जाती है। इस्तीफों की अपनी राजनीति होती है और अपने मंतव्य। कुछ इस्तीफे दिए जाते हैं तो कुछ लिए। कुछ वापस लेने के लिए दिए जाते हैं। इस्तीफों की उलटबांसी जटिल प्रतीकों से ही समझी जा सकती है।

इस्तीफा एक सुरक्षित मार्ग है दायित्वों से बचने का। वह पलायन भी है, चाल भी। वह छद्म भी है, दांव भी। वह अश्वगंधा भी है तो पुनर्नवा भी। वह कभी-कभी रिचार्ज भी करता है तो कभी पार्टी पर बोझ बने लोगों को डिस्चार्ज भी। इस्तीफा एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। हर हार एक संदेश लाती है, हारित और विजित दोनों के लिए। ये राजनीति का एक फेज मात्र है, जो प्रयासों, कर्मों और करतूतों से बदलता रहता है।

इसलिए हे पार्थ, निराश न हो! गांडीव उठा और युद्ध में प्रविष्ट हो जा। वरना हस्तिनापुर अभिलाषी सेंध लगाने की प्रतीक्षा में हैं।

ट्वीट-ट्वीट

मायावती ने अखिलेश यादव से गठबंधन कर अपनी जीरो से दस सीटें करवा लीं। अखिलेश पांच के पांच रह गए। उल्टे अब मायावती अखिलेश को सुना रही हैं कि उनसे गठबंधन के कारण नुकसान हो गया।
नरेंद्र नाथ मिश्रा@iamnarendranath

अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के खाते से महिलाओं के लिए मेट्रो का किराया खत्म कर रहे हैं। मनोज तिवारी को केंद्र सरकार के खाते से बाकी लोगों के लिए किराया कम करवाना चाहिए। आपस में क्यों लड़ना, जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के लिए मुकाबला करिए।
सर्वप्रिया सांगवान@DrSarvapriya

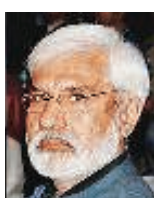

लीजिए, केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के लिए अपनी ही बनाई समिति के प्रारूप पर इतना भी आत्मविश्वास नहीं दिखाया कि दक्षिण भारत के अतार्किक, राजनीतिक विरोध के दबाव पर उनसे संवाद-बहस तक कर सके। नीति के प्रारूप को बदल दिया गया है।
राहुल देव@rahuldev2

कुशल कोठियाल
राज्य संपादक, उत्तराखंड

उत्तराखंड डायरी

शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी की उम्मीद

इस बार के आम चुनाव में राज्य की पांचों लोकसभा सीटों पर भाजपा ने बाजी मारी है। प्रदेश में कांग्रेस की दशा और दिशा को देखते हुए ये परिणाम राज्यवासियों के लिए बिल्कुल प्रत्याशित ही रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कभी इस राज्य को महज पांच सीटों वाले राज्य के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसके धार्मिक और सामरिक महत्व को समझते हुए वह इसे समुचित महत्व देते रहे हैं। उधर चुनाव के नतीजों के बाद से ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उत्तराखंड के प्रतिनिधित्व को लेकर तमाम आशंकाएं तैर रही थीं, लेकिन इसे दूर करते हुए प्रधानमंत्री ने हरिद्वार से चुने गए सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को अपने कैबिनेट में लेकर मानव संसाधन जैसा भारी-भरकम महकमा सौंपा। उनके इस चयन से राज्य में सकारात्मक चर्चा भी चल पड़ी है। हालांकि निवर्तमान सरकार में भी अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा को राज्य मंत्री के रूप में दायित्व दिया गया था, लेकिन इस प्रतिनिधित्व को औपचारिक ही समझा गया। इस बार सीधे कैबिनेट बर्थ देकर बड़ा दायित्व भी दिया गया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने राजनीतिक तजुर्बे एवं सक्रिय राजनीतिक व्यवहार वाले निशंक पर भरोसा किया है। अब रमेश पोखरियाल निशंक को केंद्रीय टीम में जगह मिलने के बाद से राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी की उम्मीदें जोर मार रही हैं। वर्तमान में राज्य में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन राज्यवासियों की आशानुरूप नहीं है। सरकारी क्षेत्र में तो स्थिति दयनीय है। अब शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ही लोग दिन बहुरने की उम्मीद जता रहे हैं। निशंक पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी सक्रियता पूरे प्रदेश में रही है। ऐसे में हर कोने से निशंक से राज्य के हित में कुछ करने की अपेक्षा जताई जा रही है।

ये आग कैसे बुझेगी

प्रदेश के जंगल हर बार की तरह इस बार भी आग की चपेट में हैं, लेकिन इस बार चिंता कुछ ज्यादा है। मई के पहले पखवाड़े तक पहाड़ों में बारिश एवं बर्फबारी होती रही। सर्दियों में जमकर बर्फबारी हुई। वन विभाग भी पिछले दो-तीन महीनों से आग पर काबू पाने के लिए पूरी तैयारी के बड़े दावे कर रहा था। इन स्थितियों में समझा जा रहा था कि जंगलों की आग बेकाबू नहीं हो पाएगी। स्थिति ठीक इसके उलट है।

उत्तराखंड के जंगलों में अब तक आग की 1819 घटनाएं हो चुकी हैं और 2521 हेक्टेयर वन क्षेत्र में आग लग चुकी है। वनाग्नि से अल्मोड़ा जिला सर्वाधिक प्रभावित रहा। अभी तक दस लोग आग बुझाते समय घायल हो चुके हैं और एक श्रमिक की मृत्यु हो चुकी है। अब विभाग कृत्रिम बारिश कराने के उपायों पर सोच रहा है। यह आगामी साल में संभव हो पाएगा।

उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा परिणाम

उत्तराखंड शिक्षा परिषद का परीक्षा परिणाम 30 मई को घोषित हो गया। चर्चा इस बार परिणाम से ज्यादा बोर्ड की लेटलतीफी की रही। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बोर्ड के परिणाम काफी पहले निकल गए थे, लेकिन राज्य के बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारी लोकसभा चुनाव और आचार संहिता जैसे बहानों के बूते अपनी कछुआ चाल को तर्कसंगत बनाने की कोशिशों में लगे रहे।

देश के अन्य विद्यालयी शिक्षा परिषदों की तुलना में उत्तराखंड का प्रशासनिक दृष्टि से पिछड़ना व्यवस्था पर कई सवालिया निशान लगाता है। वेतनमान और अन्य दूसरी सुविधाओं की दृष्टि से ठीक-ठाक शिक्षा विभाग परिणामोन्मुखी क्यों नहीं बन पा रहा, यह सवाल छात्रों का भी है और जागरूक अभिभावकों का भी? हाईस्कूल का 76 एवं इंटरमीडिएट का परिणाम 80 प्रतिशत रहा। इस परिणाम में भी निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी निर्णायक है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षक वेतन और भत्तों के अनुरूप परिणाम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इस सवाल पर हर सत्र के प्रारंभ में विमर्श होता है, इस बार भी हो रहा है।

जागरण जनमत कल का परिणाम

अमेरिका द्वारा कारोबारी वरीयता का दर्जा वापस लेने से भारत की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ेंगी?

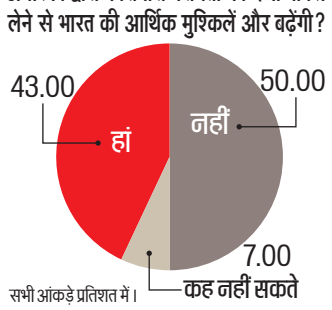

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या सरकार ने नई शिक्षा नीति के मसौदे से हिंदी की अनिवार्यता को खत्म कर सही किया है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

जाता तर जिस नाम के सुमिरन से इंसान,
उसी नाम पर उठ रहा नफरत का तूफान।
नफरत का तूफान रसातल में ले जाए,
खिसकी जाय जमीन अक्ल फिर भी ना आए।
सुनकर जय श्रीराम क्रोध उनको है आता,
पारा सौ के पार ममता का चढ़ जाता।
- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

प्रभु पिंगली
निदेशक, टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रीशन

कुपोषण दूर करने के उपाय

वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने पर केंद्र सरकार का बल कुपोषण और भूख से मुकाबले की दिशा में बहुत अहम है

आजादी के बाद से खाद्यान्न उत्पादन में पांच गुनी वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत ने खाद्य सहायता पर निर्भरता को पीछे छोड़ दिया है और अब एक खाद्य निर्यातक देश बन चुका है। बावजूद इसके भूख की समस्या के कुल वैश्विक बोझ का करीब एक चौथाई भारत में मौजूद है। भारत वर्ष 2011 तक के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के अंतर्गत गरीबी कम करने के ध्येय तक पहुंचने में समर्थ तो हो गया, लेकिन भूख की समस्या में कमी करने के ध्येय की पूर्ति में बहुत पीछे रह गया। हालांकि देश में अल्पपोषण (जरूरत से कम भोजन मिलना) के प्रचलन में कमी आई है, लेकिन अब भी यह 15 प्रतिशत के आसपास बना हुआ है, जो विश्व में सर्वाधिक ऊंची दरों में एक है। वर्ष 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के ध्येय-2, जो कुपोषण के मुकाबले के अपने उद्देश्य को लेकर तो स्पष्ट है ही, साथ ही पर्यावरणीय मुद्दों एवं आनुवांशिक विविधता पर केंद्रित सतत खाद्य प्रणाली पर भी पूरा जोर देता है, की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत को भूखे लोगों की तादाद में कम-से-कम 20 करोड़ की कमी लानी होगी। यह भारत के नीति निर्माताओं के लिए सर्वाधिक कड़ी चुनौतियों में एक होने जा रहा है, जिसके लिए नीतिगत स्तर पर गैर-परंपरागत हस्तक्षेप की आवश्यकता तो है ही, सरकारी मंचों से परे भी विभिन्न एजेंसियों/संगठनों का सहयोग लेना होगा।

पर्याप्त खाद्य तक पहुंच से आगे, एसडीजी-2.1 पोषक खाद्य तक लोगों की पहुंच की मांग भी खास तौर से करता है। कैलोरी-सघन मुख्य आहार की तुलना में पोषक खाद्य (प्रोटीन एवं सूक्ष्म-पोषकता से भरे खाद्य) तक पहुंच में कमी रही है। हालांकि आहार विविधता की दिशा में रुझान निश्चित रूप से बढ़ा है, फिर भी गैर-मुख्य आहार की तुलनात्मक रूप से अधिक कीमतें पोषक आहार तक खासकर गरीबों की पहुंच सीमित कर देती हैं। पिछले 50 वर्षों के दौरान हमने मुख्य आहार के अनाजों की वास्तविक कीमतों में गिरावट या स्थिरता, जबकि फलों, सब्जियों, दालों, घरेलू पशु के उत्पादों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी तथा अधिक उतार-चढ़ाव देखे हैं। गैर-मुख्य आहार की तुलनात्मक कीमतें बढ़ते जाने और इस वजह से अधिक पोषक खाद्य हासिल करने में असमर्थता के कारण गरीबों के आहार में सूक्ष्म-पोषक पदार्थों की कमी बढ़ी है। इसे ही 'छिपी भूख' (हिडन हंगर) की संज्ञा दी गई है, जिसका नतीजा पोषण परिणामों में कमी के रूप में सामने आता है। जैसे-बच्चों की वृद्धि का रुकना तथा उनकी कमजोरी के अलावा महिलाओं में रक्ताल्पता (एनीमिया) के ऊंचे प्रचलन आदि।

पोषण के परिणामों में कमी के चलते वैसे वयस्क व्यक्तियों में संज्ञानात्मक कौशलों, शैक्षिक परिणामों, उत्पादकता तथा उनकी दिहाड़ी में भी कमी आ जाती है, जो अपने बचपन में कुपोषित थे। बच्चों में मृत्यु की ज्यादा जोखिमों के अतिरिक्त, अध्ययनों से यह भी पता चला है कि बचपन में अल्प-पोषकता से पीड़ित रहे वयस्क व्यक्तियों में गैर-संचारी (नॉन-कम्युनिकेबल) रोगों का प्रचलन वैसे लोगों की अपेक्षा अधिक होता है, जिन्हें बचपन से ही उचित रूप में खानपान मिलता है। खाद्य विविधता तक परिवारों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दो स्तरों पर हस्तक्षेप की जरूरत है। पहला तो यह कि स्थानीय प्रणाली के अंतर्गत खाद्य विविधता की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित हो। हस्तक्षेपों के दूसरे समूहों द्वारा इन आहारों की वहनीयता बढ़ाए जाने की जरूरत होगी।

इस तरह एक प्रभावी खाद्य नीति वह है, जो पोषकता के प्रति संवेदी नई खाद्य प्रणाली विकसित करे और खाद्य उपलब्धता को अधिक स्वस्थ आहार में परिवर्तित कराए। भारत में खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित नीतिगत बहसें अक्सर मुख्य आहार संबंधी अन्नों के उत्पादन पर लगातार जोर द्वारा कैलोरियों तक पर्याप्त पहुंच सुनिश्चित करने पर ही बल देती रही हैं। फिर भी आहार तथा पोषण परिवर्तन से संबद्ध रुझान मौजूदा प्रतिमानों पर सवाल उठाने एवं एक अच्छी गुणवत्तासंपन्न तथा संतुलित आहार तक पहुंच पर संवाद शुरू करने के लिए बाध्यकारी साक्ष्य प्रदान करते हैं। मुख्य आहार पर जोर ने गैर-मुख्य आहार के लिए बाजारों के विकास के लिए प्रोत्साहनों को प्रभावित किया है, उनकी आपूर्ति पर असर डाला है और उनकी कीमतों में अनिश्चितता भी बढ़ा दी है। अतः नीति निर्माताओं को चाहिए कि वे उपभोक्ताओं की परिवर्तित होती मांग पूरी करने के लिए खाद्य प्रणाली विविधीकरण के लिए नए अवसरों के सृजन पर गौर करें।

वहीं वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर सरकार का बल कुपोषण और भूख से मुकाबले की दिशा में बहुत अहम है। छोटे किसानों द्वारा कृषि उत्पादन पोषण एवं खाद्य सुरक्षा से तीन तरह से घनिष्ठ रूप में संबद्ध है। यह परिवार के अपने ही उत्पादन से उसकी खाद्य सुरक्षा उन्नत करता है। यह खाद्य की वास्तविक कीमत कम करके उसकी आपूर्ति बढ़ाते हुए उसे अधिक वहनीय बना देता है। यह किसान परिवार की आय बढ़ा कर उन्हें पोषक खाद्य हासिल करने में समर्थ बनाता है।

एसडीजी-2 के मुद्दे पर प्रगति के लिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम उस दिशा में सार्वजनिक, निजी और सामाजिक संगठनों के संसाधन तथा उनकी विशेषज्ञता का भी उपयोग करें। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि कृषि, खाद्य, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता तथा ग्रामीण विकास जैसे विभिन्न मंत्रालयों को लेकर बहु-क्षेत्रीय समन्वय स्थापित किया जाए।

पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भौगोलिक विस्तार हासिल करने के लिए केंद्र से लेकर राज्यों तथा स्थानीय पंचायतों तक सभी स्तरों पर एसडीजी के लिए प्रतिबद्धता पैदा करनी होगी। भारत के पिछड़े क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने की संभावनाएं तब अधिक उज्ज्वल होंगी, जब वहां चावल एवं गेहूं के दो मुख्य अनाजों के बजाय मोटे अनाजों तथा दालों को बढ़ावा दिया जाएगा। अंत में उन राजनीतिक-आर्थिक कारकों की पहचान कर उन्हें भी सही करना होगा, जिन्होंने भूख तथा कुपोषण मिटाने की दिशा में प्रगति बाधित कर रखी है।

राष्ट्रीय संस्करण
मंगलवार 4 जून 2019
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

डब्ल्यूएचओ ने कैग को एक्सटर्नल ऑडिटर चुना

नई दिल्ली : भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) राजीव महर्षि को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है। वह 2020 से 2023 तक संगठन के एक्सटर्नल ऑडिटर की भूमिका में रहेंगे। महर्षि को जेनेवा में हुई 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में बहुमत से इस पद के लिए चुना गया। भारत के अलावा कांगो, फ्रांस, घाना, ट्यूनीशिया और ब्रिटेन के ऑडिटर जनरल भी इस पद की दौड़ में थे। (जागरण ब्यूरो)

पिछले दो वर्षों के दौरान छोटी बचत की योजनाओं ने सरकार को राजस्व घाटा काबू में रखने में बड़ी मदद की है।
— उदय कोटक, बैंकर

सेंसेक्स	40,267.62 ▲ 553.42	निफ्टी	12,088.55 ▲ 165.75	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 33,195 ▲ ₹75	चांदी प्रति किलोग्राम	₹37,500 ▼ ₹80	$ डॉलर	₹69.26 ▼ ₹0.44	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$62.00

तैयारी ▶ गांवों को डिजिटल बनाने के लिए स्थापित होंगे पांच लाख वाई-फाई हॉट स्पॉट

सौ दिनों में शुरू हो जाएगा 5जी का ट्रायल

साल के अंत तक होगी स्पेक्ट्रम की नीलामी, भारत का भी होगा ब्राडबैंड इंडेक्स

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार 100 दिनों के भीतर 5जी सेवाओं का परीक्षण शुरू करेगी। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा कि स्पेक्ट्रम की नीलामी भी इस साल के अंत तक हो जाएगी। उन्होंने एक लाख गांवों को डिजिटल बनाने व टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के अलावा बीएसएनएल व एमटीएनएल के पुनरुद्धार के प्रयास करने का भी एलान किया।

प्रसाद ने संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने तीन वर्षों तक मंत्रालय को सफलतापूर्वक संभालने के लिए मनोज सिन्हा का भी अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया और समावेशी भारत के स्वप्न को पूरी तरह साकार करने के लिए वे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच समन्वय सुनिश्चित करेंगे ताकि आम जनता तक सेवाओं की आसान व पारदर्शी डिलीवरी हो। प्रसाद ने बाद में इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला। उन्होंने कहा कि डिजिटल विलेज की अवधारणा के तहत एक लाख गांवों को डिजिटल बनाने के लिए पांच लाख वाई-फाई स्पॉट स्थापित किये जाएंगे। इससे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), ई-हास्पिटल, ई-स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रसाद ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड सुविधाओं के विस्तार वाली भारतनेट प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने को भी अपनी प्राथमिकताओं में गिनाया। उन्होंने राष्ट्रीय ब्राडबैंड मिशन के साथ नेशनल ब्रॉडबैंड अथॉरिटी के गठन के साथ ही भारत का ब्रॉडबैंड इंडेक्स लांच करने का एलान भी किया।

5जी परीक्षण पर बोलते हुए प्रसाद ने कहा कि इसके मुताबिक स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन 5जी में उतरने वाली कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका फायदा समाज के वंचित वर्ग को भी मिले ताकि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में सुधार लाया जा सके। 5जी ट्रायल में भाग लेने वाली कंपनियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का सरकार पूरा ध्यान रखेगी। उन्होंने स्टार्ट-अप की चिंता करने के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) का पुनरुद्धार करने की प्रतिबद्धता भी जताई। उनका कहना था कि संचार क्षेत्र में पीएसयू का होना जरूरी है क्योंकि सुदूर क्षेत्रों तथा भूकंप, बाढ़, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के वक्त इनका नेटवर्क और सेवाएं बेहतर ढंग से काम करती हैं।

डिजिटल पेमेंट में घरेलू तकनीक को बढ़ावा

इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कामकाज संभालने के बाद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि देश में बढ़ रहे डिजिटल पेमेंट की अवधारणा को रफ्तार देने के लिए सरकार घरेलू प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करेगी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में देश में मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग पर जोर दिया गया। इस बार सरकार का जोर मेडिकल उपकरणों की मैन्यूफैक्चरिंग पर रहेगा। इस क्षेत्र में निवेश लाने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रसाद ने कहा कि सरकार जल्दी ही 10 शहरों में आधार सेवा केंद्र स्थापित करेगी।

रविशंकर प्रसाद। फाइल फोटो

ब्याज घटने की उम्मीद में सेंसेक्स हुआ चालीस हजारी, निफ्टी 12 हजार के पार

मुंबई, प्रेट्र : देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुए। इंट्राडे ट्रेड में सेंसेक्स ने 40,308.90 का और निफ्टी ने 12,103.05 का रिकॉर्ड ऊपरी स्तर भी छुआ। जीडीपी के कमजोर आंकड़े को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की मुख्य नीतिगत ब्याज दर में कटौती होने की उम्मीद में निवेशकों ने बाजार में चौतरफा खरीदारी की।

बीएसई का सेंसेक्स 553.42 अंकों की तेजी के साथ 40,267.62 के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 165.75 अंकों की तेजी के साथ रिकॉर्ड 12,088.55 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पहली बार 40,000 के ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स में हीरो मोटोकॉर्प में सर्वाधिक 6.01 फीसद तेजी रही। कंपनी ने रविवार को कहा था कि पिछले महीने उसके वाहनों की बिक्री अप्रैल के मुकाबले 13.5 फीसद बढ़कर 6.5 लाख यूनिट से ऊपर पहुंच गई। बीएसई के मुख्य सूचकांक में आइसीआइसीआइ बैंक में सर्वाधिक 0.13 फीसद गिरावट रही। बीएसई पर स्पाइसजेट 4.18 फीसद उछला। कंपनी ने रविवार को कहा था कि वह जेट एयरवेज के 900 और कर्मचारियों को नौकरी देगी। कंपनी के सीएमडी अजय सिंह ने चालू वित्त वर्ष में अच्छा खासा शुद्ध लाभ होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने साथ ही कहा कि कंपनी पर अधिक कर्ज नहीं है।

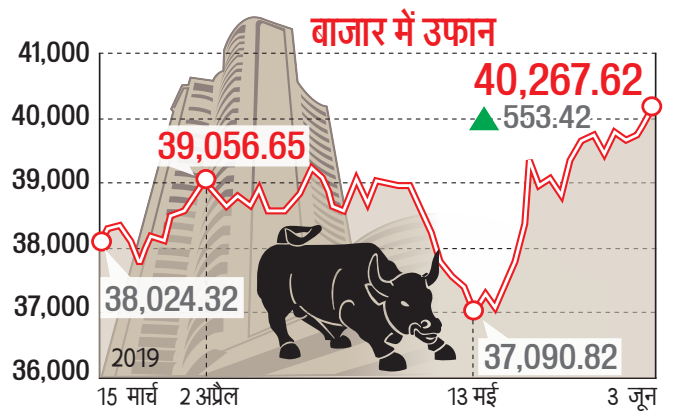

निवेशकों की संपत्ति 1.76 लाख करोड़ रुपये बढ़ी

नई दिल्ली : शेयरों में चौतरफा तेजी के कारण बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण (एमकैप) 1,76,402.37 करोड़ रुपये बढ़ गया। इसके साथ ही बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल एमकैप 1,56,14,416.92 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

स्टील सेक्टर की दिक्कतों को जल्द दूर करेगी सरकार

नई दिल्ली : इस्पात और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्पात मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर सेक्टर का जायजा लिया। जागरण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक में की स्टील उद्योग की समीक्षा
- सेक्टर को आयातित स्टील से मिल रही बड़ी चुनौती

सरकार घरेलू स्टील सेक्टर की दिक्कतों को दूर करने के लिए जल्द ही रोडमैप तैयार करेगी। सरकार का मानना है कि स्टील सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम भागीदार रहा है। सरकार का फोकस देश में स्टील के उत्पादन में वृद्धि और इससे जुड़े कच्चे माल की सुगम सप्लाई पर रहेगा।

इस्पात और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्पात मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर सेक्टर का जायजा लिया। प्रधान ने पिछले शुक्रवार को मंत्रालय का कामकाज संभाला था। सूत्रों ने बताया कि प्रधान ने बैठक में स्पष्ट कर दिया कि उनका पूरा जोर घरेलू स्टील उद्योग को मजबूत बनाने पर है।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में स्टील उद्योग के समक्ष वर्तमान में आ रही परेशानियों और दिक्कतों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने पूरे सेक्टर को लेकर प्रजेंटेशन दिए। बैठक में इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और विभाग के सचिव बिनय कुमार प्रधान भी मौजूद रहे।

स्टील उद्योग का कहना है कि उसे आयातित स्टील और खासतौर पर ईरान से आयातित स्टील से बड़ा खतरा दिख रहा है। इंडियन स्टील एसोसिएशन (आइएसए) ने कहा है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वार से भारत में स्टील का आयात लगातार बढ़ रहा है।

संगठन ने बिनय कुमार को लिखे पत्र में कहा कि बहुत सस्ते दाम पर हो रहे इन निर्यातों पर संगठन बेहद चिंतित है। यह चौंकाने वाली बात है कि जो संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्टील का आयातक रहा था, पिछले वित्त वर्ष में उसके निर्यात में एकाएक 2016-17 के मुकाबले 390 फीसद का उछाल दर्ज किया गया है।

गौरतलब है इस वर्ष से स्टील उद्योग के प्रदर्शन में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हुआ है। तीन साल लगातार घाटा उठाने के बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2018-19 में 2,179 करोड़ रुपये का मुनाफा अर्जित किया है। कंपनी विस्तार योजना पर भी काम कर रही है और साल 2030-31 अपनी क्षमता को पांच करोड़ टन तक लाना चाहती है। विस्तार योजना को दो चरणों में पूरा किया जाएगा।

पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंकों में हुआ 71,500 करोड़ रुपये का घोटाला

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में बैंकों से जुड़ी धोखाधड़ी के कुल 71,500 करोड़ रुपये से अधिक के 6,800 से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए। इससे पिछले वित्त वर्ष 2017-18 में कुल 41,167.03 करोड़ रुपये के ऐसे 5,916 मामले प्रकाश में आए थे। आरबीआइ ने सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं ने 71,542.93 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 6,801 मामलों की सूचना दी है।

आरबीआइ ने बताया कि धोखाधड़ी वाली राशि में 73 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आरबीआइ के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 11 वित्त वर्षों में कुल 2.05 लाख करोड़ रुपये की भारी धनराशि की बैंकिंग धोखाधड़ी के कुल 53,334 मामले दर्ज किए गए। 2008-09 में 1,860.09 करोड़ रुपये के 4,372 मामले सामने आए। इसके बाद 2009-10 में 1,998.94 करोड़ रुपये के 4,669 मामले दर्ज किए गए। 2015-16 में कुल 18,698.82 करोड़ रुपये के 4,693 मामले और 2016-17 में कुल 23,933.85 करोड़ रुपये मूल्य के 5,076 मामले सामने आए।

- आरबीआइ के मुताबिक घोटाले के 6,800 मामले आए सामने
- सिर्फ एक साल में 73 फीसद बढ़ गई घोटाले की राशि

शिकायत करना जरूरी : भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसे धोखाधड़ी के बारे में दी गई जानकारी को लेकर बैंकों द्वारा कानून लागू करने वाली एजेंसियों के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज कराना आवश्यक होता है। धोखाधड़ी मामलों में क्या कार्रवाई हो रही है और क्या-क्या कार्रवाई की जा चुकी है, इस बारे में किसी तरह की सूचना फिलहाल नहीं मिल सकी। गौरतलब है कि देश के बैंक धोखाधड़ी के कई बड़े मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें भगोड़े आभूषण कारोबारी नीरव मोदी और शराब कारोबारी विजय माल्या से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

साल-दर-साल बढ़ता गया घोटाले का आकार

वित्त वर्ष	मामले	राशि
2008-09	4,372	1,860.09
2009-10	4,669	1,998.94
2010-11	4,534	3,815.76
2011-12	4,093	4,501.15
2012-13	4,235	8,590.86
2013-14	4,306	10,170.81
2014-15	4,639	19,455.07
2015-16	4,693	18,698.82
2016-17	5,076	23,933.85
2017-18	5,916	41,167.03
2018-19	6,801	71,542.93

(नोट : राशि करोड़ रुपये में)

मैन्यूफैक्चरिंग में लगातार तीसरे महीने बनी रही रफ्तार

नई दिल्ली, प्रेट्र : मांग में बढ़ोतरी के साथ कंपनियों का उत्पादन बढ़ने से पिछले महीने देश में मैन्यूफैक्चरिंग गतिविधियों की रफ्तार में वृद्धि दर्ज की गई। इसके कारण इस क्षेत्र में रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई। सोमवार को जारी निक्केई इंडिया मैन्यूफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआइ) की रीडिंग मई में उछलकर 52.7 पर पहुंच गई, जो अप्रैल में 51.8 पर थी। यह पिछले तीन महीने में इस क्षेत्र में सबसे तेज विकास को दर्शाता है।

यह लगातार 22वां महीना है, जब मैन्यूफैक्चरिंग पीएमआइ 50 अंक से ऊपर रहा है। पीएमआई की शब्दावली में इंडेक्स के 50 से ऊपर रहने से यह पता चलता है कि संबंधित क्षेत्र में विस्तार हुआ है। 50 से नीचे की रीडिंग यह बताती है कि संबंधित क्षेत्र में संकुचन हुआ है। आइएचएस मार्किट की प्रधान अर्थशास्त्री और इस सर्वेक्षण रिपोर्ट की लेखिका पॉलियाना डि लीमा ने कहा कि नए ठेके में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादन को तेज करना पड़ा। मई में खाली हुई इन्वेंट्री को फिर से भरने के लिए कंपनियों ने उत्पादन में बढ़ोतरी की, ताकि बढ़ी हुई मांग की पूर्ति की जा सके।

- मैन्यूफैक्चरिंग पीएमआइ 51.8 से उछलकर मई में 52.7 पर पहुंचा
- पिछले तीन माह में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में हुआ है सबसे तेज विकास

सर्वेक्षण के मुताबिक मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों में उत्साह का संचार होने और नए ऑर्डर में बढ़ोतरी होने से इस क्षेत्र में रोजगार बढ़े हैं। अप्रैल, 2018 के बाद से नौकरियों में लगातार इजाफा दर्ज किया गया है। मई में फरवरी के बाद रोजगार में सबसे तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई।

अप्रैल के बाद से इस उद्योग की स्थिति सुधरी है और मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों को विश्वास है कि अगले एक साल में उत्पादन में बढ़ोतरी जारी रहेगी। महंगाई को लेकर सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि कीमत का दबाव आलोच्य अवधि में कम रहा। लागत में मामूली बढ़ोतरी के कारण मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों ने अपने उत्पादों के बिक्री मूल्य को पहले के स्तर पर बनाए रखा। लीमा ने कहा कि सर्वेक्षण के 14 साल से अधिक के आंकड़ों के आधार पर देखा जाए, तो मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर औसत से कम चल रही है।

छोटे किसानों की प्राथमिकता पर अनुसंधान की जरूरत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रतीकात्मक

कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में छोटे व मझोले किसानों की प्राथमिकताओं के हिसाब से शोध व अनुसंधान की वकालत की है। उन्होंने कहा कि सुदूर ग्रामीण किसानों की जरूरतें उनके आसपास ही पूरी होनी चाहिए, ताकि शहरों पर उनकी निर्भरता खत्म हो। तोमर सोमवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के बारे में जानकारी ले रहे थे। इस दौरान आइसीएआर के महानिदेशक त्रिलोचन महापात्र ने परिषद के कामकाज व दायरे का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। तोमर ने कहा कि खेती जैसे उद्यम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आधुनिक अनुसंधान पर जोर देना होगा। छोटे किसानों की जरूरतों के हिसाब से अनुसंधान होने चाहिए।

कृषि मंत्री ने पहले दिन ही कृषि वैज्ञानिकों से अपने कामकाज की हर दूसरे महीने समीक्षा करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि खेती की जरूरतों के हिसाब से वैज्ञानिक अनुसंधान करें, तभी फायदेमंद होगा। क्षेत्रीय जरूरतों का पूरा ध्यान रखकर ही शोध करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि शहरों के आसपास जमीन बहुत महंगी होने से खेती के बदले उनका उपयोग व्यावसायिक होने लगा है। इससे वहां के किसानों की आमदनी भले ही बढ़ गई हो, लेकिन शहरी आबादी को ताजा कृषि उत्पाद मुश्किल से मिल पाता है।

छोटे किसानों की चिंता करते हुए तोमर ने कहा कि वैज्ञानिकों को उनके लिए तकनीक बनाने का सुझाव दिया। उनका कहना था कि छोटे किसान अब तक नजरअंदाज होते रहे हैं। घटते जल संसाधन के प्रभावशाली संरक्षण और प्रबंधन तथा इसे सर्वसुलभ बनाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी की जरूरत है।

महापात्र ने देश में खाद्यान्न, बागवानी, पशुधन, डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री व मत्स्य की मांग व आपूर्ति का ब्योरा पेश किया। उन्होंने कहा कि उत्पादकता के साथ जैव व खाद्य गुणवत्ता विशेष पर जोर दिया गया है। खेती में गन्ना की सीओ-238 प्रजाति, पूसा बासमती 1121 किस्म और अनार की भगवा किस्म का उल्लेख करते हुए बताया कि इन प्रजातियों ने किसानों की आमदनी में कई गुना की वृद्धि कर दी है।

ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- अर्थव्यवस्था की सुस्ती, क्रूड की कीमतों में नरमी ने बनाया माहौल
- इससे पहले दो बैठकों में बैंक कर चुका है कुल 50 आधार अंकों की कटौती

देश में मौद्रिक नीति तय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की समिति की सोमवार को मुंबई में बैठक शुरू हो गई। जनवरी-मार्च, 2019 तिमाही के आर्थिक विकास दर आंकड़े आने के बाद इस पहली मौद्रिक नीति से उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए कुछ उपायों का एलान होगा। देश की आर्थिक विकास दर पिछली पांच तिमाहियों से लगातार गिर रही है। ऐसे में उद्योग जगत और सरकार को उम्मीद है कि गुरुवार को आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ब्याज दरों में 50 आधार अंकों तक की कटौती करेंगे। इसके साथ ही मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) आरबीआइ की तरफ से फंसे कर्जे (एनपीए) के नए नियमों पर रोक लगाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में भी कुछ एलान करने की तैयारी में है। छोटे व मझोले उद्योगों की फंड की समस्या को दूर करने के लिए भी आरबीआइ कई उपायों पर विचार कर रहा है।

पिछले हफ्ते सरकार आए कुछ सरकारी आंकड़ों के बाद रेपो रेट में कटौती की उम्मीद बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी-मार्च, 2019 के दौरान देश की आर्थिक विकास दर 5.8 फीसद रही थी। उद्योग संगठन फिक्की और सीआइआइ ने अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को बेहद गंभीर बताया है और इसमें तेजी लाने के लिए सस्ते और पर्याप्त कर्ज को सबसे बड़ी जरूरत बताई है। उधर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में नरमी की वजह से भी रेपो रेट की उम्मीद की जा रही है। इस वर्ष अप्रैल में केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में महंगाई की औसत दर के तीन फीसद से नीचे रहने की उम्मीद लगाई थी। उसके बाद से क्रूड की कीमतों और कम हुई हैं। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत भी स्थिर बनी हुई है। महंगाई की दर के नीचे रहने की स्थिति में आरबीआइ के लिए ब्याज दरों को घटाना आसान रहता है।

फाइल फोटो

आरबीआइ ने अप्रैल के पहले सप्ताह में मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की थी। उसके पहले की समीक्षा (फरवरी, 2019) में भी आरबीआइ रेपो रेट में इतनी ही कटौती कर चुका था। इस तरह से पिछले चार महीनों में रेपो रेट में 50 आधार अंकों (0.50 फीसद) की कमी हो चुकी है। हालांकि इसका असर बैंकों की कर्ज की दरों पर बहुत नहीं पड़ा है। कई बैंकों ने होम लोन और ऑटो लोन की दरों में कमी भी नहीं की है। कुछ बैंकों ने बमुश्किल 0.20-0.25 फीसद की कटौती की है। माना जा रहा है कि आरबीआइ अब रेपो रेट में जो कमी करेगी उसका सीधा असर ब्याज दरों पर दिखाई दे सकता है।

क्या है रेपो रेट : देश के बैंक आरबीआइ से जिस दर पर अल्पकालिक कर्ज लेते हैं, उसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट घटने का मतलब यह है कि बैंक कर्ज के रूप में आरबीआइ से ज्यादा रकम की मांग करने में सक्षम हो जाते हैं। इससे बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ता है और उद्योग-धंधों को सस्ती दरों पर कर्ज मिलने की राह आसान होती है। रेपो रेट घटने से बैंकों के पास कर्ज बांटने के लिए पूंजी बढ़ जाती है तो वे ब्याज दरों में भी कटौती के बारे में सोचते हैं।

आकलन

उद्योग संगठन सीआइआइ ने की भूमि व श्रम सुधारों की वकालत, कहा भूमि और श्रम सुधार सबसे ज्यादा जरूरी

दस फीसद विकास दर के लिए लाखों करोड़ डॉलर निवेश चाहिए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत की विकास दर को अगले पांच साल में दस फीसदी के स्तर पर ले जाने के लिए भारी भरकम 5.74 लाख करोड़ डॉलर (करीब 397 लाख करोड़ रुपये) की दरकार होगी। सरकार को यह लक्ष्य हासिल करने के लिये भूमि और श्रम सुधार भी करने होंगे। विकास दर को गति देने के लिए यह सुझाव उद्योग संगठन सीआइआइ ने दिया है। उद्योग संगठन का यह सुझाव इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्त वर्ष 2018-19 में विकास दर घटकर 6.8 फीसद रह गई है, जो 2017-18 में यह 7.2 फीसद थी। वित्त वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च) में तो यह घटकर 5.8 फीसद पर आ गई है। सीआइआइ के प्रेसिडेंट विक्रम किर्लोस्कर ने कहा कि वर्ष 2023-24 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर को बढ़ाकर दोहरे अंकों तक ले जाने यानी कम से कम 10 फीसद पर पहुंचाने के लिए लगभग 5.74 लाख करोड़ डॉलर के निवेश की दरकार होगी। इसमें से 1.18 लाख करोड़ डॉलर (81.71 लाख करोड़ रुपये) निवेश की जरूरत अकेले ढांचागत क्षेत्र के लिए ही होगी, जबकि कृषि और उद्योग सहित गैर-ढांचागत क्षेत्र के लिए लगभग 4.56 लाख करोड़ डॉलर (315 लाख करोड़ रुपये) निवेश की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि सुधारों की रफ्तार को बनाए रखना जरूरी है। सरकार को जिस प्रकार का जनादेश मिला है, हमें उम्मीद है कि वह भूमि, श्रम और पूंजी के क्षेत्र में सुधार करेगी।

प्रतीकात्मक

सीआइआइ के मुताबिक निजी क्षेत्र को मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों की स्थापना के लिए जमीन मिलने करने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में लैंड बैंक बनाने की जरूरत है, जिसमें राज्यों की अहम भूमिका होगी। श्रम सुधारों के मुद्दे पर किर्लोस्कर ने राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की भूमिका पर जोर दिया। उनका कहना था कि कंपनियों को रोजगार सृजित करने के लिये प्रोत्साहन देने की भी जरूरत है।

सीआइआइ का मानना है कि विकास दर को बढ़ावा देने के लिए उपभोग, निवेश, सामाजिक व ढांचागत सुविधाओं पर सार्वजनिक व्यय और निर्यात में वृद्धि पर जोर देना चाहिए। सरकार को डायरेक्ट टैक्स कोड लाने और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधार की दिशा में कदम उठाने चाहिए। इक्विटी पर टैक्स तर्कसंगत बनाने की वकालत करते हुए सीआइआइ के अगले सत्र के लिए निर्वाचित अध्यक्ष उदय कोटक ने कहा कि विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए जाने के कारण कर्ज की तुलना में इक्विटी महंगी पड़ती है। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए।

जीएसपी की सुविधा खत्म होने से पड़ेगा निर्यात पर असर

नई दिल्ली : अमेरिका ने भारत से होने वाले निर्यात पर जीएसपी के तहत मिल रहे प्रोत्साहनों को खत्म करने का निर्णय जल्दबाजी में उठाया है। इससे घरेलू निर्यातकों को नुकसान होगा। उद्योग संगठन सीआआइ के प्रेसिडेंट विक्रम किर्लोस्कर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका और भारत इस मुद्दे पर विचार करेंगे और आपसी सहमति से कोई हल निकाल लेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने यह कदम जल्दबाजी में उठाया है। इससे हमारे निर्यात खासकर छोटी वस्तुओं के निर्यात पर असर पड़ेगा।

गौरतलब है कि अमेरिका ने जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेज के तहत भारतीय निर्यातकों को मिल रहे प्रोत्साहन को पांच जून से समाप्त कर देगा। उन्होंने कहा कि जीएसपी सुविधा को समाप्त करने का भारतीय निर्यातकों के साथ-साथ अमेरिकी कंपनियों पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल अमेरिकी आयातकों को भारत से आयात पर लगभग 73 करोड़ डॉलर की शुल्क लाभ मिलता है। इससे अमेरिकी कंपनियों को कुल मिलाकर करीब 89 करोड़ डॉलर की बचत होती है। ऐसे में जीएसपी खत्म होने पर अमेरिकी कंपनियों पर भी असर पड़ेगा।

स्थानीय खरीदारी बढ़ने से सोना उछला, चांदी फिसली

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश के मजबूत रुझान और स्थानीय ज्वेलरों के बीच मांग बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सोना 75 रुपये मजबूत होकर 33,195 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं द्वारा खरीदारी घटाने से चांदी हालांकि 80 रुपये फिसलकर 37,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।

कारोबारियों ने कहा कि विदेशी बाजारों के मजबूत रुझान के साथ-साथ स्थानीय ज्वेलरों की ओर से खरीदारी बढ़ाए जाने के कारण भी सोने की कीमत बढ़ी है। ट्रेड वार तीखा होने से निवेशकों में सुरक्षित निवेश के रूप में मांग बढ़ने से सिंगापुर और न्यूयॉर्क में सोने की कीमत बढ़ी। न्यूयॉर्क में सोने में 1,314.50 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर और चांदी में 14.73 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार हुआ। अमेरिका द्वारा मेक्सिको के सभी आयातित उत्पादों पर पांच फीसद शुल्क लगाने की घोषणा किए जाने से भी सुरक्षित निवेश के रूप में सोने का आकर्षण बढ़ा है। अमेरिका का यह शुल्क इसी महीने की 10 तारीख से लागू होगा।

- 33,195 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया सोमवार को सोना
- 37,500 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया चांदी का भाव

राष्ट्रीय राजधानी में 99.9 फीसद खरा सोना 75 रुपये मजबूत होकर 33,195 रुपये और 99.5 फीसद खरा सोना भी इतनी ही मजबूती के साथ 33,025 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। आठ ग्राम सोने की गिन्नी हालांकि 26,700 रुपये प्रत्येक के भाव पर कायम रही। शनिवार को सोने का भाव 50 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरा था। चांदी हाजिर 80 रुपये फिसलकर 37,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई, जबकि वीकली डिलीवरी 87 रुपये मजबूत होकर 36,464 रुपये प्रति किलोग्राम की हो गई। चांदी के सिक्कों की कीमत प्रति सैकड़ा 80,000 रुपये खरीद और 81,000 रुपये बिक्री के स्तर पर कायम रही।

19 लोगों की मौत हो गई है विद्रोहियों के कब्जे वाले सीरिया के उत्तर-पश्चिमी शहर अजाज में एक कार बम धमाके में। इसमें करीब दो दर्जन लोग घायल हैं। शहर के एक बाजार में यह विस्फोट उस वक्त हुआ जब वहां ईद की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुटी थी।

लैंगिक असमानता खत्म करने में फिसड्डी साबित हुई दुनिया

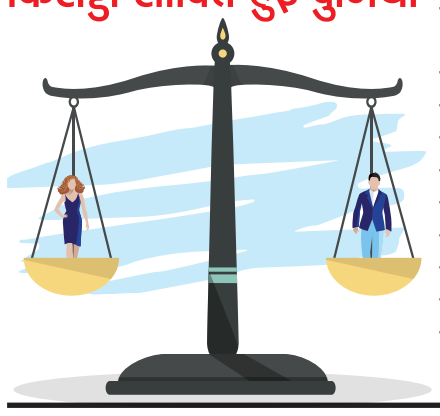

2015 में दुनिया के 193 देशों ने 17 एसडीजी (टिकाऊ विकास लक्ष्य) क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए लक्ष्य रखा था कि 2030 तक इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा देंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दुनिया के देशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के आकलन पर सोमवार को जारी दुनिया का पहला एसडीजी जेंडर इंडेक्स बताता है कि कोई भी देश इस लक्ष्य के आसपास पहुंचता नहीं दिख रहा है। भारत इस सूचकांक में 56.2 अंकों के साथ 95वें पायदान पर है।

अगर कोई भी देश लैंगिक भेदभाव को लेकर तय किए गए लक्ष्यों के करीब पहुंचता नहीं दिख रहा है तो यह बहुत चिंता वाली बात है। दुनिया को अब नींद से जाग जाना चाहिए
मेलिंडा गेट्स, सह-चेयरपर्सन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन

2.8 अरब का अधर में भाग्य

इन 193 देशों में महिलाएं और लड़कियों की संख्या 2.8 अरब है। इक्वल मीजर्स 2030 की भागीदारी से तैयार पहला एसडीजी जेंडर इंडेक्स बताता है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों का भाग्य अधर में लटका है। ये देश इनकी जीवनदशाओं को सुधारने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं।

क्या हैं एसडीजी लक्ष्य

2015 में इन्हें तय किया गया था। इसके तहत लैंगिक असमानता, गरीबी, जलवायु परिवर्तन सहित 17 चीजें शामिल थीं। तय किया गया था कि 2030 यानी 15 साल बाद इन क्षेत्रों के लिए तय किए गए लक्ष्यों को हासिल कर लिया जाएगा।

प्रयासों में कितनी तेजी

129 देशों की लैंगिक असमानता को खत्म करने के प्रयास को शून्य से सौ अंक दिए गए हैं। सूचकांक के अनुसार 90 या इससे ज्यादा अंक वाले देश की अच्छी प्रोग्रेस है जबकि 59 या इससे कम अंक वाले देशों की प्रगति चिंताजनक है।

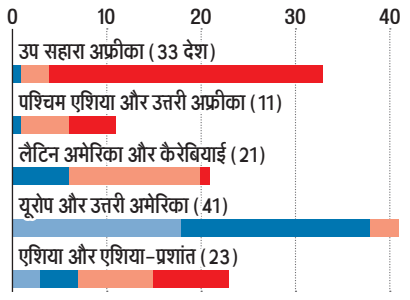

जिनमें सभी देश पिछड़े

संसद में महिलाओं की अल्प भागीदारी, वेतनमान में अंतर और लैंगिक हिंसा के मामलों को दूर करने के लिए सभी देश संघर्ष करते दिख रहे हैं। सिर्फ 21 देशों के 80 या उससे अधिक अंक मिले हैं। 21 देशों को 50 से कम अंक मिले हैं। चाड सबसे निचले पायदान पर है।

क्रम	देश	स्कोर (0 25 50 75 100)
01	डेनमार्क	89.3
10	ऑस्ट्रेलिया	85.2
17	ब्रिटेन	82.2
28	अमेरिका	77.6
74	चीन	64.7
95	भारत	56.2
129	चाड	33.4
	औसत	65.7

न्यूज गैलरी

पाकिस्तान में एसी फेल होने से आठ नवजातों की मौत

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के एक अस्पताल में कथित तौर पर एसी फेल होने से 24 घंटे के भीतर आठ नवजात की मौत हो गई। यह घटना पंजाब प्रांत के साहीवाल शहर के सरकारी अस्पताल की है। पंजाब के उपायुक्त जमान वट्टू ने कहा, 'शनिवार रात एक मरीज के साथी ने मुझे साहीवाल शहर के जिला मुख्यालय अस्पताल के बाल चिकित्सा वार्ड का एसी नहीं चलने से बच्चों की मौत होने की जानकारी दी। मैं तुरंत वार्ड में पहुंचा। एसी नहीं चलने से वहां का तापमान काफी बढ़ गया था।' वट्टू के अनुसार उन्होंने इस संबंध में प्रांतीय सरकार को एक पत्र भी लिखा है। पंजाब के स्वास्थ्य विभाग ने हालांकि एसी खराब होने की वजह से बच्चों की मौत की खबरों का खंडन किया है। प्रांत के स्वास्थ्य अवर सचिव रफकत अली ने कहा, 'इस मामले की फिर से जांच कराई जाएगी क्योंकि पांच बच्चों की मौत उसी समय हो गई थी जब एसी ठीक से चल रहा था।' (आइएएनएस)

दूसरे की जान को न बन जाए खतरा, करवा दी बेटे की हत्या

टोक्यो : जापान के एक पूर्व शीर्ष अधिकारी ने इस डर से अपने बेटे की हत्या कर दी कि वह कहीं दूसरों की जान के लिए खतरा ना बन जाए। टोक्यो पुलिस ने सोमवार को यहां बताया कि कृषि विभाग में शीर्ष पद पर रहे 76 साल के हिदेकी कुमाजावा ने बीते शनिवार को अपने 44 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी। कुमाजावा ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वह एकांत में पड़े रहने वाले अपने बेटे से तंग आ चुके थे। उन्हें डर था कि कहीं वह दूसरों की हत्या ना कर दे। पिछले हफ्ते ही जापान में एकांत में रहने वाले एक शख्स ने चाकू से हमला कर दो लोगों की हत्या कर दी थी। उसने बस स्टैंड पर खड़ी स्कूली छात्राओं पर चाकू से हमले के बाद खुद को भी चाकू मारकर जान दे दी थी। जापान में एकांत में या सामाजिक रूप से अलग-थलग रहने के चलन को हीकिकोमोरी कहा जाता है। (एपी)

यूएई में तीसरी मंजिल से गिरी भारतीय बच्ची, हालत नाजुक

दुबई: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के शारजाह शहर में रहने वाले एक भारतीय परिवार की बच्ची तीसरी मंजिल के अपने फ्लैट की बालकनी से नीचे गिर गई। इतनी ऊंचाई से गिरने से छह साल की सफा की कई हड्डियां टूट गई हैं। उसकी हालत नाजुक है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, ऊंची इमारत की तीसरी मंजिल पर रहने वाले भारतीय परिवार की बेटी सफा बीते शनिवार को खेलते-खेलते बालकनी में पहुंच गई और नीचे गिर गई। घर पर उस वक्त उसके मां-बाप भी मौजूद थे। पुलिस घटना के पीछे की वजह जानने की कोशिश में लगी है। हाल में यूएई में ऊंची इमारतों से बच्चे के गिरने की घटनाएं बढ़ी हैं। बीते तीन महीनों में यह 16वां हादसा है। (प्रेट्र)

ब्रेक्जिट पर घमासान के बीच ब्रिटेन पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप

अहम दौरा ▶ बकिंघम पैलेस में हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत

लंदन, एपी : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को तीन दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे। उनके साथ पत्नी मेलानिया भी हैं। ट्रंप का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब ब्रेक्जिट को लेकर ब्रिटेन में सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री टेरीजा मे एलान कर चुकी हैं कि अपना उत्तराधिकारी चुने जाने पर वह पीएम पद से इस्तीफा दे देंगी।

बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरी बार ब्रिटेन आए ट्रंप इस दौरे में प्रधानमंत्री टेरीजा मे के साथ जलवायु परिवर्तन और चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी हुआवे समेत कई अहम मसलों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत बकिंघम पैलेस से की, जहां 93 साल की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ट्रंप और मेलानिया का स्वागत किया। इस दौरान प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला भी मौजूद रहीं। बकिंघम पैलेस में ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

ट्रंप ब्रिटेन में तीन दिन रहने के दौरान कई समारोहों में भी शिरकत करेंगे, लेकिन सभी की नजरें ट्रंप के सम्मान में दिए जाने वाले रात्रिभोज पर लगी हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने इस भोज का बहिष्कार किया है। ट्रंप ने अपने एयरफोर्स वन विमान से लंदन में उतरने से पहले ट्वीट किया, 'मैं अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त ब्रिटेन से मिलने के लिए उत्सुक हूं और अपने दौरे का इंतजार कर रहा हूं।' उनके आगमन से पहले टेरीजा ने भी कहा, 'सुरक्षा और समृद्धि के लिए हमारे संबंध बहुत सालों से हैं और आगे भी पीढ़ियों तक बने रहेंगे।'

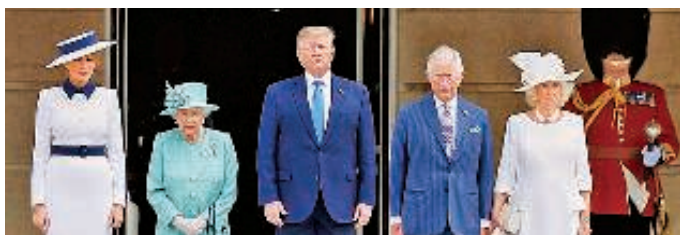

लंदन में सोमवार को बकिंघम पैलेस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और और उनकी पत्नी के स्वागत समारोह में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला भी मौजूद रहीं। एएफपी

ट्रंप ने लंदन के मेयर को बताया नाकारा

लंदन, रायटर : ट्रंप ने लंदन के मेयर सादिक खान को नाकारा करार दिया है। खान ने एक दिन पहले ट्रंप को फासीवादी और उनके बर्ताव को विभाजनकारी बताया था। इसके जवाब में ट्रंप ने ट्वीट में कहा, 'लंदन के मेयर के तौर पर भयावह काम करने वाले सादिक खान नाकारा हैं। उन्हें मेरी जगह लंदन के अपराधों पर ध्यान देना चाहिए।'

फिर आसमान में दिखेगा बेबी ट्रंप गुब्बारा

लंदन, आइएएनएस : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध करने के लिए लंदन के आसमान में फिर गुब्बारा दिखेगा। 2018 में उनकी यात्रा के दौरान भी लंदन के आसमान में बेबी ट्रंप गुब्बारा दिखा था। म्यूजियम ऑफ लंदन ने घोषणा की कि वह स्थायी तौर पर विरोध जाहिर करने के लिए दो बड़े आकार के गुब्बारे खरीदेगा। इनके जरिये ट्रंप और लंदन के मेयर सादिक खान को बेबी के तौर पर चित्रित किया जाएगा।

विरोध प्रदर्शन के बीच श्रीलंका के दो गवर्नरों ने दिया इस्तीफा

कोलंबो, प्रेट्र : श्रीलंका के बहुसंख्यक बौद्ध समुदाय के भिक्षुओं के भारी विरोध प्रदर्शन के चलते दो मुस्लिम गवर्नरों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन्हें बर्खास्त करने की मांग को लेकर हजारों लोग कैंडी शहर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ईस्टर आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का कथित तौर पर समर्थन किया था।

अधिकारियों के अनुसार, पश्चिमी प्रांत के गवर्नर अजत सैली और पूर्वी प्रांत के गवर्नर एमएएलएम हिसबुल्ला ने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेन को सौंप दिया है। इन दोनों मुस्लिम गवर्नरों की नियुक्ति सिरिसेन ने ही की थी। दोनों ने हालांकि आतंकियों के समर्थन के आरोप से इन्कार किया है। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर चार दिन पहले सांसद बौद्ध भिक्षु अतुरेलिया रत्ना कैंडी में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। उन्होंने कहा था, 'दोनों मुस्लिम गवर्नरों को बर्खास्त किए जाने के बाद ही मैं भूख हड़ताल खत्म करूंगा।' इस दौरान करीब दस हजार बौद्ध यहां के प्रसिद्ध मंदिर में जमा थे और उन्होंने मुस्लिम विरोधी नारे लगाए थे।

श्रीलंका में गत 21 अप्रैल को तीन चर्चों और तीन होटलों पर हुए आत्मघाती हमलों में करीब 260 लोग मारे गए थे। इसके लिए आइएस से जुड़े स्थानीय आतंकी संगठन नेशनल तौहीद जमात को जिम्मेदार ठहराया गया था। इन हमलों के बाद देश में कई मस्जिदों और मुस्लिम प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया था। बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति ने पुलिस महानिदेशक को निलंबित कर दिया था और अब वह श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं।

अमेरिका में पढ़ना किसी खतरे से कम नहीं : चीन

बीजिंग, एएफपी : कारोबारी तनाव के बीच चीन ने अमेरिका में पढ़ने की चाहत रखने वाले अपने छात्रों को आगाह किया है कि वे किसी खतरे में पड़ सकते हैं। छात्रों और शिक्षकों से कहा गया है कि अमेरिकी की ओर से उन्हें वीजा देने से मना किया जा सकता है या वीजा देने में देरी की जा सकती है।

चीन ने यह चेतावनी ऐसे समय पर जारी की है जब दोनों देशों में कारोबारी तनाव दूर करने के लिए हो रही वार्ता में गतिरोध आ गया है। अमेरिका, चीन पर यह आरोप भी लगाता आ रहा है कि वह विवादित दक्षिण चीन सागर का सैन्यीकरण कर रहा है। हाल के कुछ महीनों में अमेरिका के कई अधिकारी और सांसद यह चिंता भी जाहिर कर चुके हैं कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार चीनी छात्रों और शिक्षकों का जासूस के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है।

चीन के शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, 'अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आवेदन कर रहे छात्रों को खुद को वीजा संबंधी दिक्कतों और सख्त मूल्यांकन के लिए तैयार रखना चाहिए क्योंकि हाल में चीनी छात्रों और शिक्षकों को वीजा पाने के लिए कई तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ा।'

विदेशी छात्रों में एक तिहाई चीनी: पिछले साल अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने वाले विदेशी छात्रों में करीब एक तिहाई चीनी थे। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पिछले साल करीब तीन लाख 60 हजार चीनी छात्रों ने दाखिला लिया था।

14 अरब डॉलर का योगदान: चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने अमेरिकी डाटा के हवाले से अनुमान लगाया है कि 2017 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में चीनी छात्रों ने 14 अरब डॉलर (करीब 97 हजार करोड़ रुपये) का योगदान दिया था।

गेंग शुआंग। फाइल फोटो

अनावश्यक बाधाएं खड़ी कर रहा अमेरिका : गेंग शुआंग

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने सोमवार को कहा, 'दोनों देशों के लोगों के बीच आदान-प्रदान में अमेरिका अनावश्यक बाधाएं खड़ी कर रहा है। इसका चीन और अमेरिका के शिक्षा क्षेत्रों के साथ ही वहां पढ़ रहे चीनी छात्र भी व्यापक विरोध कर रहे हैं।'

समझौता हो या न हो, ईयू से अलग होगा ब्रिटेन : बोरिस

लंदन, रायटर : ब्रेक्जिट (यूरोपीय यूनियन से अलगाव) के लिए होने वाले समझौते को संसद स्वीकृति दे या न दे, 31 अक्टूबर को संबंध विच्छेद की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यह एलान ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने किया है। इसी के साथ सोमवार को उन्होंने अपनी उम्मीदवारी से जुड़ा अभियान भी शुरू कर दिया।

टेरीजा मे पूर्व घोषणा के अनुसार सात जून को अपने पद से इस्तीफा देंगी और उसके बाद सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगी। यह प्रक्रिया करीब दो महीने तक चल सकती है। ब्रेक्जिट प्रक्रिया को लेकर पार्टी को एकजुट न रख पाने के कारण टेरीजा को इस्तीफा देना पड़ रहा है। उनके द्वारा संसद में प्रस्तुत समझौते का प्रस्ताव तीन बार गिर गया था। बोरिस ने ब्रेक्जिट को लेकर टेरीजा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे और उसके बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

अब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में बिना समझौते के भी ब्रेक्जिट प्रक्रिया पूरी करने का एलान ट्विटर के जरिये किया है। ब्रिटेन यात्रा पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही सलाह दी है। ट्रंप ने बोरिस की

पीएम पद के अग्रणी उम्मीदवार बोरिस जॉनसन ने शुरू किया प्रचार अभियान

बोरिस जॉनसन। फाइल फोटो

उम्मीदवारी का समर्थन किया है। जबकि बोरिस के प्रतिद्वंद्वी जेरेमी हंट ने बेहतर समझौते के लिए साथियों से बातचीत करने और विपक्ष से भी समर्थन जुटाने के लिए प्रयास की बात कही है। उन्होंने विश्वास जताया है कि प्रधानमंत्री के रूप में वह 31 अक्टूबर तक ब्रेक्जिट को पूरा कराने में सफल होंगे। बोरिस और हंट के अतिरिक्त कंजरवेटिव पार्टी के 11 और नेता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। पार्टी के 1,60,000 सदस्य इनके भाग्य का फैसला करेंगे।

राजनीति पसंद नहीं पर पीएम बनना चाहती हूं : प्रियंका चोपड़ा

वाशिंगटन, एएनआइ : वैश्विक स्तर पर पहचान बना चुकीं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा (36) का कहना है कि उन्हें राजनीति से जुड़ी चीजें पसंद नहीं हैं, लेकिन वह भारत की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। साथ ही वह चाहती हैं कि उनके पति और गायक निक जोनस (26) अमेरिका के राष्ट्रपति बनें।

'द संडे टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रियंका ने कहा, '... लेकिन मैं जानती हूं कि हम वास्तव में बदलाव लाना चाहते हैं।' प्रियंका ने कहा कि उन्होंने अभी तक की जिंदगी में अराजनीतिक रहने की कोशिश की है क्योंकि उन्हें मानवता के लिए काम करना पसंद है। प्रियंका ने इस तथ्य से इन्कार नहीं किया कि निक व्हाइट हाउस में रहने के लिए अपनी रॉकस्टार की जिंदगी खो सकते हैं और यह एक महान नेता बनने के लिए होगा।

मालूम हो कि 2017 में फोर्ब्स पत्रिका ने बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को दुनिया की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया था। वह यूनीसेफ की सद्भावना दूत भी हैं और महिला शिक्षा व महिला अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम करती रहती हैं।

जेल भी पहुंचा सकता है प्रैंक सोच समझकर चुनें विषय

न्यूयॉर्क टाइम्स से

- बेहूदे प्रैंक वीडियो के चलते प्रैंकस्टर को 15 महीने की जेल
- सजा के तौर पर 15.50 लाख रुपये का हर्जाना भी भरना होगा

मैड्रिड : स्पेन में एक यूट्यूब प्रैंकस्टर को बेहूदा मजाक करना भारी पड़ गया। उसे 15 महीने की जेल की सजा और 20,000 यूरो (करीब 15.50 लाख रुपये) का हर्जाना देने को कहा गया है। रीसेट के नाम से यूट्यूब पर प्रैंक वीडियो डालने वाले कांगुआ रेन ने एक गरीब व्यक्ति से साथ शरारत करते हुए उसे बिस्किट में क्रीम की जगह टूथपेस्ट रखकर दे दिया था।

मामला 2017 का है। उस समय रेन की उम्र 19 साल थी। यूट्यूब पर अपने 12 लाख फॉलोअर्स में से किसी एक की चुनौती पर रेन ने बिस्किट में टूथपेस्ट भरने का बेहूदा मजाक किया था। उसने एक सुपरमार्केट के बाहर फुटपाथ पर बैठे व्यक्ति को टूथपेस्ट भरा बिस्किट दिया था। बिस्किट को असली दिखाने के लिए उसने साथ में 20 यूरो (करीब 1,500 रुपये) का बिल भी दिखाया था। जैसे ही उस व्यक्ति ने बिस्किट खाया, उसे उल्टी हो गई। वीडियो को लेकर लोगों ने रेन की कड़ी आलोचना की थी।

अब उसे एक गरीब के सम्मान को ठेस पहुंचाने के आरोप में 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर उसके चैनल को पांच साल के लिए बंद करने का भी आदेश सुनाया है। इस वीडियो पर आलोचना के बाद रेन ने उस व्यक्ति से मिलकर माफी भी मांगी थी और उसकी बेटी को 300 यूरो (करीब 23,250 रुपये) देकर कानूनी कार्यवाही नहीं करने की अपील भी की थी। उसने अदालत के सामने अपने बचाव में कई दलीलें भी दीं, लेकिन उसके अन्य वीडियो को देखते हुए अदालत ने उसे माफी नहीं दी।

क्या होता है प्रैंक वीडियो? : प्रैंक आमतौर पर किसी को चौंका देने वाली शरारत को कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में यूट्यूब से लेकर तमाम सोशल मीडिया पर ऐसे ढेरों वीडियो सामने आए हैं। इनमें लोग तरह-तरह की शरारत करते हुए वीडियो बनाकर शेयर करते हैं। इस तरह के कई यूट्यूब चैनलों को लाखों की संख्या में लोग फॉलो करते हैं।

स्वीडन में कोर्ट का असांजे की गिरफ्तारी के आदेश से इन्कार

उपासला, एएफपी : स्वीडन की कोर्ट ने विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार करने की प्रोसीक्यूटर की अर्जी को अस्वीकार कर दिया है। कहा है- असांजे इस समय ब्रिटिश जेल में है। यूरोपीय जांच आदेश लेकर उससे वहां पर पूछताछ की जा सकती है। इसके लिए असांजे को प्रत्यर्पित कर स्वीडन लाने और उसे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है।

जूलियन असांजे पर 2010 में स्वीडन में उसकी एक पूर्व सहयोगी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। यह वह दौर था जब विकिलीक्स नित नए अमेरिकी गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक कर रहा था। अमेरिका में असांजे के खिलाफ गोपनीय दस्तावेज चुराने और उन्हें सार्वजनिक कर राष्ट्र हित को नुकसान पहुंचाने के कई मुकदमे दर्ज हैं। अमेरिका अब इन मुकदमों के सिलसिले में ब्रिटेन से असांजे के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। 2010 में स्वीडन में दर्ज दुष्कर्म के मुकदमे के सिलसिले में लंदन में जमानत लेकर असांजे ने वहां स्थित इक्वाडोर के दूतावास में शरण ले ली थी। सात साल बाद बीती अप्रैल में जब वह दूतावास से बाहर आया तो उसे जमानत शर्तों के उल्लंघन के आरोप में लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

भारत और चीन ने निरस्त्रीकरण पर की बातचीत : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन ने निरस्त्रीकरण, अप्रसार और हथियारों पर नियंत्रण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है। दोनों पक्षों ने निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर सोमवार को भारत-चीन द्विपक्षीय वार्ता के छठे दौर के दौरान इन मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अतिरिक्त सचिव (निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामले) इंद्र मणि पांडेय ने किया वहीं चीनी पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के हथियार नियंत्रण विभाग के महानिदेशक राजदूत फू कांग ने किया।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने निरस्त्रीकरण, अप्रसार और हथियार नियंत्रण से संबंधित परस्पर हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने भविष्य में नियमित अंतराल पर बातचीत जारी रखने का फैसला किया। राजदूत फू कांग ने अगले दौर की बातचीत के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल को परस्पर सुविधाजनक समय पर बीजिंग आने का आमंत्रण दिया।

विदेश मंत्री ने की सचिवों से मुलाकात : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को अपने मंत्रालय के विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रमुखों और सचिवों से मुलाकात की। जयशंकर के कार्यभार संभालने के तीन बाद हुई बैठक में विदेश सचिव विजय गोखले मौजूद थे। मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि बैठक सुबह हुई। समझा जाता है कि जयशंकर ने बैठक में अगले कुछ वर्षों के लिए विदेश मंत्रालय के कार्य के बारे में अपना दृष्टिकोण साझा किया।

यूएई के प्रिंस हैं अरब जगत से सबसे शक्तिशाली नेता

वाशिंगटन, प्रेट्र : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के प्रिंस मुहम्मद बिन जायेद अरब जगत के सबसे शक्तिशाली नेता हैं। वह यूएई के वास्तविक शासक हैं और 1.3 ट्रिलियन डॉलर (90 लाख करोड़ रुपये) के खजाने को नियंत्रित करते हैं। यूएई के अतिरिक्त यमन, लीबिया, सोमालिया और मिस्र में उनके विशेष बल कार्रवाई के लिए तैनात हैं। यह रिपोर्ट अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हुई है।

अखबार के अनुसार 58 वर्षीय अबूधाबी के युवराज को एमबीजेड के नाम से भी जाना जाता है। वह अमेरिका में भी सबसे असरदार विदेशी नेताओं में शुमार हैं। अमेरिका मानता है कि अरब जगत में उनका प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। उनके पास इलाके की सबसे सशक्त और उच्च तकनीक उपकरणों वाली सेना है। यह सेना अमेरिका के साथ मिलकर निरंतर ऑपरेशन चलाती रहती है। प्रिंस मुहम्मद इस सेना के उप सर्वोच्च कमांडर हैं। उन्होंने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है। हाल के वर्षों में दो बार की भारत यात्रा के दौरान प्रिंस ने भारत के साथ रक्षा के साथ ही घनिष्ठ व्यापार सहयोग वाले संबंध भी स्थापित किए हैं।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दो बार यूएई की यात्रा की है। दोनों नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर भी घनिष्ठ संबंध बनाए हैं। मोदी को यूएई ने अपना सर्वोच्च सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त मुहम्मद विन जायेद को अमेरिकी अखबार ने बताया हर तरह से असरदार

प्रिंस मुहम्मद बिन जायेद। फाइल फोटो

दिया है और मोदी ने 30 मई को जब प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली तो सरकार ने अबूधाबी में एडीएनओसी बिल्डिंग को प्रकाश बिंदुओं से सजाकर खुशी जाहिर की। मोदी और प्रिंस मुहम्मद के प्रोर्टेट प्रदर्शित हुए। बता दें कि नवंबर 2003 में प्रिंस के पिता ने इन्हें उप-युवराज घोषित किया। पिता की मृत्यु के बाद वर्ष 2004 में इन्हें युवराज घोषित किया गया तथा वर्ष 2005 में संयुक्त अरब अमीरात की सेना का डिप्टी कमांडर नियुक्त किया गया। बाद में सेना में जनरल पद पर पदोन्नत हुए। वर्ष 2017 में भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि भी मौजूद रहे।

भारत ने ओआइसी के कश्मीर संबंधी उल्लेख को फिर खारिज किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने इस्लामी देशों के संगठन ओआइसी के कश्मीर संबंधी उल्लेख को एक बार फिर 'अस्वीकार्य' बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि जम्मू एवं कश्मीर ओआइसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और यह भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। ओआइसी ने सऊदी अरब के यूसुफ अल्डोबेय को जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष दूत नियुक्त किया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'हम 31 मई को सऊदी अरब के मक्का में ओआइसी की 14वीं बैठक में मंजूर अंतिम बयान में भारत के अभिन्न हिस्से के बारे में अस्वीकार्य उल्लेख को एक बार फिर खारिज करते हैं।' उन्होंने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और इससे जुड़ा मामला ओआइसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत यह बात दोहराता है कि ओआइसी को ऐसे अवांछित उल्लेखों से बचना चाहिए।

गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन ओआइसी में 57 सदस्य देश हैं और इनमें से 53 मुस्लिम बहुल देश हैं। पिछले शुक्रवार को मक्का में ओआइसी की 14वीं बैठक आयोजित हुई और मुस्लिम देशों के कई नेता इसमें शामिल हुए। बैटक में कश्मीर के संदर्भ में कथित मानवाधिकारों के हनन का विषय उठाया गया और भारत से वहां संयुक्त राष्ट्र आयोग और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन को जाने देने की अनुमति देने को कहा गया। इससे पहले भी मार्च में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि जम्मू एवं कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है।

तानाशाह किम जोंग उन के साथ दिखा उत्तर कोरिया का पूर्व परमाणु दूत

प्योंगयांग : सेना के जवानों की पत्नियों द्वारा संगीतमय प्रस्तुति का आनंद लेते उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन। इस मौके पर उत्तर कोरिया के पूर्व परमाणु दूत किम योंग चोल (लाल घेरे में) भी मौजूद रहे। एपी

सियोल, रायटर : उत्तर कोरिया के पूर्व परमाणु दूत किम योंग चोल को देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के साथ देखा गया है। इससे यह जाहिर होता है कि वह जेल में नहीं हैं और सुरक्षित हैं। बीते शुक्रवार को विदेशी मीडिया में ऐसी खबरें आई थीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वियतनाम में हुई शिखर वार्ता विफल रहने के कारण किम ने अपने पांच अधिकारियों की जान ले ली और चोल समेत कुछ को जेल में डाल दिया है।

उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी केसीएनए ने सोमवार को कहा कि चोल उन 12 शीर्ष अधिकारियों में शामिल थे जिन्होंने रविवार को किम जोंग उन और उनकी पत्नी री सोल जू के साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा। इस कार्यक्रम को उत्तर कोरियाई सैन्य अधिकारियों की पत्नियों ने प्रस्तुत किया था। पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया के चोसुन इल्बो अखबार ने एक उत्तर कोरियाई सूत्र के हवाले से खबर दी थी कि चोल को जेल में डाल दिया गया है और उनसे मजदूरी कराई जा रही है। चोल को किम का दायां हाथ बताया जाता था। गत फरवरी में वियतनाम वार्ता से पहले वह उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री के तौर पर काम करते थे। ट्रंप और किम की दूसरी मुलाकात से पहले चोल ने ह्वाइट हाउस का दौरा किया था। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो से मुलाकात भी की थी। अमेरिकी विदेश मंत्री से रविवार को जब अपने उत्तर कोरियाई समकक्ष चोल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया। इससे पहले एक इंटरव्यू में पोंपियो ने कहा था, ऐसा लग रहा है कि आगामी बातचीत में मेरा उत्तर कोरियाई समकक्ष कोई और होगा।

ये भी जानिए
पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 348 रन बिनाए। यह पाकिस्तान का किसी बल्लेबाज के शतक लगाए बिना सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इससे पहले उन्होंने 2008 में जिंबाब्वे के खिलाफ 347 रन बनाए थे।

ओपनर

- कल विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगा भारत
- खराब फॉर्म में चल रहे ओपनरों पर होगा अच्छा करने का दबाव

अभिषेक त्रिपाठी ● साउथैंप्टन

सोमवार को जब बादलों से ढके रोज बाउल स्टेडियम की पिच के ऊपर से कवर हटाए गए तो उसकी हरी घास देखकर तेज गेंदबाजों के मुंह में पानी आ सकता था, लेकिन कुछ मिनटों में ही पिच को गंजा कर दिया गया। इसका मतलब साफ है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) चाहती है कि भारत जब बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत करे तो दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को मजा आए। हालांकि, यह सब तभी होगा जब बारिश मैच में खलल ना डाले, क्योंकि बुधवार को यहां बारिश होने की संभावना 60 फीसद है। हालांकि, 2001 में बने इस स्टेडियम का ड्रेनेज सिस्टम शानदार है जिससे मैच के पूरा धुलने की संभावना ना के बराबर है। हालांकि, डकवर्थ-लुइस नियम के प्रयोग को होते हुए यहां पर देखा जा सकता है।

लोढ़ा समिति की सिफारिशों के कारण भारतीय टीम के खिलाड़ी जिन टूर्नामेंटों में खेल रहे हैं उनके बीच में कम से कम 15 दिन का अंतर होना चाहिए। पहले आइपीएल का फाइनल 20 मई के आसपास प्रस्तावित था और यही कारण था कि आइसीसी ने विश्व कप में टीम इंडिया का पहला मैच पांच जून को रखा, लेकिन भारत में लोकसभा चुनावों और अन्य वजहों से आइपीएल फाइनल 12 मई को हुआ। यही कारण है कि टीम इंडिया जब अपना पहला विश्व कप मैच खेल रही होगी तब दक्षिण अफ्रीका इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला खेलेगी। लगातार दो मुकाबले हारने के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम सोमवार को ही साउथैंप्टन पहुंची, जबकि भारतीय टीम कई दिनों से यहां अभ्यास कर रही है। उसने यहां की परिस्थितियों में काफी अभ्यास कर लिया है। सोमवार को भी विराट एंड कंपनी ने जमकर पसीना बहाया।

ओपनरों पर होगा दारोमदार : साउथैंप्टन में मैच के दिन बारिश होने की उम्मीद है और मौसम नौ डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अच्छी बात यह है कि पिच पर घास नहीं होगी और यहां का रिकॉर्ड बल्लेबाजों की सफलता की कहानी कहता है। इसके बावजूद टीम इंडिया के ओपनरों को संभलकर रहना होगा क्योंकि ओवल में हुए पहले अभ्यास मैच में रोहित शर्मा (02) और शिखर धवन (02) टीम के 10 रन पूरे होते-होते पवेलियन पहुंच गए थे, तो कार्डिफ में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे अभ्यास मैच में 50 रन के कुल योग पर दोनों आउट हो गए थे जिसमें शिखर ने सिर्फ एक तो शर्मा ने 19 रन बनाए। दोनों ही मैचों में तेज गेंदबाजों ने ही इन दोनों का शिकार किया। पहले अभ्यास मैच में भले ही विराट ने टॉस जीतकर तेज गेंदबाजी के सामने अभ्यास करने के लिए पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया हो, लेकिन बाकी कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का ही निर्णय ले रहे हैं क्योंकि सुबह ठंडे मौसम और आसमान में बादल होने के कारण तेज गेंदबाज नाचती गेंदों पर बल्लेबाजों, खासतौर पर ओपनरों को ब्रेक डांस करने को मजबूर कर देते हैं।

शिखर-रोहित ने कमजोरियों को परखा: इसी को देखते हुए शिखर और रोहित ने सोमवार को जमकर अभ्यास किया। रोहित ने मुहम्मद शमी सहित सभी तेज गेंदबाजों को नेट सत्र में आड़े हाथ लिया। उन्होंने शमी की बाउंसर पर अच्छा हुक शॉट लगाया तो युजवेंद्रा सिंह चहल की गेंद को स्टैंड पर पहुंचा दिया। कुल मिलाकर उन्होंने आक्रामक रहने पर ध्यान दिया, जबकि धवन संभल-संभलकर खेल रहे थे। वह अपनी गलतियों को चेक कर रहे थे। बल्लेबाजी को लेकर उन्होंने मुख्य कोच रवि शास्त्री और सहायक कोच संजय बांगर से बात भी की। इसमें कोई शक नहीं कि अभ्यास मैचों के खराब प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया इन्हीं दो ओपनरों के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।

टीम संयोजन पर ध्यान: अब बात करते हैं टीम इंडिया के संयोजन की, जिसके ऊपर भारत की पहली जीत और आगे का अभियान निर्भर करेगा। यहां का मौसम और पिच एक-दूसरे के उलट हैं। और यही दोनों टीम इंडिया की दिक्कत हैं क्योंकि अगर पिच के साथ जाएं तो भारत को दो कलाई के स्पिनरों कुलदीप यादव और युजवेंद्रा सिंह चहल को खिलाना होगा। इन दोनों का रिकॉर्ड भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छा है और एबी डिविलियर्स भी दक्षिण अफ्रीकी टीम में नहीं हैं। ऐसे में टीम इसके अलावा दो सिर्फ दो तेज गेंदबाजों और एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को जगह दे सकती है। यहां सोमवार को हल्की बारिश हुई है और मंगलवार को बारिश होती है तो पिच में अच्छी नमी आ जाएगी। बुधवार को आसमान में बादल रहेंगे। ऐसे परिस्थिति में टीम के पास तीन तेज गेंदबाजों मुहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह के साथ उतरने का विकल्प होगा। पांड्या चौथे तेज गेंदबाज होंगे और किसी एक स्पिनर को अंतिम एकादश में जगह दी जाएगी। केदार जाधव ने सोमवार को भी अभ्यास किया और अगर वह खेलते हैं तो फिर टीम के पास अतिरिक्त गेंदबाज होगा। उनके नहीं खेलने पर विजय शंकर को खिलाया जा सकता है क्योंकि वह बल्ले के साथ गेंदबाजी भी कर सकते हैं। बल्लेबाजी में दोनों ओपनरों के अलावा कप्तान विराट कोहली, केएल राहुल और महेंद्र सिंह धौनी की जगह पक्की है।

भारतीय ओपनर शिखर धवन और रोहित शर्मा ● फाइल फोटो, एएफपी

फिर विवादों में टीम इंडिया

अभिषेक त्रिपाठी ● साउथैंप्टन

विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया और मीडिया के बीच कई वर्षों से सब कुछ अच्छा नहीं है, और इसकी एक बानगी सोमवार को भी देखने को मिली। टीम इंडिया के मीडिया मैनेजर की तरफ से बताया गया था कि अभ्यास के बाद टीम का एक खिलाड़ी प्रेस कांफ्रेंस के लिए आएगा। इसी कारण भारतीय मीडिया कांफ्रेंस रूम में इकठ्ठा हो गई। आइसीसी की तरफ से आए प्रतिनिधियों ने प्रेस कांफ्रेंस के सारे नियमों की जानकारी भी दे दी। 15 मिनट इंतजार करने के बाद मीडिया मैनेजर ने कहा कि टीम इंडिया का कोई खिलाड़ी प्रेस कांफ्रेंस में नहीं आएगा, बल्कि टीम को अभ्यास कराने के लिए यहां आए दो तेज गेंदबाज आवेश खान और दीपक चाहर आएंगे।

इसके बाद वहां मौजूद मीडिया नाराज हो गया। उन्हें बताया गया कि यह आइसीसी का टूर्नामेंट है और प्रेस कांफ्रेंस में ऐसे खिलाड़ी को भेजना चाहिए जो इस टूर्नामेंट में खेल रहा है। ऐसे में भारतीय मीडिया मैनेजर ने हास्यास्पद जवाब देते हुए कहा कि ये दोनों मंगलवार को भारत जा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा पब्लिसिटी मिल जाए। अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह के निर्देश मीडिया मैनेजर को टीम प्रबंधन ने दिए या उन्होंने यह खुद ही कहा। जबसे भारतीय टीम इंग्लैंड आई है तब से कप्तानों की प्रेस कांफ्रेंस को छोड़कर उनकी तरफ से किसी ने भी मीडिया से बातचीत नहीं की है। इससे पहले 2015 विश्व कप में भी कप्तान महेंद्र सिंह धौनी की प्रेस कांफ्रेंस को लेकर विवाद हुआ। उसमें मैच जल्दी खत्म हो गया था और उसके बाद धौनी फुटबॉल खेलने लगे। जब मीडिया मैनेजर से कहा गया कि नियम के अनुसार प्रेस कांफ्रेंस कराई जाए तो धौनी झुंझलाते हुए आए और कहने लगे कि इसकी वजह से मैं फुटबॉल नहीं खेल पाया। इससे पहले 2010 में श्रीलंका दौरे के समय में मीडिया ने तत्कालीन कप्तान धौनी की प्रेस कांफ्रेंस से वॉकआउट किया था। तब भी वह मैच खत्म होने के बाद प्रेस कांफ्रेंस की जगह फुटबॉल खेलने में व्यस्त हो गए थे और कई बार जानकारी मिलने के बाद भी समय पर प्रेस कांफ्रेंस में नहीं आए थे।

विश्व कप डायरी
- पहले मैच से पूर्व ही विराट की टीम ने दिखाए नखरे
- भारतीय मीडिया मैनेजर के जवाब से नाराज हुआ मीडिया

बुमराह का हुआ डोप टेस्ट

साउथैंप्टन: राष्ट्रीय डोपिंग रोधक एजेंसी (नाडा) से बचते आ रहे भारतीय क्रिकेटर आइसीसी विश्व कप में विश्व डोपिंग रोधक एजेंसी (वाडा) से नहीं बच पाएंगे और इस वैश्विक एजेंसी ने सोमवार को भारत के अभ्यास सत्र के बीच में ही तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का डोप टेस्ट किया। विश्व कप के दौरान और भी भारतीय खिलाड़ियों के डोप टेस्ट हो सकते हैं। यह आइसीसी का टूर्नामेंट है और इसलिए बीसीसीआइ या टीम इंडिया मना नहीं कर सकती है।

जब टीम रोज बाउल स्टेडियम में अभ्यास कर रही थी तभी एक डोप अधिकारी बुमराह का यूरीन सैंपल ले गया। इसके 45 मिनट बाद फिर बुमराह को नमूना एकत्रित करने के लिए ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार बुमराह के यूरीन और ब्लड सैंपल लिए गए हैं और आगे अन्य खिलाड़ियों के भी डोप टेस्ट हो सकते हैं। इससे पहले बीसीसीआइ टीम इंडिया के खिलाड़ियों के भारत में रहने के दौरान नाडा के जरिये डोप टेस्ट कराने से इन्कार करता रहा है। नाडा, वाडा से मान्यता प्राप्त भारतीय डोपिंग रोधक इकाई है। हालांकि हाल ही में बीसीसीआइ ने अपना रवैया नरम करते हुए छह महीने तक नाडा के साथ काम करने की बात कही थी। इसके मुताबिक आइसीसी, बीसीसीआइ और नाडा के बीच त्रिपक्षीय करार होगा, जिसके तहत पंजीकृत पूल में शामिल खिलाड़ियों के नमूने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) में नाडा के जरिये जाएंगे। इससे पहले स्वीडन की आइडीटीएम नमूने एकत्र करती थी। वाडा ने आइसीसी से साफ तौर पर कहा है कि बीसीसीआइ को नाडा के दायरे में आना होगा। बीसीसीआइ इस शर्त के साथ तैयार हो गया कि वह खुद मूत्र के नमूने एकत्र करके नाडा को देगा।

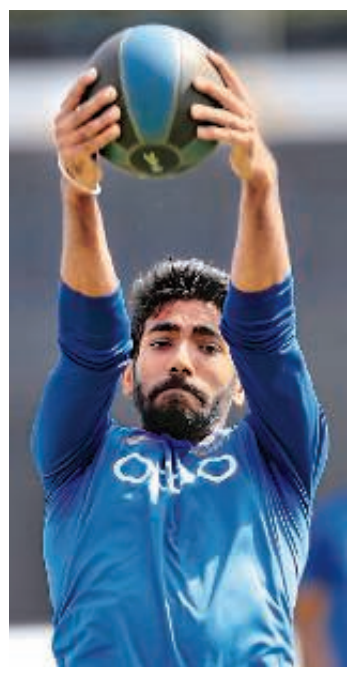

जसप्रीत बुमराह ● फाइल फोटो, एपी

कोहली की गेंदबाजी पर टीम को भरोसा नहीं

साउथैंप्टन : अपनी बल्लेबाजी से कई रिकॉर्ड बनाने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम गेंदबाजी में भी आठ अंतरराष्ट्रीय विकेट दर्ज हैं। इसके बावजूद उनकी टीम के साथी उनकी मध्यम गति की गेंदों पर उतना भरोसा नहीं करते हैं जितना की वह खुद अपनी गेंदबाजी पर करते हैं।

विश्व कप के मेजबान प्रसारणकर्ता को दिए साक्षात्कार में कोहली ने कहा, 'श्रीलंका (2017 में) में वनडे सीरीज के दौरान हम लगभग सारे मैच जीत रहे थे। मैंने महेंद्र सिंह धौनी से पूछा कि क्या मैं गेंदबाजी कर सकता हूं। जैसे ही मैं गेंदबाजी के लिए तैयार हुआ बुमराह (जसप्रीत) बाउंड्री से चिल्लाए और कहा कि कोई मजाक नहीं, यह अंतरराष्ट्रीय मैच है। टीम में किसी को भी मेरी गेंदबाजी पर उतना भरोसा नहीं है जितना मुझे है। इसके बाद मेरी पीठ में तकलीफ हो गई और मैंने कभी गेंदबाजी नहीं की।'

कोहली अब भी नेट पर गेंदबाजी करते हैं और इस हफ्ते यहां अभ्यास सत्र के दौरान भी उन्होंने गेंदबाजी की। कोहली ने कहा, 'जब मैं अकादमी (दिल्ली में) में था तो मैं जेम्स एंडरसन के एक्शन से गेंदबाजी करने का प्रयास करता था। बाद में जब मुझे उसके साथ खेलने का मौका मिला तो मैंने उन्हें यह बात बताई। हम दोनों इस पर काफी हंसे थे।'

कोहली ने वनडे और टी-20 में चार-चार विकेट लिए हैं, जबकि टेस्ट क्रिकेट में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।

दक्षिण अफ्रीका को स्टेन के अनुभव की दरकार होगी

के श्रीकांत
कलम से

जब चीजें शुरुआत में अनुकूल नहीं होतीं तो टीमें आमतौर पर हताश हो जाती हैं। मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीकी टीम में कुछ तो कमी है। यहां बात प्रतिभाओं की नहीं है। बल्कि, यह एक टीम के रूप में एकजुट प्रदर्शन नहीं कर पाने की उनकी अक्षमता है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। टीम के बल्लेबाजों में से डिकॉक और फाफ डुप्लेसिस को छोड़ दें तो कोई भी भरोसेमंद नहीं लग रहा है।

रबादा से काफी उम्मीदें थीं। मगर वह लय में नहीं दिखे और उनके खराब दिन का असर अन्य गेंदबाजों पर भी पड़ा। उम्मीद है कि भारत के खिलाफ डेल स्टेन को टीम में शामिल किया जाए। टीम इंडिया की मजबूत बल्लेबाजी को असहज करने के लिए दक्षिण अफ्रीका को स्टेन के अनुभव की दरकार होगी।

वहीं, भारतीय टीम तरोताजा होकर मैदान पर उतरेगी। दावेदार होने के दबाव को छोड़ दें तो टीम सकारात्मकता के साथ मैदान पर उतरेगी। मेरे हिसाब से बुमराह, भुवनेश्वर और शमी की तेज तिकड़ी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। वे इंग्लैंड के हालात से वाकिफ हैं। भारत के लिए उसकी ओपनिंग जोड़ी भी अहम होगी। रोहित-धवन बड़े मंच पर अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं और दोनों ही इंग्लैंड में सफेद गेंद से खेलने का लुत्फ उठाते हैं। रोज बाउल की पिच बल्लेबाजों के मुफीद है और टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रनों का पहाड़ खड़ा करना चाहेगी। दक्षिण अफ्रीकी टीम की टूर्नामेंट में शुरुआत अच्छी नहीं रही। एक और हार उनके लिए सेमीफाइनल के दरवाजे बंद कर सकती है। (टीसीएम)

हताश श्रीलंका का सामना आज अफगानिस्तान से

कार्डिफ (वेल्स), आइएएनएस: अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरी तरह मात खाने के बाद श्रीलंका को विश्व कप के अपने अगले मैच में मंगलवार को छुपे रुस्तम अफगानिस्तान से भिड़ना है। दोनों टीमें यहां सोफिया गार्डेंस स्टेडियम में मुकाबला खेलेंगी। दोनों टीमों का यह दूसरा मैच है। श्रीलंका को जहां न्यूजीलैंड ने रौंदा था तो वहीं अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने पटका था।

श्रीलंका कीवी टीम के सामने नतमस्तक हो गई थी और सिर्फ 136 रनों पर सिमट गई थी, वहीं अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खराब शुरुआत के बाद भी बल्लेबाजी में कड़ी प्रतिस्पर्धा दिखाई थी और 200 के पार जाने में सफल रही थी। इन दोनों की तुलना की जाए तो अफगानिस्तान की टीम इस समय बेहतर स्थिति में है, क्योंकि उसके अंदर जीतने के लिए वो जुनून और प्रतिद्वंद्विता है, जिसकी दरकार होती है। वहीं, श्रीलंका हताशा से भरी नजर आ रही है।

श्रीलंका को निश्चित तौर पर जीतने के लिए मानसिकता में बड़े बदलाव की जरूरत है। अफगानिस्तान की ताकत उसकी गेंदबाजी है। श्रीलंका की गेंदबाजी भी कमजोर है। सबसे अनुभवी लसित मलिंगा भी फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं।

डुप्लेसिस के लिए अब काफी मुश्किल हो गया है टूर्नामेंट

जैक कैलिस
ऑलराउंडर

इस बात का कोई मतलब नहीं है कि बांग्लादेश के हाथों दक्षिण अफ्रीका की हार सिर्फ एक झटका था। यह उससे कहीं अधिक गंभीर था और अब टूर्नामेंट फाफ डुप्लेसिस और उनके खिलाड़ियों के लिए काफी मुश्किल हो गया है। सौम्य सरकार ने शुरुआत से ही तेज गेंदबाजों पर अपने ही अंदाज में जवाबी हमला बोला।

चिंता की बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के पास प्लान-बी नहीं था। पिच उतनी तेज नहीं थी और बल्लेबाज भी भयभीत नहीं थे। यहां तक कि, वे शॉर्ट गेंदों पर भी आसानी से रन बना रहे थे। यदि शॉर्ट गेंदें काम नहीं कर रही थीं तो आपको बल्लेबाज को ड्राइव करने के लिए मजबूर करना चाहिए था। फिर भी मुझे यकीन है कि प्रोटियाज बुधवार को भारत के खिलाफ अपनी गलतियों से सीख लेंगे। यह मुकाबला अब दक्षिण अफ्रीका के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। यदि वे भारत से भी हार जाते हैं तो उन्हें सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए बाकी बचे अपने सभी छह मैच जीतने होंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ भारत को हमेशा से ही अपनी संभावित सेमीफाइनल की सूची में रखा था। मैं पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या वेस्टइंडीज में से किसी को अंतिम चार में देख सकता हूं, लेकिन मैं प्रोटियाज के लिए उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है कि स्टेन को भारत के खिलाफ खेलना होगा, भले ही वह शत-प्रतिशत फिट ना हों। नगिदी समय पर उबर नहीं पाएंगे और टीम को जीत की सख्त जरूरत है।

THE ULTIMATE INVERTER BATTERY
EXIDE INVATUBULAR

भारतीय टीम अगले घरेलू सत्र में खेलेगी 26 मैच

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- बीसीसीआइ ने किया 2019-20 सत्र के लिए कार्यक्रम घोषित
- पांच टेस्ट, नौ वनडे और 12 टी-20 मैचों को होगा आयोजन

बीसीसीआइ ने आगामी 2019-20 घरेलू सत्र की घोषणा कर दी है। इस घरेलू सत्र में कुल 26 मैच खेले जाएंगे, जिसमें पांच टेस्ट, नौ वनडे और 12 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच शामिल हैं।

बीसीसीआइ के मुताबिक, भारत के घरेलू सत्र का आगाज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गांधी-मंडेला सीरीज के लिए फ्रीडम ट्रॉफी से होगा, जिसका आयोजन 15 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। इस दौरान तीन तीन-20 और तीन टेस्ट मैच खेले जाएंगे। पहला टी-20 धर्मशाला में (15 सितंबर), दूसरा टी-20 मोहाली में (18 सितंबर), तीसरा टी-20 बेंगलुरु में (22 सितंबर), पहला टेस्ट विशाखापत्तनम में (2-6 अक्टूबर), दूसरा टेस्ट रांची में (10-14 अक्टूबर), तीसरा टेस्ट पुणे में (19-23 अक्टूबर) खेला जाएगा।

इसके बाद बांग्लादेश की टीम नवंबर में भारत का दौरा करेगी। इस दौरे पर बांग्लादेश की टीम भारत के साथ तीन टी-20 मैच और दो टेस्ट मैच खेलेगी। टी-20 मैच दिल्ली (तीन नवंबर), राजकोट (सात नवंबर) और नागपुर (10 नवंबर) में खेले जाएंगे। वहीं, टेस्ट मैच इंदौर (14-18 नवंबर) और कोलकाता (22-26 नंवबर) में खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज की टीम दिसंबर में भारत का दौरा करेगी, जिसमें वह टीम इंडिया के साथ तीन मैचों की टी-20 सीरीज और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। वेस्टइंडीज के साथ टी-20 मैच मुंबई (छह दिसंबर), तिरुअनंतपुरम (आठ दिसंबर) और हैदराबाद (11 दिसंबर) में होंगे, जबकि वनडे मैच चेन्नई (15 दिसंबर), विशाखापत्तनम (18 दिसंबर) और कटक (22 दिसंबर) में होंगे।

जिंबाब्वे की टीम जनवरी 2020 में भारत के दौर पर आएगी और तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेलेगी। ये मैच गुवाहाटी (पांच जनवरी), इंदौर (सात जनवरी) और पुणे (10 जनवरी) में होंगे। इसके तुरंत बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के मैच मुंबई (14 जनवरी), राजकोट (17 जनवरी) और बेंगलुरु (19 जनवरी) में होंगे।

ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम मार्च 2020 में तीन वनडे मैच खेलने भारत आएगी। इस सीरीज के मैच धर्मशाला (12 मार्च), लखनऊ (15 मार्च) और कोलकाता (18 मार्च) में होंगे।

पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दी 14 रनों से शिकस्त, काम नहीं आए रूट और बटलर के शतक, हफीज बने मैन ऑफ द मैच

पाकिस्तान का अंग्रेजों पर पलटवार

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अगले मैच में कैसा प्रदर्शन करेगी यह बता पाना बेहद ही मुश्किल होता है। पाकिस्तानी टीम का हाल के वर्षों में यह इतिहास रहा है। एक मैच में टीम चौकाने वाला प्रदर्शन करती है तो दूसरे ही मैच में अपने प्रदर्शन से प्रशंसकों को शर्मिंदा कर देती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ एक मैच पहले पाकिस्तानी टीम 105 रनों पर ढेर हुई थी तो अब सोमवार को नॉटिंघम में विश्व कप के अपने दूसरे मुकाबले में उसने इंग्लैंड के खिलाफ 50 ओवर में आठ विकेट पर 348 रन बना डाले और यह मुकाबला 14 रनों से जीत लिया। जो रूट और जोस बटलर के शतक खराब गए और इंग्लैंड 50 ओवर में नौ विकेट पर 334 रन ही बना सकी। इसी के साथ पाकिस्तान ने लगातार 11 हार का सिलसिला तोड़ दिया। वहीं, इंग्लैंड को चार साल बाद घर में लक्ष्य का पीछा करते हुए शिकस्त झेलनी पड़ी।

349 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड के पास इतिहास रचने का मौका था, क्योंकि विश्व कप इतिहास में अब तक इतने बड़े लक्ष्य का कोई भी टीम पीछा नहीं कर पाई है। इंग्लैंड की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। 12 रनों के स्कोर पर ही शादाब खान ने आक्रामक बल्लेबाज जेसन रॉय (08) को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद 60 रनों के स्कोर पर जॉनी बेयरस्टो (32) भी चलते बने। कुछ देर बाद कप्तान इयोन मोर्गन (09) को मुहम्मद हफीज ने चलता किया। वहीं शोएब मलिक ने बेन स्टोक्स (13) को आउट करके इंग्लैंड को मुश्किल में डाल दिया था, लेकिन विश्व की नंबर एक टीम ऐसे हार नहीं मानने वाली थी। रूट और बटलर ने पांचवें विकेट के लिए 118 रनों की साझेदारी करके मैच बनाना शुरू किया, लेकिन रूट शतक लगाते ही गलती कर बैठे और शादाब की गेंद पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बटलर का विकेट गंवाना इंग्लैंड को भारी पड़ गया। मुहम्मद आमिर ने उन्हें वहाब रियाज के हाथों कैच कराकर वापस भेजा। इसके बाद मोइन अली (19) और क्रिस वोक्स (21) आउट हुए और इंग्लैंड की मैच जीतकर इतिहास रचने की उम्मीदें धूमिल हो गई।

इससे पहले, पाकिस्तान के लिए इस मैच में मुहम्मद हफीज का अनुभव काम आया जिन्होंने 62 गेंदों पर आठ चौके और दो छक्कों की मदद से 84 रनों की पारी खेली। हफीज के अलावा बाबर आजम ने 68 गेंदों पर 63 रन बनाए। उनकी पारी में चार चौके और एक छक्का शामिल रहा।

दरअसल, इन दोनों ने जो पारियां खेलीं उसके लिए मंच इमाम उल हक और फखर जमां की सलामी जोड़ी ने तैयार किया था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया और पाकिस्तान की इस सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े। 15वें ओवर की पहली गेंद पर मोइन अली ने फखर को आउट कर इस साझेदारी पर विराम लगाया। फखर ने 40 गेंदों पर 38 रन बनाए। बाबर के साथ मिलकर इमाम ने टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया, लेकिन वह अपने अर्धशतक से छह रन से चूक गए। अली ने उनका विकेट 111 के कुल स्कोर पर चटकाया। इमाम ने तीन चौके और एक छक्के की मदद से 58 गेंदों पर 44 रन बनाए। यहां बाबर और हफीज ने अपने अनुभव का फायदा उठाया और बिना किसी जल्दबाजी के स्कोरबोर्ड चलाते रहे और मौका मिलने पर बाउंड्री भी लगाते रहे। इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी की। टीम का स्कोर 199 था तभी अली ने एक बार फिर साझेदारी तोड़ने का काम किया और इस बार उनका शिकार बाबर बने। बाबर ने अली की गेंद पर आगे बढ़कर शॉट खेला और क्रिस वोक्स ने उनका शानदार कैच पकड़ा।

स्कोर बोर्ड

टॉस: इंग्लैंड (गेंदबाजी)

पाकिस्तान — 348/8 (50 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
इमाम उल हक का. वोक्स बो. अली	44	58	03	01
फखर जमां रटं. बटलर बो. अली	36	40	06	00
बाबर आजम का. वोक्स बो. अली	63	66	04	01
मुहम्मद हफीज का. वोक्स बो. वुड	84	62	08	02
सरफराज अहमद का. एंड बो. वोक्स	55	44	05	00
आसिफ अली का. बेयरस्टो बो. वुड	14	11	00	01
शोएब मलिक का. मोर्गन बो. वोक्स	08	08	00	00
वहाब रियाज का. रूट बो. वोक्स	04	02	01	00
हसन अली नाबाद	10	05	00	01
शादाब खान नाबाद	10	04	02	00

अतिरिक्त: (बा-1, लेबा-8, वा-11) 20

कुल: 50 ओवर में आठ विकेट पर 348 रन

विकेट पतन: 1-82 (जमां, 14.1), 2-111 (इमाम, 20.1), 3-199 (बाबर, 32.5), 4-279 (हफीज, 42.4), 5-311 (अली, 46.1), 6-319 (अहमद, 47.2), 7-325 (वहाब, 47.5), 8-337 (मलिक, 49.1)

गेंदबाजी:
क्रिस वोक्स 8-1-73-3
जोफ्रा आर्चर 10-0-79-0
मोइन अली 10-0-50-3
मार्क वुड 10-0-53-2
बेन स्टोक्स 7-0-43-0
आदिल राशिद 5-0-43-0

अपनी पारी के दौरान शॉट खेलते हुए मुहम्मद हफीज ● रायटर

नेमार से जुड़े वीडियो की जांच करेगी ब्राजीली पुलिस

रियो डि जेनेरियो : रियो डि जेनेरियो के अधिकारियों का कहना है कि रियो की पुलिस उस वीडियो की जांच करेगी जो ब्रीजीली फुटबॉल स्टार नेमार ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर जारी की है। इस वीडियो में नेमार और उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला के बीच का अंतरंग दृश्य शामिल हैं। ऐसे में ब्राजील के इस दिग्गज फुटबॉलर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

जब नीदरलैंड्स में मेरा एमआरआई हुआ तब डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि मैं अगले दो साल तक नहीं खेल पाऊंगा। इससे मुझे काफी बड़ा सदमा लगा। अब मैं वापसी करके खुश हूं।
– रमनदीप सिंह, भारतीय हॉकी खिलाड़ी

फ्रेंच ओपन ▶ जर्मनी के जॉन लेनार्ड स्ट्रफ को सीधे सेटों में हराकर बनाया रिकॉर्ड

जोकोविक 10वीं बार क्वार्टर फाइनल में

रोलां गैरां पर लगातार 10वीं बार अंतिम-आठ में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बने नोवाक

पेरिस, रायटर : शीर्ष वरीय और दुनिया के नंबर एक सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने फ्रेंच ओपन के पुरुष सिंगल्स में अपने शानदार खेल को जारी रखते हुए सोमवार को क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 32 वर्षीय जोकोविक ने जर्मनी के जॉन लेनार्ड स्ट्रफ को 6-3, 6-2, 6-2 से हराकर लगातार चौथी बार सीधे सेटों में जीत हासिल की और रोलां गैरां पर लगातार 10वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बने।

पहली बार किसी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद में खराब मौसम के बीच खेलने उतरे स्ट्रफ ने शुरुआती सेट में कुछ अच्छा खेल दिखाया, लेकिन जल्द ही जोकोविक ने मुकाबले में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी और सातवें गेम में दो ब्रेक प्वाइंट हासिल किए, जिसमें एक बैकहैंड पासिंग शॉट भी शामिल था। जोकोविक ने एक घंटे 33 मिनट तक चले इस मुकाबले में महज 11 असहज गलतियां कीं।

निशिकोरी भी जीते : जापान के केई निशिकोरी ने फ्रांस के बेनोइत पियरे को पांच सेट तक चले मैराथन मुकाबले में 6-2, 6-7, 6-2, 6-7, 7-5 से हराकर पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। यह मुकाबला रविवार को कम रोशनी की वजह से रोक दिया गया था, लेकिन सातवीं वरीय निशिकोरी ने सोमवार को पियरे की गलतियों का फायदा उठाकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अब अंतिम-आठ में उनका सामना 11 बार के चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल से होगा, जिन्होंने सोमवार को अपना 33वां जन्मदिन मनाया।

मैच के दौरान शॉट खेलते सर्बिया के नोवाक जोकोविक। एपी

अंतिम-आठ में पहुंची बार्टी और कीज

पेरिस, एएनआइ : ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने अमेरिका की सोफिया केनिन को 6-3, 3-6, 6-0 से हराकर पहली बार फ्रेंच ओपन के महिला सिंगल्स के अंतिम-आठ में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में आठवीं वरीय बार्टी का सामना 14वीं वरीय अमेरिका की मेडिसन कीज से होगा, जिन्होंने एक अन्य मुकाबले में चेक गणराज्य की कैटरीना सिनिएकोवा को सीधे सेटों में 6-2, 6-4 से हराया। कीज दूसरे साल इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। तीन सेट के मुकाबले में बार्टी को दूसरा सेट गंवाना पड़ा, लेकिन निर्णायक सेट में उन्होंने एक तरफा जीत दर्ज की।

बारिश की वजह से खेलना मुश्किल था, लेकिन पेरिस में ऐसा होता है। मुझे अपनी सर्विस पर पूरा भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि यह ऐसे ही आगे भी बरकरार रहेगा।
– नोवाक जोकोविक, सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी

जो मेरे पास था, वो कोहली के पास भी : रिचर्ड्स

लंदन, प्रेट्र : क्रिकेट जगत के सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में शुमार वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स का कहना है कि वह कोहली को पसंद करते हैं क्योंकि खेल और मानसिकता के लिहाज से जो उनके पास था, वह कोहली के पास भी है। रिचर्ड्स के मुताबिक कोहली अपनी बल्लेबाजी शैली और मैदान पर अपने रवैये से उन्हें उनके खेल की याद दिलाते हैं। रिचर्ड्स ने एक भारतीय मीडिया समूह के कार्यक्रम में कहा कि मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं। लोग आक्रामकता की बात करते हैं, लेकिन यह अपने आप में यकीन करना होता है। यह अपने घर की चाबी अपने पास होने जैसा है। विराट में काफी कुछ ऐसा है, जो मुझे अपने खेल की याद दिलाता है। जो उस समय मेरे पास था, वह अज विराट के पास है। रिचर्ड्स ने कहा कि उन्हें भारतीय बल्लेबाज हमेशा से पसंद रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय बल्लेबाजी से हमेशा से प्यार रहा है। विराट को जो आत्मबल हासिल है, वह एक रात में नहीं मिलता। या तो इसे आपमें समाया गया है या फिर आपने इसके साथ ही जन्म लिया है। वह योद्धा हैं और किसी और से अधिक अपनी टीम की रक्षा करते हैं।

गांगुली ने बदली भारतीय क्रिकेट की दिशा और दशा : हुसैन

लंदन, प्रेट्र : इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन की नजर में सौरव गांगुली ऐसे खिलाड़ी और कप्तान रहे हैं, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की दिशा और दशा बदली। हुसैन ने कहा कि उनकी नजर में भारतीय क्रिकेट गांगुली के कारण ही बदला। उन्होंने कहा कि गांगुली जब कप्तान थे, तब भारतीय टीम का पूरा व्यक्तित्व बदल गया था। सौरव को कभी लोगों के साथ दोस्ती करने में गुरेज नहीं रहा। गांगुली ने भारतीय टीम को अच्छी टीम से एक ऐसी टीम के रूप में तब्दील कर दिया, जो सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए खेलती थी। गांगुली की कप्तानी साल 2000 के मैच फिक्सिंग प्रकरण के बाद शुरू हुई थी। उनकी देखरेख में कई सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम 2003 विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली थी।

हुसैन ने यह भी कहा कि मौजूदा भारतीय कप्तान विराट कोहली महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर द्वारा बनाए गए कई रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे। हुसैन ने कहा कि विराट को किसी और चीज की चिंता नहीं रहती। वह सिर्फ और सिर्फ देश के लिए मैच जीतना चाहते हैं। यह कप्तान के तौर पर शानदार गुण है। मैं मानता हूं या फिर मैंने सोचा था कि कोई सचिन की जगह नहीं ले सकेगा, लेकिन विराट सचिन द्वारा बनाए गए सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करने वाले हैं।

विवियन रिचर्ड्स। एपी

कोहली की तरह खेलना चाहते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी : यूनिस

लंदन, प्रेट्र : पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान यूनिस खान ने कहा है कि उनके देश में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय कप्तान विराट कोहली की तरह खेलना चाहते हैं और उनके जैसे फिट रहना पसंद करते हैं। इंग्लैंड में जारी आइसीसी क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान और भारत के बीच 16 जून को मैनचेस्टर में मुकाबला खेला जाएगा। यूनिस ने कहा कि कोहली को पाकिस्तान में बहुत लोग पसंद करते हैं। आज कई पाकिस्तानी खिलाड़ी कोहली जैसे खेलना चाहते हैं और उनके जैसे फिट रहना पसंद करते हैं। कई पाकिस्तानी खिलाड़ी कोहली जैसा व्यक्तित्व रखना चाहते हैं। एशिया कप में जब वह (कोहली) नहीं खेले थे तो स्टेडियम में ज्यादा दर्शक नहीं थे। विराट विश्व कप में टीम इंडिया के बड़े एक्स फैक्टर हैं।

इस बार हमें काफी कुछ साबित करना है : शाकिब

लंदन, एएफपी : दक्षिण अफ्रीका पर बांग्लादेश की शानदार जीत के हीरो रहे ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का कहना है कि इस बार उनकी टीम को काफी कुछ साबित करना है और इसके लिए वह अपना पूरा दमखम लगा देंगे। शाकिब ने कहा कि हमने इससे पहले भी उलटफेर किए हैं। यह हमारी खास जीत है। यह मेरा चौथा विश्व कप है और इस साल हमें एक टीम के तौर पर काफी कुछ साबित करना है। शाकिब ने आगे कहा कि हमारी शुरुआत शानदार रही। हम इसी उम्मीद और तैयारी के साथ यहां आए थे। ड्रेसिंग रूम में उत्साह है और हम इसे जारी रखना चाहते हैं। दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर ने कहा कि वह दो साल तक काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं और उनको इसका फायदा मिला। दक्षिण अफ्रीका पर मिली 21 रन की जीत के बाद अब बांग्लादेश को अगले मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ना है और शाकिब के मुताबिक उनकी टीम के लिए यह मैच काफी अहम होगा क्योंकि किवी टीम ने आइसीसी विश्व कप में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है।

मुर्तजा ने जीत का श्रेय पूरी टीम को दिया

लंदन, एएफपी : अपने पहले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने के बाद बांग्लादेश के कप्तान मशरफे मुर्तजा ने इस जीत का श्रेय पूरी टीम को दिया है। मुर्तजा ने मैच के बाद कहा कि टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने से हम खुश थे। हां, कुछ संदेह था लेकिन हम जानते थे कि इस विकेट पर पहले भी बल्लेबाजी की जा चुकी है, इसलिए बल्लेबाजी कोई बुरा विकल्प नहीं है। मुशफिकुर हमेशा इसी तरह की पारी खेलते हैं। उनके अलावा शाकिब ने अच्छी बल्लेबाजी की। शुरू में सौम्य ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और फिर बाद में महमूदुल्लाह और मुसद्दक ने अच्छी समाप्ति की। विजेता कप्तान ने कहा कि हमें पता था कि हमें सही क्षेत्र में गेंदबाजी करनी होगी और विकेट लेने के लिए गेंदबाजों को बदलते रहना होगा। अच्छी बात यह रही पूरी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया।

रोड्स ने कहा, डिविलियर्स अब दोबारा खेलने नहीं आएंगे

नई दिल्ली, आइएएनएस : लगातार दो हार झेलने के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम अब प्रशंसकों के निशाने पर आई गई है। दक्षिण अफ्रीका को विश्व कप के अपने पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड के हाथों 104 रनों से और दूसरे मैच में बांग्लादेश के हाथों 21 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। प्रशंसकों का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका को पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स और चोटिल तेज गेंदबाज डेल स्टेन की कमी खल रही है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर जोंटी रोड्स ने प्रशंसकों की बातों को खारिज करते हुए कहा कि यह वह समय है जब दक्षिण अफ्रीका को यह समझना चाहिए कि डिविलियर्स अब संन्यास ले चुके हैं और अब वह चयन के लिए उपलब्ध नही होंगे। रविवार की हार के बाद एक प्रशंसक ने ट्विटर पर रोड्स से कहाकि आप की टीम (दक्षिण अफ्रीका) को डिविलियर्स और स्टेन की कमी खल रही है। रोड्स ने इसका जवाब देते हुए कहा कि पूरी टीम दो खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं रह सकती।

फ्रांस की बोलिविया पर जीत में चमके ग्रीजमैन

फुटबॉल डायरी

नांतेस (फ्रांस), एएफपी : मौजूदा विश्व चैंपियन फ्रांस ने रविवार को एक दोस्ताना मुकाबले में बोलिविया को 2-0 से हरा दिया, जहां फ्रांसिस फुटबॉल स्टार एंटोनी ग्रीजमैन ने गोल दागकर इस जीत में अपनी चमक बिखेरी। फ्रांस को यह जीत उसके यूरो कप 2020 के क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करने से ठीक पहले मिली है।

खेल के पांचवें मिनट में थॉमस लेमार ने गोल करके फ्रांस को शुरुआती बढ़त दिलाई और फिर हाल ही में स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड को छोड़ने की घोषणा करने वाले ग्रीजमैन ने हाफ टाइम से दो मिनट पहले गोल करके फ्रांस को दोहरी बढ़त दिलाई। इस गोल के साथ ग्रीजमैन फ्रांस के लिए सर्वकालिक सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में आठवें स्थान पर पहुंच गए। अपना 29वां अंतरराष्ट्रीय गोल दागने के साथ ही ग्रीजमैन ने 1998 विश्व कप विजेता फ्रांस की टीम के सदस्य रहे यॉरी जोरकैफ को पछाड़ा दिया। अब वह फ्रांस के दिग्गज जस्ट फोंटेन और जीन पियरे पापिन से एक, जबकि जिनेदिन जिदान से दो गोल पीछे हैं। बोलिविया के खिलाफ मुकाबले के दौरान फ्रांस के युवा स्टार कायलियन एमबापे टखने की चोट की वजह से हाफ टाइम के बाद खेलने नहीं उतर सके। यूरो कप क्वालीफाइंग टूर्नामेंट में अब कोच दिदिएर डेसचैंप्स की फ्रांसिसी टीम आठ जून को ग्रुप-एच में तुर्की के खिलाफ मैदान में उतरेगी।

क्लोप को बायर्न में देखना चाहता हूं : बेकनबॉयर

बर्लिन, एएफपी : जर्मनी के महान फुटबॉलर फ्रांज बेकनबॉयर ने सोमवार को कहा कि वह लिवरपूल के मैनेजर जुर्जेन क्लोप को जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख के डगआउट में देखना चाहते हैं। चैंपियंस लीग में लिवरपूल की सफलता को देखते हुए बेकनबॉयर ने कहा कि मैं एक दिन क्लोप को बायर्न में देखना चाहता हूं, यह एक अच्छा समन्वय होगा। 73 वर्षीय बेकनबॉयर बायर्न म्यूनिख के साथ बतौर खिलाड़ी और मैनेजर पांच बुंडिशलीगा खिताब जीत चुके हैं।

सीख का खिलाड़ी करेंगे इस्तेमाल : स्टिमक

बुरिरैम (थाइलैंड), प्रेट्र : भारतीय फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टिमक ने सोमवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अभ्यास में मिली सीख को उपयोग उनकी टीम के खिलाड़ी किंग्स कप में करेंगे। किंग्स कप में भाग लेने के लिए भारतीय टीम थाइलैंड पहुंच चुकी है, जहां उसका पहला मुकाबला पांच जून को कुराकाओ से होगा। स्टिमक ने कहा कि लड़के विश्वास से भरे हुए हैं और उन्हें पता है कि कड़ी मेहनत से वे अपने खेल के स्तर को सुधार सकते हैं।

यूरोप में इंग्लिश क्लबों का दबदबा इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा नहीं

लंदन, एएफपी : यूएफा यूरोपीयन चैंपियनशिप में इंग्लिश फुटबॉल क्लबों का दबदबा देखने को मिला। ऐसे में अब इंग्लिश खिलाड़ियों पर इस सप्ताह होने वाले पहले नेशंस लीग में खिताब जीतने की संभावनाओं को बल मिलेगा, लेकिन इंग्लैंड के कोच गेरेथ साउथगेट के सामने कुछ मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। चैंपियंस लीग का फाइनल खेलने वाली लिवरपूल और टॉटनहम टीमों के कुल सात खिलाड़ी साउथगेट की 23 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम में शामिल हैं। साउथगेट पर इनमें से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की चुनने की चुनौती होगी। उधर इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन पर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है जो अभी भी पूरी तरह से फिट नजर नहीं आ रहे हैं।

भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देंगे तीन स्पेनिश क्लब

जेएनएन, नई दिल्ली : फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए ला लीगा फुटबॉल स्कूलों के साथ सेविया, रीयल बेटिस और सेल्टा विगो के रूप में तीन स्पेनिश क्लब अपनी भागीदारी पेश करेंगे। फुटबॉल स्कूल के तहत पुणे (टर्फ अप), बेंगलुरु (टिएंटो) और नोएडा (पाथवे स्कूल) के परियोजनाओं को इन क्लबों द्वारा अपनाया जाएगा।

विविध

चंद्रमा पर दोबारा महकने को तैयार अमरोहा की 'खुशबू'

आसिफ अली, अमरोहा

जी हां, अमरोहा, उत्तर प्रदेश की 'खुशबू' एक बार फिर चांद पर महकेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) चांद पर दूसरा अभियान 9-16 जुलाई को लॉन्च करने जा रहा है। चंद्रयान-2 का लैंडर चांद की सतह पर छह सितंबर को उतर सकता है। अमरोहा के मुहल्ला चाहगौरी निवासी सिकंदर मिर्जा की बिटिया खुशबू मिर्जा मिशन की रिसर्च टीम का हिस्सा हैं। चंद्रयान-1 की चेकआउट टीम की लीडर रह चुकीं खुशबू दुनियाभर की महिलाओं, खासकर मुस्लिम समाज के लिए प्रेरणास्रोत बन गई हैं।

चंद्रयान-1 और मंगलयान मिशन के बाद चंद्रयान-2 इसरो के लिए अति महत्वाकांक्षी मिशन है। अभी तक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग (मानवरहित) कराने वाले देश अमेरिका, रूस और चीन ही हैं। चंद्रयान-2 आर्बिटर और लैंडर को जीएसएलवी मार्क-3 धरती की कक्षा में स्थापित करेगा। जिसके बाद उसे चांद की कक्षा में पहुंचाया जाएगा। चांद की कक्षा में चंद्रयान-2 के पहुंचने के बाद लैंडर निकलकर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके बाद रोवर उससे निकलेगा और विभिन्न प्रयोगों को अंजाम देगा। भारत ने साल 2008 में चांद पर अपना पहला मिशन चंद्रयान-1 लॉन्च किया था। लेकिन ईंधन की कमी के कारण यह मिशन 29 अगस्त 2009 को ही खत्म हो गया था।

चंद्रयान-1 मिशन की चेकआउट टीम में खुशबू सबसे कम उम्र की सदस्य थीं। इस बार वह रिसर्च टीम का हिस्सा हैं और मिशन की तैयारियों में जुटी हैं। कहती हैं, चंद्रयान-2 भारत के लिए बेहद महत्वाकांक्षी और प्रतिष्ठा से जुड़ा मिशन है। इससे जुड़े सभी सदस्यों ने भरपूर मेहनत की है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे।

इधर, खुशबू के भाई चौधरी खुशतर मिर्जा ने बताया कि इस कामयाबी का सभी को बेसब्री से इंतजार है। उस अवसर को लेकर पूरे परिवार में एक अलग उत्साह है। हम सभी इस मिशन की कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। खुशबू भी मिशन को सार्थक बनाने में जीजान से जुटी हैं। खुशतर ने दैनिक जागरण से कहा, खुशबू देश के लिए काम कर रही हैं और हम सभी को इस पर नाज है।

खुशबू के परिवार में उनकी मां फरहत मिर्जा के अलावा बड़े भाई चौधरी खुशतर मिर्जा और बहन महक हैं। 1985 में जन्मीं खुशबू के सिर से पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। मां ने ही तीनों बच्चों की परवरिश की और बेहतर तालीम दिलाई। खुशबू ने नगर के कृष्णा बाल मंदिर स्कूल से इंटर तक की पढ़ाई की। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। वह अपने बैच की गोल्ड मेडलिस्ट रहीं। स्कूल के दिनों में जिला स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी रहीं खुशबू विश्वविद्यालय की पहली छात्रा भी रहीं जिन्होंने छात्र संघ के चुनावों में हिस्सा लिया।

जश्न की तैयारी में अमरोहा... : अपनी बिटिया की उपलब्धि से परिजनों को ही नहीं बल्कि पूरे अमरोहा को उन पर नाज है। चंद्रयान-1 की सफलता के दौरान भी अमरोहा ने न सिर्फ जश्न मनाया था बल्कि अपनी बेटी को सिर-आंखों पर बैठाया था। अब दस साल बाद फिर से जश्न मनाने की तैयारी है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

जागरण विशेष

- चंद्रयान-2 की रिसर्च टीम का हिस्सा हैं अमरोहा निवासी खुशबू मिर्जा
- चंद्रयान-1 की चेकआउट टीम की लीडर भी रह चुकी हैं खुशबू, मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए बनीं प्रेरणास्रोत

अमरोहा की खुशबू मिर्जा। जागरण

चंद्रयान-1 के साथ खुशबू मिर्जा। जागरण

बेटियों को पढ़ाएं...

अब समय बदल चुका है। भारत की बेटियां अंतरिक्ष विज्ञान सहित अन्य विधाओं में दक्षता हासिल कर रही हैं। इसलिए मुस्लिम समाज का भी लड़कियों के प्रति भी नजरिया बदलना चाहिए। परिजनों को बच्चियों को बेहतर तालीम दिलानी चाहिए। **–खुशबू मिर्जा, सदस्य चंद्रयान-2, इसरो**

कामयाबी के लिए दुआ...

खुशबू देश के लिए काम कर रही हैं और हम सभी को इस पर नाज है। हम सभी इस मिशन की कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। **–चौधरी खुशतर मिर्जा, बड़े भाई**

हमें अपनी बिटिया पर नाज है...

स्लाम ने सबको तालीम का बराबर हक दिया है। बेटे के बराबर बेटी को रखा गया है। खुशबू ने सिर्फ अमरोहा का ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है। हमें अपने शहर की बेटी पर नाज है। **- नसीम खां, समाजसेवी, अमरोहा।**

चंद्रयान-1 के वक्त रखे थे रोजे

मेरे शहर की बेटी ने तालीम भी हासिल की और अब मुल्क के लिए अपना फर्ज पूरा कर रही है। खुशबू ने चंद्रयान-1 की लॉचिंग के वक्त रोजे भी रखे थे तथा ईद भी वहीं मनाई थी। उनकी कामयाबी से समाज में सकारात्मक संदेश गया है। **– हाजी नासिर सिद्दीकी, अमरोहा निवासी।**

खुशबू ने तोड़ा मिथक

खुशबू ने मिथक तोड़ कर साबित किया है कि तालीम मिलने पर वह हर क्षेत्र में देश सेवा कर सकती हैं। **– इफ्तेखार सैफी, अमरोहा निवासी।**

सभी के लिए प्रेरणास्रोत...

: खुशबू मिर्जा सबके लिए प्रेरणास्रोत बनी हैं। उनकी कामयाबी ने मुस्लिम बेटियों को आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाया है। **– अली मकीन नकवी, अमरोहा निवासी।**

पर्यावरणीय चुनौती को मात दे रही 'सुपर वूमन'

विश्व पर्यावरण दिवस कल ▶ कूड़े और वायु प्रदूषण से निबटने को विकसित कर रहीं बेहतर उपाय

मनु त्यागी, नई दिल्ली

देशभर की 40 लैंडफिल साइट्स पर कूड़े के पहाड़ों को समतल करके रागिनी जैन पर्यावरण प्रहरियों के बीच 'सुपर वूमन' बन चुकी हैं। उन्नत तकनीकी और अटूट जज्बे के बूते वह पर्यावरणीय चुनौतियों का कारगर समाधान प्रस्तुत कर रही हैं।

आग लगी तो लगी, पानी के बगैर बुझती देखी है कभी? वो भी कूड़े के पहाड़ों में? यदि एक बार आग लग जाए तो दिन, सप्ताह, महीनों तक सुलगती रहती है। ऐसे ही कूड़े के पहाड़ और पर्यावरणीय चुनौतियों को नई तकनीकी के माध्यम से मात दे रही हैं 59 वर्षीय रागिनी जैन। रागिनी की फर्म गीतांजलि इनवायरोटेक ने ऐसी उन्नत तकनीकों के विकास पर ध्यान दिया है, जो पर्यावरण संरक्षण में कारगर साबित हो रही हैं। लैंडफिल साइट्स पर लगने वाली आग को जीई माइक्रोब के जरिए (बिना पानी) बुझाना इसमें से एक है। सिर्फ आग ही नहीं आसमान छूती कूड़े के पहाड़ों की ऊंचाई को तकनीक के जरिए कुछ ही दिनों में एकदम धरातल पर ला रही हैं।

पर्यावरण संरक्षण

मूलरूप से मुंबई निवासी रागिनी जैन की इस फर्म का गुरुग्राम में भी ऑफिस है। कहती हैं, दिल्ली में गाजीपुर, भलस्वा और गुरुग्राम की बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर काफी काम किया है। अमूमन आपने देखा होगा कूड़े के ढेर पर मीथेन गैस के कारण आगजनी की घटनाएं बहुत होती हैं और उसका धुआं पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। दिल्ली-एनसीआर में पहले ही बहुत अधिक प्रदूषण है, ऐसे में इस तरह की आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए मैंने यह तकनीक तैयार की। इसके जरिए मीथेन गैस को पूरी तरह कंज्यूम (खपा) कर लिया जाता है जिससे आग रुक जाती है। यह तकनीक बिलकुल आर्गेनिक है।

अक्टूबर 2016 की बात है गुरुग्राम के बंधवाड़ी में 100 फीट का कूड़े का पहाड़ हुआ करता था, जिसे रागिनी की माइक्रोब तकनीक से दस दिन में 23 फीट पर ला दिया गया था। अब तो यह खत्म ही हो चुका है। रागिनी कहती हैं, आज कूड़े के पहाड़ों को कैपिंग के जरिए खत्म करने पर चर्चा की जा रही है जो कि पर्यावरण के लिए तो बेहद हानिकारक है ही इससे हमारी उतनी जमीन भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। मैंने सुप्रीम कोर्ट को एक प्रोजेक्ट भेजा था, जिसमें दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट को खत्म करने की कारगर योजना बताई थी। इस प्रोजेक्ट पर अभी विचार किया जा रहा है। हालांकि इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बायो माइनिंग को बढ़ावा देनी की बात जरूर असरदार तरीके से होने लगी है। लेकिन उसका इस्तेमाल कम ही किया जा रहा है।

नमामि गंगे स्वच्छ भारत मिशन से भी जुड़ीं रागिनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जनक अलमित्रा पटेल से प्रेरणा लेकर इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। कहती हैं, हम पर्यावरण की चिंता तो बहुत करते हैं लेकिन उसके कारणों पर पर्दा डाले रहते हैं। कूड़े के पहाड़ों की बढ़ती ऊंचाई को कम न कर पाने के पीछे वजह हमारे सिस्टम की कमी भी है। नगर निगम का पूरा सिस्टम कारगर नहीं है। कुछ लोग कभी नहीं चाहते कि यह ढेर खत्म हों, क्योंकि इससे इनके कुछ हित भी जुड़े होते हैं।

इसी तरह दूसरी चुनौती हमारे वैज्ञानिक हैं जो लैब में बैठकर पॉलिसी तो तैयार करते हैं लेकिन वह जमीनी स्तर पर सफल होगी या नहीं इस पर कभी गौर नहीं करते। इनकी ऐसी सैकड़ों पॉलिसीज उदाहरण हैं, जो असफल हुईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के प्रति आग्रह ने मुझ जैसे लोगों को प्रेरित किया है। उम्मीद है, कुछ बेहतर होगा।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

रागिनी जैन। जागरण

लैंडफिल साइट पर अपने काम को अंजाम देती रागिनी जैन। जागरण

मोर्चे पर खुद उतरती हैं...

रागिनी जैन भले ही 59 साल की हो चुकी हैं, लेकिन इस काम को लेकर उनका जज्बा वैसा ही है, जैसा कि बीस साल पहले भी हुआ करता था। आज भी वे लैंडफिल साइट्स पर कूड़े के पहाड़ के सफाए में जुटी देखी जा सकती हैं। अपनी टीम का नेतृत्व वह स्वयं करती हैं। जेसीबी सहित हर तरह की बड़ी भारीभरकम मशीनें वह खुद भी चलाती हैं।

पंजाब में कैदी चलाएंगे पेट्रोल पंप करेंगे कानून की पढ़ाई : जेल मंत्री

जागरण संवाददाता, पटियाला

पंजाब की जेलों में बंद कैदियों को उनके अपराध की सजा मिल जाती है, लेकिन अपनी गलती सुधार कर आम नागरिक बनाने के लिए बेहतर अवसर नहीं मिलते। इसके लिए अब पंजाब की जेलों में बंद कैदियों को पेट्रोल पंपों पर काम करने का मौका दिया जाएगा।

जेल परिसर के बाहर मॉडर्न पेट्रोल पंप खोले जाएंगे, जिसके लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। यह बातें पंजाब ट्रेनिंग स्कूल की पास आउट परेड में पहुंचे जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहीं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तर्ज पर इस प्रोजेक्ट को लागू किया जा रहा है और इन पेट्रोल पंपों पर कैदी ही काम करेंगे।

रंधावा ने कहा कि इन पेट्रोल पंपों पर आउटलेट बनाकर जेल में तैयार होने वाले अलग अलग उत्पादों की बिक्री भी की जाएगी। आउटलेट में वेरका और मार्कफैड के 'ईटिंग हब' बनाने की भी योजना है। पटियाला सेंट्रल जेल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू किया जा चुका है।

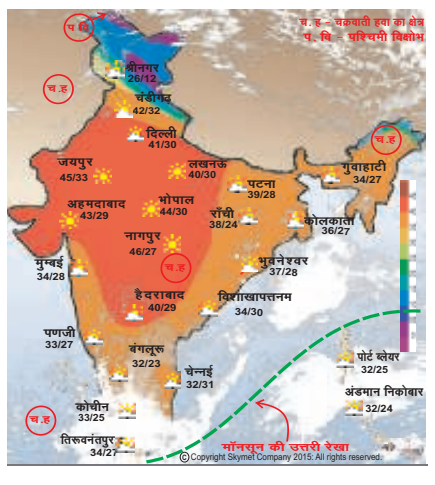

मौसम विशेष

राजस्थान में मध्यम गति गर्म हवाओं के साथ प्रचंड लू का प्रकोप जारी रहेगा। हरियाणा, पंजाब व दिल्ली में भी भीषण गर्मी जारी रहेगी। इन राज्यों के कुछ स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ आंधी संभव है। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा होगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	35/27/व	अहमदाबाद	42/24/आंबा
कोलकाता	37/28/सा	बड़ोदा	41/25/आंबा
चेन्नई	39/27/आंबा	नागपुर	46/28/व
हैदराबाद	41/28/सा	इन्दौर	43/27/व
बंगलूरू	33/22/सा	रांची	37/25/व
त्रिवेन्द्रम	33/28/व	पटना	42/31/आंबा
गुवाहाटी	36/27/सा	जमशेदपुर	36/26/आंबा
गंगटोक	17/08/आंबा	पुणे	32/24/आंबा

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 4 जून 2019
आजकल
14
www.jagran.com

गर्म हवा के गुब्बारे को पहली बार सफलतापूर्वक उड़ाया

1783 में आज ही फ्रेंच आविष्कार मांटगॉल्फियर बंधुओं ने पहली बार सफलतापूर्वक हॉट एयर बैलून उड़ाया था। इन्हीं बंधुओं के नाम पर हॉट एयर बलून को मॉन्टगॉल्फियर बैलून कहा जाता है। इसमें बर्नर की मदद से बैलून में गरम हवा डाली जाती है।

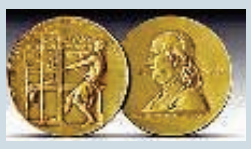

पहली बार पुलित्जर पुरस्कार दिया गया

1917 में आज ही पत्रकारिता, लेखन के क्षेत्र में चार लोगों को पहली बार पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने इस पुरस्कार की स्थापना के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय को 20 लाख डॉलर की धन राशि दी थी।

सौम्य और सशक्त अभिनय की मल्लिका थीं नूतन

बीते जमाने की मशहूर अदाकारा नूतन का जन्म 1936 में आज ही मुंबई में हुआ था। हिंदी सिनेमा पर चालीस साल राज करने वाली नूतन ने 70 से अधिक फिल्मों में काम किया। नौ साल की उम्र में फिल्म 'नल दमयंती' में बतौर बाल कलाकार करियर की शुरूआत की। बंदिनी, कन्हैया, छलिया, अनाड़ी, पेइंग गेस्ट, मैं तुलसी तेरे आंगन की, बारिश, मंजिल, तेरे घर के सामने, कर्मा और सौदागर उनकी कुछ प्रमुख फिल्में रहीं। 1952 में मिस इंडिया बनीं। पांच बार फिल्मफेयर मिला। 1974 में पद्मश्री मिला। 21 फरवरी, 1991 को दुनिया को अलविदा कहा।

इधर उधर की

80 साल बाद हाई स्कूल पास हुए भाई-बहन

वाशिंगटन,एजेंसी : कहते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती। अमेरिका के रहने वाले 95 वर्षीय जॉर्ज रेमिरेज और 94 वर्षीय उनकी बहन एनिटा रेमिरेज ने एक साथ हाई स्कूल की डिग्री हासिल की है। इन दोनों बुजुर्गों ने करीब 80 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जॉर्ज रेमिरेज ने अपने पिता के कहने पर पढ़ाई छोड़कर आर्मी ज्वाइन कर ली थी। इस दौरान कई देशों की यात्रा करने के कारण वो पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। वहीं जॉर्ज की बहन एनिटा रेमिरेज ने 15 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बाद उन्होंने घर संभालना शुरू कर दिया। बाद में उनकी शादी हो गई। अब करीब आठ दशकों के बाद दोनों ने फिर से हाईस्कूल किया है।

अचरज भरा आकाश ▶ सुपरनोवा से लगाया जा सकता है ब्रह्मांड के विस्तार का पता

वैज्ञानिकों ने खोजे 1800 नए सुपरनोवा

किसी तारे के भयंकर विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं

- पृथ्वी से 800 करोड़ प्रकाशवर्ष दूर है 58 टाइप ला सुपरनोवा
- इनका प्रकाश और विकिरण इतना जबरदस्त होता है कि आकाशगंगा भी धुंधली हो जाती है

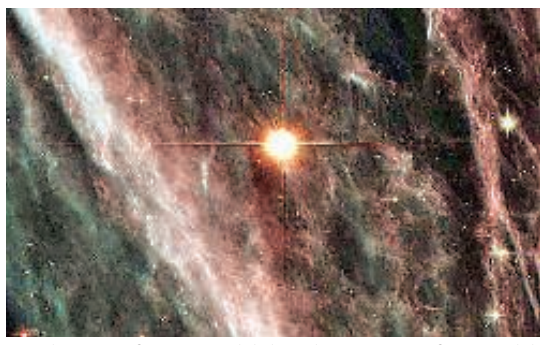

सुपरनोवा ब्रह्मांण की दुर्लभ घटनाओं में से एक है। प्रतीकात्मक फोटो

टोक्यो, प्रेट्र : हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल और गतिशील है कि उसमें निरंतर कुछ न कुछ घटित होता रहता है। वैज्ञानिक दिन प्रतिदिन इसके बारे में नई जानकारियां जुटाते रहते हैं। अब उन्होंने 1800 नए सुपरनोवा खोजे हैं। खगोलशास्त्र में सुपरनोवा या महानोवा किसी तारे के भयंकर विस्फोट को कहते हैं। धमाके के बाद सुपरनोवा से निकलने वाला प्रकाश और विकिरण इतना जबरदस्त होता है कि कुछ समय के लिए यह पूरी आकाशगंगा को भी धुंधला कर देता है। इनकी मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि ब्रह्मांड किस गति से विस्तार कर रहा है।

जापान की कवली इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिक्स एंड मैथमैटिक्स ऑफ द यूनिवर्स (कवली आइपीएमयू) और टोक्यो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली डिजिटल कैमरों और टेलीस्कोप के डाटा से इनकी खोज की है।

इस खोज में 58 टाइप ला सुपरनोवा (जिसमें दो तारे बिल्कुल बगल में होते हैं और एक तारा व्हाइट ड्वार्फ होता है) भी सामने आए हैं जो पृथ्वी से करीब 800 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं। सूपरनोवा का टाइप ला वर्ग बहुत उपयोग में आता है, क्योंकि उनकी निरंतर चमक शोधकर्ताओं को यह गणना करने में मदद करती है तारा पृथ्वी से कितनी दूर है। यह उन शोधकर्ताओं के लिए विशेषकर उपयोगी है जो ब्रह्मांड के विस्तार को मापना चाहते हैं।

सुपरनोवा अपनी आकाशगंगा के सामान ही चमकदार हो जाते हैं और छह माह तक इसकी चमक सूर्य से एक अरब गुना तक ज्यादा तेज होती है। इसके बाद यह धीमा पड़ने लगता है। हालांकि, सुपरनोवा दुर्लभ घटनाएं हैं और दुनिया में केवल कुछ टेलीस्कोप ही हैं जो दूर के हाल ही के वर्षों में शोधकर्ताओं ने एक नए तरह के सुपरनोवा की खोज की है जो टाइप ला सुपरनोवा से पांच से दस गुना तेज चमकता है। इसका नाम सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा रखा गया है। कई शोधकर्ता इन सितारों के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन तारों की असामान्य चमक शोधकर्ताओं को ब्रह्मांड के सबसे दूर के हिस्सों में तारों को देखने में सक्षम बनाती है जो कि आमतौर पर बहुत धुंधले होते हैं।

दुनिया के सबसे शक्तिशाली डिजिटल कैमरों की ली मदद

टोक्यो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली डिजिटल कैमरों और टेलीस्कोप के डाटा से इनकी खोज की है। इन घटनाओं की तस्वीरें खींचने के लिए सुबारू टेलीस्कोप और 870 मेगापिक्सल का डिजिटल कैमरा हाइपर सुपरटाइम-कैम का उपयोग किया। सुपरनोवा की तस्वीरों के लिए ये कैमरे सबसे अच्छे माने जाते हैं। सितारों की तस्वीरें खींच सकती हैं। शोधकर्ताओं ने इन घटनाओं की तस्वीरें खींचने के लिए सुबारू टेलीस्कोप और 870 मेगापिक्सल का डिजिटल कैमरा हाइपर सुपरटाइम-कैम का उपयोग किया। यह डिजिटल कैमरा रात के समय एक शॉट में बहुत व्यापक क्षेत्र को कैप्चर करता है। इनके द्वारा छह महीने तक ली गई तस्वीरों के माध्यम से वैज्ञानिकों ने सुपरनोवा के बारे में पता लगाया। वैज्ञानिकों ने पांच सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा और 400 टाइप ला सुपरनोवा की खोज की। इसमें से 58 टाइप ला सुपरनोवा पृथ्वी से 800 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर हैं।

स्तन कैंसर पीड़ित की उम्र बढ़ा सकती है नई दवा

न्यूयॉर्क टाइम्स से

- इस दवा से बढ़ा एडवांस्ड स्टेज के मरीजों का सर्वाइवल रेट

वाशिंगटन : स्तन कैंसर के इलाज की दिशा में उम्मीद की नई किरण दिखी है। एंडवास्ड स्टेज के स्तन कैंसर के प्रसार को धीमा करने में कारगर एक दवा को सर्वाइवल रेट बढ़ाने में भी मददगार पाया गया है। कैंसर के एडवांस्ड स्टेज में पहुंचने और इलाज के बाद मरीज के जीवित रहने की संभावना को सर्वाइवल रेट कहते हैं। आमतौर पर जो दवा कैंसर के प्रसार को रोकती है, जरूरी नहीं है कि उससे सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाए। कई बार कैंसर दोबारा उभर जाता है और फिर उस पर कोई इलाज काम नहीं करता है। इसे ही एडवांस्ड स्टेज का कैंसर कहा जाता है।

अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 2017 में दवा राइबोसाइक्लिब को मीनोपॉज की उम्र के बाद की महिलाओं पर प्रयोग के लिए मंजूरी दी थी। 2018 में इसे युवा महिलाओं के लिए भी मंजूर कर लिया गया था। इस दवा के प्रयोग से जुड़े डॉक्टरों ने बताया कि पारंपरिक इलाज के साथ इस दवा का प्रयोग करने पर 70 फीसद महिलाएं साढ़े तीन साल से ज्यादा समय तक जीवित रहीं। वहीं मात्र पारंपरिक इलाज लेने वाली 46 फीसद महिलाएं ही इतने समय तक जीवित रह पाती हैं। अध्ययन में 18 से 59 साल की 672 महिलाओं को शामिल किया गया था। इनमें 72 फीसद की उम्र 40 साल या इससे ज्यादा थी। इन सभी को एडवांस्ड स्टेज का कैंसर था। इसका अर्थ है कि कैंसर इलाज के बाद दोबारा उभर आया था या शरीर के अन्य हिस्सों तक इसका प्रसार शुरू हो गया था और इसे लाइलाज मान लिया गया था।

क्या है इलाज का तरीका ? : एस्ट्रोजन हार्मोन को कई महिलाओं में कैंसर कोशिकाओं के प्रसार में सहायक पाया जाता है। इसीलिए इलाज के पारंपरिक तरीके में ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन को बाधित कर देती हैं। वहीं राइबोसाइक्लिब दवा टार्गेटेड थेरेपी की तरह है। यह कैंसर के प्रसार में सहायक बनने वाले एक एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। दवा बनाने वाली कंपनी नोवार्टिस के मुताबिक, इस दवा की एक महीने की खुराक करीब 12,553 डॉलर (करीब 8.68 लाख) रुपये की पड़ेगी।

बढ़ गई हैं उम्मीदें : ह्यूस्टन के एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर के ब्रेस्ट मेडिकल ऑकोलॉजी चेयरमैन व प्रमुख अध्ययनकर्ता डॉ. देबू त्रिपाठी ने कहा, 'नतीजों से उम्मीद की नई किरण दिखी है। हमने सर्वाइवल रेट की एक सीमा को पार कर लिया है। अब उम्मीद है कि हम और आगे जाएंगे। एक सीमा पार करने के साथ हम यह भी सीखते हैं कि सीमाएं कैसे तोड़ी जा सकती हैं।'

तेजी से बढ़ रहा स्तन कैंसर का खतरा : स्तन कैंसर दुनियाभर में तेजी से बढ़ रहा है। अकेले अमेरिका में इस साल स्तन कैंसर के 2,68,600 नए मामले आने और 41,760 की जान जाने का अनुमान है। वैश्विक स्तर पर स्तन कैंसर के सालाना 21 लाख नए मामले सामने आते हैं। पिछले साल इससे 6,27,000 की मौत हो गई थी।

शोध अनुसंधान

दिल के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है कॉफी

अगर आप भी कॉफी के शौकीन हैं, तो खुश हो जाइए। एक ताजा शोध के मुताबिक, कॉफी पीना दिल के लिए उतना घातक नहीं है, जितना अब तक माना जाता था। पहले के अध्ययनों में बताया गया था कि ज्यादा कॉफी पीने से धमनियां सख्त हो जाती हैं। ऑक्सीजन व अन्य पोषक तत्वों के साथ खून को दिल से शरीर के बाकी हिस्से तक पहुंचाना धमनियों का काम होता है। धमनियों के सख्त होने से दिल पर दबाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में दिल का दौरा पड़ने या स्ट्रोक का खतरा रहता है। ब्रिटेन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के शोधकर्ताओं ने 8,000 से ज्यादा लोगों पर शोध के बाद पाया कि कॉफी से धमनियां सख्त नहीं होती हैं। अध्ययन के मुताबिक, रोजाना 25 कप तक कॉफी पीने वालों की धमनियों में भी कोई अतिरिक्त सख्ती नहीं पाई गई। शोधकर्ता केनेथ फंग ने कहा, 'धमनियों के लिए कॉफी उतनी बुरी नहीं है, जितना कहा जाता है।' - प्रेट्र

बाइपास सर्जरी में घातक है ज्यादा बॉडी फैट मास

ज्यादा बॉडी फैट मास वालों के लिए दिल की बाइपास सर्जरी घातक हो सकती है। नए शोध के मुताबिक, ऐसे लोगों में सर्जरी के बाद मौत का खतरा चार गुना हो जाता है। बॉडी फैट मास का आकलन शरीर में वसा के अनुपात के आधार किया जाता है। शारीरिक तौर पर मोटा नहीं होने पर भी व्यक्ति का बॉडी फैट मास ज्यादा हो सकता है। शोध के दौरान ऐसे 3,373 लोगों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, जिन्होंने जनवरी, 2013 से दिसंबर, 2016 के बीच बाइपास सर्जरी कराई थी। इसमें पाया गया कि ज्यादा बॉडी फैट मास वाले मरीजों में सर्जरी के 30 दिन के अंदर मौत का खतरा कम बॉडी फैट मास वालों की तुलना में 4.1 गुना हो जाता है। इसी तरह ज्यादा मोटे लोगों को और ज्यादा बॉडी फैट मास वालों को आइसीयू में भी ज्यादा वक्त बिताना पड़ता है। - एएनआइ

याददाश्त लौटाने में मददगार है ब्रेन जैपिंग

- कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस जर्नल में प्रकाशित शोध में वैज्ञानिकों ने किया दावा
- स्मृति सहेजता है मस्तिष्क का लेफ्ट रोस्ट्रोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स

लॉस एंजिलस, प्रेट्र : मस्तिष्क के एक विशेष हिस्से को करंट देकर मनुष्य की याददाश्त वापस लाई जा सकती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि वह पहली बार ऐसा करने में सफल हुए हैं। इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन के जरिये किसी व्यक्ति की याददाश्त वापस लाई जा सकती है। भूली-बिसरी यादों को वापस लाने की इस विधि को ब्रेन जैपिंग कहा जाता है। इसे ब्रेन शॉक, हेड शॉक और इलेक्ट्रिकल शॉक भी कहते हैं।

कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस जर्नल में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि मस्तिष्क का लेफ्ट रोस्ट्रोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स याददाश्त वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेरिका में लॉस एंजिलस स्थित कैलीफोर्निया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी रिसमैन ने कहा कि जब मस्तिष्क के इस हिस्से में बिजली के झटके देकर इसकी क्षमता बढ़ाई, तो हमने देखा कि नाटकीय रूप से यादें लौट आईं। उन्होंने कहा कि लेफ्ट (बांया) रोस्ट्रोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स विचारों को संजोने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके जरिये ही मस्तिष्क के अन्य क्षेत्रों की जानकारी और निगरानी की जाती है। यह क्षेत्र कपाल के बायीं ओर, भौं और बालों के बीच होता है। रिसमैन ने कहा कि हमें लगता है कि यह मस्तिष्क हिस्सा विशेष रूप से जानकारियों को मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही भूतकाल की बातों का स्टोर रूम-सा लगता है और निर्णय लेने की शक्ति देता है।

इस अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिकों ने उन तीन समूहों के साथ प्रयोग किए जिनकी औसत आयु 20 थी। प्रत्येक समूह में 13 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल थे। प्रतिभागियों को कंप्यूटर स्क्रीन में 80 शब्दों की एक श्रृंखला दिखाई गई और उन्हें निर्देश दिया गया कि वे एक-दूसरे से बातचीत कर हर शब्द की कल्पना करें। अगले दिन जब प्रतिभागी प्रयोगशाला में आए तो उनके तीन टेस्ट (स्मृति, तर्क क्षमता, और दृष्य बोध यानी विजुअल्स को समझना) किए गए।

प्रत्येक प्रतिभागी ने एक उपकरण पहना था जो मस्तिष्क पर एक इलेक्ट्रोड के माध्यम से हल्का करंट भेजता था, इससे उनके मस्तिष्क के बाएं रोस्ट्रोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स की उत्तेजना को कम या ज्यादा किया जा सकता है। रिसमैन ने कहा कि उत्तेजना बढ़ाने पर न्यूरॉन्स का बहाव और तेज हो जाता है।

घंटे भर के अध्ययन सभी प्रतिभागियों की स्थिति समान रही। जिसके बाद शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि करंट देने के बाद सभी प्रतिभागियों का स्तर समान कैसे रहा। अगले 30 मिनट बाद, प्रतिभागियों के एक समूह को जब इलेक्ट्रिक करेंट दिया गया तो उनके न्यूरॉन्स की बहाव में तेजी आई और दूसरे समूह को करंट दिया तो उनमें न्यूरॉन गतिविधि को दब गई तीसरे समूह को केवल झटके महसूस हुए। इन आंकड़ों का विश्लेषण कर वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि याददाश्त वापस लाई जा सकती है। रिसमैन ने कहा कि अध्ययन बताता है कि याददाश्त लौटाने के लिए लेफ्ट रोस्ट्रोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन के जरिये किसी व्यक्ति की याददाश्त वापस लाई जा सकती है।

दोपहर की नींद से बढ़ सकता है बच्चों का आइक्यू

वाशिंगटन, प्रेट्र : दोपहर के वक्त कुछ देर की नींद ले लेने से बच्चे ना सिर्फ तरोताजा महसूस करते हैं, बल्कि इससे उनके व्यवहार में भी सुधार होता है। दोपहर की नींद से बच्चों का आइक्यू बढ़ता है और पढ़ाई में उनका प्रदर्शन सुधरता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरविन के शोधकर्ताओं ने यह बात कही है।

अध्ययन में चौथी, पांचवीं और छठी कक्षा के करीब 3,000 बच्चों को शामिल किया गया था, जिनकी उम्र 10 से 12 साल थी। इसमें पाया गया कि दोपहर में कुछ देर सो लेने से बच्चे ज्यादा खुश रहते हैं और स्वयं पर उनका नियंत्रण बेहतर होता है। हफ्ते में तीन दिन या इससे ज्यादा दोहपर में नींद लेने वाले बच्चों के प्रदर्शन में 7.6 फीसद तक का निखार देखा गया। इससे बच्चों में थकान की समस्या भी कम होती है।

गर्मी में अक्सर देखा जाता है कि दोपहर में खाना खाने के बाद नींद आने लगती है। कई लोग दिन में सोना ठीक नहीं मानते लेकिन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों के दावे इसके ठीक उलट हैं।

'ग्लोइंग' प्रोटीन से मिलेगी कैंसर के अध्ययन में मदद

मॉस्को, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने एक नया 'ग्लोइंग' (चमकदार) प्रोटीन बनाया है, जिससे कैंसर, संक्रामक रोगों और अंगों के विकास के अध्ययन में मदद मिल सकती है। रूस में मास्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी (एमआईपीटी) के शोधकर्ताओं ने कहा कि जब पराबैंगनी और नीली रोशनी से विकिरण होता है, तो उच्च तापमान पर यह प्रोटीन बहुत छोटा और स्थिर हो जाता है। फ्लूअरेसंस माइक्रोस्कोपी जीवित ऊतक का अध्ययन करने के लिए एक विधि है जो प्रकाश पर आधारित होती है।

एक विशेष वेवलेंथ (तरंग दैर्ध्य) में लेजर विकिरण के संपर्क में आने के बाद कुछ प्रोटीन अगल तरह की वेवलेंथ पर प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। जो यह बताता है कि विशेष माइक्रोस्कोप में इस प्रकाश का विश्लेषण किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि फ्लूअरेसंस माइक्रोस्कोपी के लिए इस प्रोटीन में कई संभावनाएं हैं। फोटो कैमिकल एंड फोटोबायोलॉजिकल साइंस जर्नल में प्रकाशित हुए अध्ययन में बताया गया है कि शोधकर्ता ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से फ्लोरोसेंट प्रोटीन को अन्य प्रोटीनों में जोड़कर माइक्रोस्कोप के जरिये कोशिकाओं में उनके व्यवहार का निरीक्षण किया।

ऐतिहासिक गोलमेज की केक की प्रतिकृति

यूरोपीय देश पोलैंड में 1989 में हुए देश के पहले स्वतंत्र संसदीय चुनाव की 30वीं वर्षगांठ का जश्न एक बेकरी ने अनोखे तरीके से मनाया। ब्यडगोस्जकज शहर में बेकरी की ओर से पोलैंड के ऐतिहासिक गोलमेज की केक से प्रतिकृति तैयार की गई। छह फरवरी से पांच अप्रैल 1989 के बीच राजधानी वारसा में तत्कालीन कम्युनिस्ट शासन और विपक्ष के बीच गोलमेज वार्ता हुई थी। इसी के बाद देश में स्वतंत्र संसदीय चुनाव और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ था। इस तरह चार जून को पहला राउंड और 18 जून को दूसरे राउंड संपन्न हुआ था। रायटर

कोलंबिया में टमाटर युद्ध

यूरोपीय देश स्पेन की तरह दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में भी टोमैटो फाइट फेस्टिवल मनाया जाने लगा है। कोलंबिया के सुतमरचन कस्बे में 10वां टोमैटो फेस्टिवल उत्साहपूर्वक मनाया गया। मस्ती और उल्लास पर केंद्रित इस सालाना फेस्टिवल में हजारों लोगों ने शिरकत की। इस दौरान प्रतिभागियों ने एक-दूसरे पर जमकर टमाटर बरसाए। स्पेन का टोमैटो फेस्टिवल 'ला टोमाटीना' बेहद मशहूर है। यह महोत्सव विदेशी पर्यटक के आकर्षण का केंद्र है और हजारों की संख्या में पर्यटक इसमें हिस्सा लेते हैं। रायटर

स्क्रीन शॉट

अमिताभ बच्चन ने ताजा की अपनी शादी की यादें

गत 3 जून को अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने अपनी शादी की 46वीं वर्षगांठ मनाई। हालांकि इस मौके पर जया अमिताभ के साथ नहीं, बल्कि विदेश में थीं। अमिताभ ने शादी को लेकर एक दिलचस्प किस्सा अपने ब्लॉग पर साझा किया। उन्होंने लिखा, 'तब मैं सेवेंथ रोड पर एक किराए के घर में रहता था। हमने शादी का फैसला कर लिया था। उस समय 'जंजीर' फिल्म सफल हुई थी। दोस्तों के बीच वादा हुआ था कि यदि फिल्म सफल हुई तो दोस्तों का गैंग लंदन छुट्टियों पर जाएगा। हमने अपने माता-पिता से पूछा या यूं कहें कि बताया कि हम अपने सभी दोस्तों के साथ इंग्लैंड जा रहे हैं, तो बाबूजी की तरफ से सवाल आए कि कौन-कौन जा रहा है? जया भी तुम्हारे साथ जा रही है? उन्हें पता चला कि जया भी जा रही हैं, तो उन्होंने कहा -तुम्हें जाना है तो शादी करके जाओ। पंडित और परिवार को सूचना दी गई। अगले दिन सब सेट हो गया था। रात की फ्लाइट थी। फ्लाइट से पहले शादी होनी थी। मैं शादी के लिए भारतीय परिधानों में था। अपनी कार चलाकर मालाबार हिल तक जाना चाहता था, जहां उनके (जया) के दोस्त रहते थे और यह समारोह वहीं होना था। मेरे ड्राइवर नागेश ने मुझे बाहर निकालकर कहा कि शादी की जगह तक वह ड्राइव करके ले जाएंगे। इसे शादी में इस्तेमाल होने वाले घोड़े का विकल्प समझा जा सकता है। मुंबई के जेवीपीडी स्कीम के सेवेंथ रोड पर स्थित किराये के घर 'मंगल' में सब कुछ तैयार था। तभी बूंदाबांदी होने लगी। पड़ोसी मेरे पास आकर बोले- शादी के लिए निकलो, बरसात एक अच्छा शगुन है। मैं निकला, कुछ ही घंटों में शादी हो गई और हम मिस्टर ऐंड मिसेज बन गए।' इसके बाद दोनों लंदन गए। अमिताभ ने लिखा, यह मेरी और जया की पहली लंदन ट्रिप थी।

'हमें तुमसे प्यार कितना' के लिए पहली पसंद नहीं थीं प्रिया बनर्जी!

संजय गुप्ता निर्देशित फिल्म 'जज्बा' में नजर आईं प्रिया बनर्जी अब करणवीर बोहरा के साथ फिल्म 'हमें तुमसे प्यार कितना' में नजर आएंगी। हालांकि वह फिल्म के लिए निर्माताओं की पहली पसंद नहीं थीं। यह रहस्योद्घाटन सोमवार को मुंबई में फिल्म के ट्रेलर लांच के मौके पर करणवीर ने किया। फिल्म के निर्माता उनके पिता महेंद्र बोहरा हैं। करणवीर ने बताया, 'फिल्म की कास्टिंग मुकेश छाबड़ा कर रहे थे। बाकी स्टारकास्ट फाइनल हो गई थी। शूटिंग के लिए मनाली जाने को लेकर सबके टिकट बुक हो गए थे, लेकिन हीरोइन का कुछ अता-पता नहीं था। हमने अनेक अभिनेत्रियों के ऑडिशन लिए थे। हालांकि हमारे पास सबसे पहले हीरोइन के लिए प्रिया की गूगल वाली फोटो भेजी गई थी। उसे देखकर हमने इन्कार कर दिया था। उस समय उनका ऑडिशन भी नहीं हुआ था। मनाली में शूटिंग के सात दिन पहले मुकेश छाबड़ा ने प्रिया का ऑडिशन लेने को कहा। हमने कहा ठीक है। वह हमारे घर आईं। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी। उन्होंने जिस तरह से स्क्रिप्ट पढ़ी, वहां से लगा कि यही हमारी हीरोइन है। मनाली पहुंचने पर हमें एहसास हुआ कि यह तो वही लड़की है, जिसकी फोटो देखकर हमने लेने से इन्कार कर दिया था।' इस रहस्योद्घाटन के बाद उन्होंने साथ में मौजूद प्रिया से गूगल पर मौजूद अपनी पुरानी फोटो हटाने का आग्रह भी किया। प्रिया ने भी कहा कि वह उस फोटो को अवश्य हटा लेंगी। ललित मोहन निर्देशित 'हमें तुमसे प्यार कितना' 28 जून को रिलीज होगी।

अब 2 अगस्त को रिलीज होगी 'जबरिया जोड़ी'

सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा अभिनीत फिल्म 'जबरिया जोड़ी' की रिलीज तारीख आगे खिसक गई है। यह फिल्म बिहार में प्रचलित पकड़वा विवाह पर आधारित है। पहले फिल्म को 12 जुलाई को रिलीज करने की तैयारी थी, लेकिन अब 2 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। एकता कपूर की बालाजी और कर्मा मीडिया इसकी निर्माता कंपनियां हैं। 12 जुलाई को ही रितिक रोशन अभिनीत 'सुपर 30' रिलीज हो रही है। पहले उसे 26 जुलाई को रिलीज होना था। उसी दिन एकता कंगना रनोट अभिनीत 'मेंटल है क्या' रिलीज कर रही हैं। पहले उसे जून में रिलीज होना था। तारीख बदलने पर कंगना की बहन रंगोली और रितिक के बीच सोशल मीडिया पर बहसबाजी भी हुई थी, जिसके बाद रितिक ने निर्माताओं से फिल्म की तारीख बदलने का आग्रह किया था। अब 'सुपर 30' की रिलीज तारीख आगे खिसकाकर 12 जुलाई कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, रितिक रोशन से दोबारा टकराव से बचने के लिए एकता कपूर ने 'जबरिया जोड़ी' की तारीख को आगे बढ़ा दिया है।

राहत काजमी की फिल्म में लीड रोल में दिखेंगी हिना खान

टेलीविजन के बाद बॉलीवुड में पहचान बनाने वाली अभिनेत्री हिना खान को एक के बाद एक फिल्में मिल रही हैं। कान फिल्म महोत्सव में रेड कारपेट पर अपनी अदाओं से लोगों का दिल जीतने के बाद वह अब एक बार फिर डायरेक्टर और अंतरराष्ट्रीय फिल्ममेकर राहत काजमी के साथ दिखाई देंगी। काजमी बड़े एक्टर्स के साथ कई फिल्में कर चुके हैं, अब वह हिना को अपनी फिल्म से लांच कर रहे हैं। कान फिल्मोत्सव के बाद हिना यूरोप में ही रहीं और इस दौरान उन्हें राहत काजमी और उनकी टीम के साथ देखा गया। अंदाजा यह लगाया जा रहा था कि शायद वह अपनी अगली फिल्म के लिए शूटिंग कर रही थीं। राहत काजमी ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा, 'जी हां, हमने हिना खान को अगली तीन फिल्मों के लिए साइन किया है। यूरोप में हम अपनी अगली फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिसमें एक बार फिर हिना खान लीड रोल में दिखाई देंगी।' जब काजमी से हिना को चुनने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, ' हिना जो भी रोल करती हैं, उसमें बहुत गहराई तक चली जाती हैं।'

अध्ययन

सूखाग्रस्त इलाकों के लिए ग्लेशियरों का पानी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज ज्यादातर इलाकों में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमखंड पिघल रहे हैं, जो चिंता का कारण है...

सूखे के दौरान संजीवनी बनेंगे एशिया के ग्लेशियर

- हर साल बर्फबारी के बाद गर्मियों में पिघल जाता है ग्लेशियरों से 1.6 गुना पानी
- शोधकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे बदलावों के प्रति जताई गहरी चिंता

ग्लेशियरों से निकलने वाले पानी पर लगभग 80 करोड़ लोग निर्भर हैं।

लंदन, प्रेट्र : एक अध्ययन में दावा किया गया है कि सूखे के दौरान एशिया के ग्लेशियर प्रमुख नदी बेसिनों में पानी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन जाते हैं, जो लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं। नेचर जर्नल में प्रकाशित हुए शोध के मुताबिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सूखाग्रस्त इलाकों के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं है, लेकिन आज ज्यादातर इलाकों में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमखंड पिघल रहे हैं, जो चिंता का कारण है।

ब्रिटेन के ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे (बीएएस) के ग्लेशियर विज्ञानी हामिश प्रिचर्ड ने कहा कि जब बारिश नहीं होती और पानी के स्रोत भी सूख जाते हैं तो ऐसे में लोगों के लिए ग्लेशियरों का पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, प्रत्येक गर्मी के मौसम में ग्लेशियर 36 क्यूबिक किलोमीटर पानी छोड़ते हैं, जो 1 करोड़ 40 लाख ओलंपिक स्वीमिंग पूल के पानी के बराबर है। यह 2 करोड़ 21 लाख लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

एशिया क्षेत्र में उच्च हिमालयी क्षेत्रों को (जिसमें हिमालय भी शामिल है) तीसरे ध्रुव के रूप में जाना जाता है। यहां कुल 95 हजार ग्लेशियर मौजूद हैं और इनसे निकलने वाले पानी पर लगभग 80 करोड़ लोग आंशिक रूप से निर्भर हैं। हालांकि, यह आपूर्ति जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल प्रभावित हो रही है। हर साल बर्फबारी के बाद ग्लेशियरों का 1.6 गुना पानी पिघल जाता है। शोधकर्ताओं ने औसत वर्षों और सूखे के वर्षों में बारिश की मात्रा के साथ ग्लेशियर योगदान के अनुमानों का विश्लेषण किया। इसके लिए उन्होंने जलवायु के डाटा सेट और हाइड्रोलिक मॉडलिंग का उपयोग कर ग्लेशियर से निकलने वाले पानी की मात्रा और क्षेत्र के प्रमुख नदी बेसिनों का अध्यन किया।

ग्लेशियर विज्ञानी हामिश प्रिचर्ड ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हालात ये हैं कि एशिया के उच्च- हिमालय भी खतरे में हैं।

अध्ययन में पता चला है कि पानी के प्राकृतिक भंडार के रूप में ये समाज के लिए काफी मूल्यवान हैं, जो गर्मियों में नदियों को लंबे समय तक सूखने से रोकता है। उन्होंने बताया कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो सूखे कारण पानी और भोजन की आने वाले समय में कमी हो सकती है। आगामी दशकों में ऐसी संभावना से नकारा नहीं जा सकता। प्रिचर्ड ने कहा कि एशिया के ग्लेशियर पानी की कमी और सूखाग्रस्त आबादी को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।